हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 मार्च, 1980

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 12 मार्च, 1980

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(8)1
तारांकित प्र न संख्या 1582 पर आधे घंटे की चर्चा के लिए मांग	(8)10
तारांकित प्र न एवं उतर (पुनरारम्भ)	(8)10
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उतर	(8)26
भाोक प्रस्ताव	(8)28
ध्यानाकर्शण सूचनाएंः–	
1. हथनी कुंड बैरेज के निर्माण के सम्बन्ध में उतर प्रदे ा तथा हरियाणा के मध्य 1974 का समझौता लागू करने सम्बन्धी	(8)31
2. ओलावृश्टि से फसलों आदि के नश्ट होने सम्बन्धी	(8)32
वक्तव्यः–	
सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा हथनी कुंड बैरेज के निर्माण के सम्बन्ध में उतर प्रदे ा तथा हरियाणा के मध्य 1974 का समझौता लागू करने सम्बन्धी	(8)33
वर्श 1980–81 के बजट पर सामान्य चर्चा	(8)37

हरियाणा विधानसभा सभा

बुधवार 12 मार्च, 1980

विधानसभा की बैठक , हरियाणा सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1 चण्डीगढ में प्रातः 9:00 बजे हुई। (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एंव उत्तर

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब सवाल होगें।

S.S. Teachers

*** 1574. Smt. Dr. Kamla Verma :** Will the chief Minister be pleased to state whether it is a fact that S.S Teacher have been appointed against the posts of science Teacher / Teachersses in the various schools in the State; if so , the reasons therefore?

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती ाान्ति देवी) : जी हां, । इस समय 452 सामाजिक अध्ययन मास्टर्ज / मिस्ट्रैसिज विज्ञान मास्टर्ज / मिस्ट्रैसिज के पदो ंके समक्ष कार्य कर रहे है। विभिन्न कारणों से विभाग के पास अनेक सामाजिक अध्ययन मास्टर्ज / मिस्ट्रैसिज उनकी जरूरत से फालतू है। और उन्हे दूसरों वि ायों

के मास्टर्ज / मिस्ट्रैसिज के पदो ंके विरूद्व असंतुलन के कारण समायोजित करना पडा है। इस असंतुलन के कारण ये है:–

(1) जैसे 1973 की हडताल के दौरान नियुक्त मास्टर्ज / मिस्ट्रैसिज की सेवा में बनाए रखने का निर्णय लेना,

(2) प्राईमरी पाठशालाओं में मास्टर्ज / मिस्ट्रैसिज को नियुक्त करने की नीति को समाप्त करना जिसके फलस्वरूप पदधारियों को दूसरे स्कूलों में समायीजित करना,

(3) 1975 से पूर्व के मास्टर्ज / मिस्ट्रैसिज जो खण्ड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करते थे , के स्थान पर मुख्याध्यापक / मुख्याध्यापिकाओं की खण्ड शिक्षा अधिकारी के पदों पर नियुक्त ,

(4) जे0 बीह0 टी0 / सी0 एण्ड0 बी0 अध्यापकों को उनके लिये आरक्षित 25 प्रतिशत कोआ के समक्ष मास्टर्ज / मिस्ट्रैसिज पदों पर पदोन्नत किया जाना।

श्रीमती डा0 कमला वर्मा :– अध्यक्ष महोदय , मै आपकी मारफत मुख्य संसदीय सचिव महोदस से यह जानना चाहती हुॅ कि इन्होने सामाजिक अध्ययन अध्यापकों को साईंस अध्यापकों / अध्यापिकाओं के पदो ंके विरूद्व लगाये जाने के जो कारण बताएं हे क्या इन कारणों से बच्चों के शिक्षा स्तर पर असर नही पडता घ क्योंकि अगर साईंस अध्यापकों की जगह पर दूसरें अध्यापक पढायेगें तो बच्चे उनसे क्या सीखेगें घ

श्रीमती भाांति देवी :– अध्यक्ष महोदय , किसी हद तक माननीय सदस्या की बात ठीक है । हम इस बात पर पुर्नविचार कर रहे है कि बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए वि यानुसार की अध्यापकों की नियुक्तियां की जांए ओर हम यह काम बहुत जल्द ही करने वाले है।

श्री मांगे राम गुप्ताः– स्पीकर साहब , अभी मुख्य संसदीय सविव महोदया ने अपने लिखित जवाब में पढडा हे कि विभिन्न कारणों से विभाग के पास अनेक सामाजिक अध्ययन मास्टर्ज सरप्लस है और उनके स्थानों पर दूसरे वि ायों के मास्टर्ज ओर मिस्ट्रेज को काम करना पड रहा है। क्या मुख्य संसदीय सचिव बताने की कृप्पा करेगी कि जब एस0 एस0 मास्टर्ज सरप्लस हे और उनकी नई नियुक्तियों पर बैन लगा हुआ है तो उनके लिए ट्रेंनिंग सैन्टर्ज क्यों खोले हए है।

श्रीमती भाांति देवी :– अध्यक्ष महोदय, अभी आनरेबल मैम्बर ने यह पूछा कि जब स्टाफ सरप्लस हे उनके बावजूद भी सरकार ने बी0 एड0 के लिए टेनिंग सेन्टर्ज क्यों खोल रखे है। मै उनको बताना चाहती हुं कि ट्रेंनिेग देने के बाद सरकार उनको नोकरियां देने के लिए उतरदायी नही होती । ट्रैनिंग लेने के बाद व लोग प्राईवेट स्कूलों में सेवा कर सकते है, प्राईवेट टयूशन भी कर सकते हे ओर समय आने पर कभी न कभी उनका नम्बर सरकारी स्कूलों में भी आ सकता है। अब हमने मैथ ओर सांइस सब्जैक्टस के लिए सींटे भी सीमित कर दी हे। इसके साथ साथ

मै मैम्ब्र साहेबान को यह भी बताना चाहती हुं कि ओ0 टी0 की ट्रेनिंग भी इस समय हमारे पास चल रही हैं इसमे दो वि ायों हिन्दी ओर संस्कृत को प्राथमिकता दी जा रही हे। इसका विस्तार हम इसलिए नही कर पा रहे कि कहीं बी0 एड0 वाली समस्या न पैदा हो जाएं।

श्री हीरा नन्द आर्यः– अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य संसदीय सचिव महोदया से यह जानना चाहता हूं कि जब सांईस अध्यापकों की कमी है तो फिर जो एडहौक पर काम कर रह सांईस अध्यापक हे क्या उनका रैगूलर करने का सरकार का कोई विचार है।

श्रीमती भाांति देवी :– अध्यक्ष महोदय, मै आनरेबल मैम्बर की जानकरी के लिए बता देना चाहती हुॅ कि हमने इन सब टीचर्ज को रेगूलर करने का निर्णय पहले ही ले लिया हे।

श्री हीरा नन्द आर्यः– अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य संसदीय सचिव महोदया से यह जानना चाहता हुॅ कि एस0 एस0 मास्टर्ज सरप्लस हे ओर कई स्थान ऐसे है जहां पर एस0 एस0 मास्टर्ज की पोस्टें खाली पडी है। इस के क्या कारण है घ

श्रीमती भाांति देवी :– अध्यक्ष महोदय , वास्तव में आनरेबल मैम्बर साहब की बात ठीक है । सोनीपत रोहतक जिलों में एस0एस0 मास्टर्ज की संस्था ज्यादा है ओर सिरसा ओर हिसार जिलों में एस एस मास्टर्ज की संख्या ंकम है। इसके कारण यह हे कि सरकार की तबादला पालिसी के काण मास्टर्ज वहां पर जाने

के लिए तैयार नही हे। लेकि अब सरकार ने यह निर्णय लिया हे कि जो अध्यापक आर्डर्ज की पालना नही करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

डा0 मंगल जैन :– सभी मुख्य संसदीय सचिव महोदय ने अपने जवाब में कहा कि दो सीानों पर ओ0 टी0 क्लासिज चल रही है। क्या उनके नोटिस में यह बात हे कि ये ो कलासिज इनसफीशिऐण्ट हे ओर इस ट्रेनिग की डिमांड ज्यादा है। अगर नोटिस में है तो कया इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार स तरह के ट्रेनिंग सेन्टर ओर खोलने का विचार रखती है।

श्रीमती भाांति देवी :– अध्यक्ष महोदय , अभी हम इस ओर बिल्कुल प्रयास नही कर रहे ओर न ही ओर ज्यादा व्यक्तियों को टेन्ड करना चाहते है कहीं ऐसा न हो कि टेन्ड व्यक्तियों का एस एस मास्टर्ज की तरह समायोजन करना सरकार के लिए असम्भव हो जाए।

चौधरी हरस्वरूप बूराः– अध्यक्ष महोदय , मै मुख्य संसदीय सचिव महोदया से यह जानना चाहती हु कि जो एस एस मास्टर्ज सरप्लस हे उनको एडजस्ट करने के लिए ओर पोस्टे बढाने का सरकार को कोई विचार हे । ताकि वो नौकरियां दोबारा आ सके।

श्रीमती भाांति देवी :– अध्यक्ष महोदय , मे पहले भी बता चूकी हू कि हमने यह निर्णय ले लिया है ।

चौधरी रामकि ान :– स्पीकर साहब, सोनीपत के साइस टीचर्स और जे0 बी0 टी0 टीचर्ज जीन्द डिस्ट्रक्ट में लगा रखे है। जिसके कारण से जीन्दजिला के टीचर्ज खासकर हमारे सफीदों के टीचर्ज बिल्कुल बेकार बैठे है। क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदया बताने की कृप्पा करेगी कि क्या यह बात सरकार के नोटिस में है और क्या सरकार उनकी जगह पर जीन्द जिला के टीचर्ज को ऐबजार्ब करने का विचार करेगी तरकि जिला जीन्द के लेागों में किसी प्रकार की गल्त भावना न पैदा हो जाएं।

श्रीमती भाांति देवी :– स्पीकर साहब, साईंस टीचर्ज जो होते है वे टेस्ट केडर के होते हे ओर वे किसी भी जिला में सेवा कर सकते हे । जब हमारे पास पोस्ट ही वेकेन्ट नही है तो फिर वे कैसे वहां लगाएं आ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष :– जो टेस्ट केडर के टीचर्ज होते है उनको कही भी लगाया जा सकता हे सोनीपत वाले सफीदों में ओर सफीदों वाले फरीदाबाद में भी लगाएं जा सकते है।

सरदार सुखदेव सिंह :– स्पीकर साहब , अभी मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने कहा कि हिसार ओर सिरसा में मास्टर्ज जाना नही चाहते । क्या इस बात को हल करने के लिए सरकार सिरसा ओर हिसार में इस तरह के कोई ट्रेनिंग सेन्टर्ज खोलने का विचार रखती हे ताकि जो लडके लडकियां वहां पर ट्रेनिंग ले वे

वहीं पर ही पोस्ट कर दिए जाएं जिससे यह समस्या भी हल हो जांएं।

श्रीमती भाांति देवी :– अध्यक्ष महोदय, मै पहले ही मुख्यमन्त्री महोदया से इस बारे में बता कर चूकी हु कि सोनीपत के ज0 बी0 टी0 टीचर्ज जीनद जिले में लगे हुए है और इसी काण से जीन्द के जो टीचर्ज हे उनको नौकरियां नही मिल रही है। डिस्ट्रिक केडर जो होता हे उसको आप डिस्ट्रिक में ही रख सकते है क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदया इसका जवाब देन की कोशिश करेगी कि ऐसा क्यों हुआ ध

श्री भाम ोर सिंह :– अभी श्री राम किशन जी ने जो सवाल किया उसमें कहा गया थ कि सोनीपत के जे0 बी0 टी0 टीचर्ज जीन्द में लगे हुए है । ओर इसी कारण से जीनद मे जो टीचर्ज है उनको नोकरियां नही मिल रही हे । डिस्टिक केउर जो होता हे उसका आप डिस्टिक में ही रख सकते हे। क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदया इसका जबाव देने की कोशिश करेगी कि ऐसा क्यो हुआ ध

श्रीमती भाांति देवी :– अध्यक्ष महोदया , सोनीपत में अध्यापक पद रिक्त होने के काण जिला जीनद मे भेजे दिए गऐ थे जैसे जैसे हमारे पास अध्यापकों के पद रिक्त हो ते जा रहे है हम उनको वापस बुला रहे है। जैस ही ओर पद रिकत हो जाएगें हम उनको लै के लिए तैयार है।

श्री भाम ोर सिंह :– अध्यक्ष महोदया , सी0 पी0 एस0 महोदया ने माना हे कि सोनपत जिले के जे0 बी0 टी0 टीचर्ज जीन्द जिले में लगे हुए है। क्या यह कायदे कानून के खिलाफ नही है और क्या इसको जल्दी रैक्टीफाई किया जाएगा घ

श्रीमती भाांति देवी :– जो टीचर्ज लगे हुए है वे कायदे कानू के खिलाफ नही लगे हुए है ।

मास्टर ि ाव प्रसाद :– स्पीकर साहब, इन्होने जबाव के पैरा दो ओर तीन में लिखा है:–

प्राईमरी पाठशालाओं में मास्टर्ज / मिस्ट्रेसिज को नियुक्त करने की नीति को समाप्त करना जिसक फलस्वरूप पदाधिकारियों को दूसरे स्कलों में समायोजित करना,

1975 से पूर्व के मास्टर्ज / मिस्ट्रेसिज जो खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करते थे के स्थान पर मुययाध्यापक / मुख्याध्यापिकाओं की खंड शिक्षा अधिकारी के पदो पर नियुक्त,

उससे पहले भी स्कूलो में सामाजिक अध्ययन टीचर साईंस की जगह पढा रहे ि तो क्या यह हरियाणा के बच्चे के साथ अन्याय नही हो रहा है।

श्री अध्यक्ष :– इस सवाल का जवाब पहले ही आ चूका हे।

डा0 मंगल सैन :– सपीकर साहब इन्होने कहा कि सोनीपत ओर रोहतक जिलो में सामाजिक अध्ययन क? अध्यापक ज्यादा है और स्थानान्तरण नीति दो ापूर्ण होने की वजह से हिसार ओर सिरसा जिलो में जाने से अध्यापक संकोच क्यों करते है।

श्रीमती ाान्ति देवी :– स्पीकर साहब, मैने दो ापूर्ण ाब्द नही कहा था । मेरा ख्याल है डा0 साहब ने उस वक्त ध्यान नही दिया।

श्री अध्यक्ष :– डा0 साहब यह जानना चाहते है कि टीचर्ज हिसार और सिरसा में जाने के लिए संकोच क्यों नही करते है।

श्रीमती ाांति देवी :– हमारी स्थानन्तरण पालिसी यह है कि हम टीचर्ज को उसके जिले में निकट से निकट लगाना चाहते है । इसलिए टीचर्ज हिसार और सिरसा में नही जाते ।

श्रीमती डा0 कमला वर्मा :– अध्यक्ष महोय, पिछले दो व ा्र के अन्दर 191 स्कूल तो प्राथमिक अपग्रेड हुए और 158 माध्यमिक अपग्रेड हुए। मै यह जानना चाहती हू कि इतने स्कूल अपग्रेड होने के बावजूद भी सामाजिक अध्ययन के टीचर्ज सरप्लस क्यों रहे । कहीं ऐसा तो नही कि साईंस टीचर्ज को वचित रख कर इन्होने और सामाजिक अध्ययन टीचर्ज नए रख लिए है।

श्रीतमी ाान्ति देवी :– इन्होने कहा कि इतने स्कूल अपग्रेड हुए स्पीकर साहब, इसमे कोई दो राय नही है हमारे ास कुल दो हजार एस0एस0 मास्टर्ज सरप्लस थे जिनमें स ेअब 900 बाकी हैं

श्री अध्यक्ष :– यह तो यह जानना चाहती है कि सरप्लस होने के बावजूद एस0एस0 मास्टर्ज और तो एम्पलाय नही किए।

श्रीमती ाान्ति देवी :– जी नही , ओर एम्पलाय करने पर तो बैन है।

Mr. Speaker : I must congratulate the Chief Parliamentary Secretary for giving very clear cut replies.

Rural Industrialisation Scheme

***1582 Shri Mool Chand Jain :** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the number of industrial units in the State brought under the rural industrialistion scheme during :-

(i) 1-7-77 to 30-06-79 ; and

(ii) 1-07-79 to 31-01-80 ;

(b) the amount of financial assistance given by the State Government, Banks and other financial institutions to the units mentioned in part (a) above ; and

(c) the main hurdles in the successful implementation of this scheme and the steps taken to remove those hurdles ?

श्रीमती ाान्ति देवी :– जी नही , ओर ए

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क) ग्राम उघोग योजना राज्य में मास सितम्बर , 1977 से लागू की गई थी मास सितम्बर 1977 से 30– 06–79 से 31–1–80 तक कमशः 902 तथा 1277 ईकाईयां इस स्कीम के अन्तर्गत स्थापित की गई थी।

(ख) विवरणी अनुबन्ध –1 सदन के पअल पर प्रस्तुत है ।

(ग) विवरणी अनुबन्ध –11 सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

अनुबन्ध 1

क्रमांक	वितीय संस्था	सितम्बर, 1977 से 30–6–79	1–7–79 से 31–1–80	जोड़
1	बैंक	16639928	8688907	25328825

2	राज्य सरकार	434100	135550	569650
3	हरियाणा वित निगम	66000	4660000	432000
4	अन्य वितीय संस्थाएं (खादी एवं विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड)	113250	54750	168000
	कुल जोड़	**17253278**	**9245207**	**26498485**

अनुबन्ध II

इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने में कुछ मुख्य कठिनाईयां इस प्रकार है ।

1. विभिन्न जतियों ओर वर्गो के व्यक्तियों में सांझेदाी की अनिवार्य ार्त,
2. कही–कहीं बैकों द्वारा इन इकाईयों को ऋण देने में कठिनाईयां
3. कच्चे माल व बिजली की कमी : और
4. बिकी की समस्या आदि

राज्य सरकार के तदानुसार सिद्वान्त रूप में सांझेदारी की ार्त को समाप्त करने का निर्णय लिया है। बैकों के अतिरिक्त हरियाणा वित्त निगम ने भी ग्रामीण उधमकर्ताओं को ऋण देना आरम्भ कर दिया हे। राज्य सरकार , बिजली की कमी को दूर करने के लिए यथासम्भव प्रयत्न कर रही है। कच्चे माल की उचित मात्रा की उपलब्धी के लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर जोर डाल रही है। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य लघु उधोग एंव निर्यात निगम ने ग्रामीण ईकाईयों द्वारा तैयार ुदा माल की बिक्री के लिए राज्य में 8 बिक्री केन्द्र भी खोले हैं।

श्री मूल चन्द जेन :– स्पीकर साहब, मै मुख्य मंत्री जी से जानना चाहती हू कि अनैश्कच एक के कालम में 6 में कैश सबसिडी असिस्टैस की राशी दिखाई गई है मै यह जानना चाहता हू क जो पांचवा कालम है उसमे भी कोई सबसिडी की राशी है या नही घ

चौधरी भजन लाल :– स्पीकर साहब, स्टेटमैन्ट ं सारे आकडें दिए गए हे जो कि देहात में उधोग धन्धे लगाए जाते है उन पर हम 15 प्रतिशत सबस्डी देते है।

श्री मूल चन्द जैनः– स्पीकर साहब मै तो दूसरी आइटम्ज के बारे में कलैरिफिकेशन चाहता हू कि क्या उनमें भी कोई सबस्डी दी गई है या नही घ

चौधरी भजन लाल :– दूसरे कालम मे जो राशी दिखाई गई है । उसे हम लोन की ाक्ल में देते है लेकिन उस पर सूद 4 प्रतिशत लिया जाता है ।

श्री मूल चन्द मंगला :– स्पीकर साहब, देहातों देहातों मे जो इन्डस्टीज लगाई गई थी उनके लिए यह कहा गया थरा कि सेल्ज टैक्स और चुगी फ्री होगी। लेकिन लोगों ने मुख्य मन्त्री को शिकायत की है कि हमे सेल्ज टैक्स देना पडता है। ाोर और उन्होनै मेमोरेडम भी दिया है क्या मुख्य मंत्रीी महोदय बताने की कृप्पा करेगें कि ऐसा क्यों हैघ

चौधरी भजन लाल :– देहांत में जो चूंगी लगाने का काम ही नही हैै अगर किसी ने ाहरों में उदयोग लगा रखे है तो उन पर तो चुगी लगेगी । मै माननीय सदस्य को बता दू कि अगर कोई देहांत में अपना माल तैयार करके ाहर में बचने के लिए ले जाता है तो उसको भी पांच साल के लिए रियायत दे रखी है।

चौधरी गया लालः– स्पीकर साहब मै मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हु कि तहसील पलवल में जो ग्रामीण केन्द्र लगाए गए है उनमें से कितने चल रहे हे और कितने बंन्द है ओर जो बंद है उनका क्या कारण है।

श्री अध्यक्ष :– इसके लिए तो सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री गुलजार सिंह :– स्पीकर साहब मै मुख्यमत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हु कि देहातों मे जो छोटइी इंस्टटीज

लगाई गइग है उनमें से कई इंडस्टीज जो सामान बनाती हे उनको वह बेचने में बहुत परेशानी होती है तो क्या सरकार उनका सामान बिकवाने में कोई सहायता करेगी।

चौधरी भजन लाल :– अध्यक्ष महोदय उस सामान की मार्किगं के लिए हमने 8 जिलों में केन्द्र बनाए गए है। इसके अलावा फाईनैशियल कार्पोरेशन भी परचेज करती है इस कार्पोरेशन ने 38 लाख रूप्ए का माल परचेज किया है । गया लाल जी ने पलवल के बारे मे ंपूछा मेरे पास पलवल के आकडे तो नही लेकिन जिला बार आंकडे हे गुडगावा जिले में हमने 146 उदयोग लगाए है।

चौधरी राम लाल वधवा :– स्पीकर साहब जवाब मे अनैकश्चर दा पर इस योजना की सकसेसफल इम्पलमैटेशन के बारे में कुछ डिफीकल्टीज बताई गई है। इसमे पहली यह डिफिकल्टीज बताई गई हे। कि जो कम्पलशरी पार्टनरशिप की कंडीशन लगाई गई थी उसे इम्पलीमैंट करना मुश्किल है मै मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हू कि ऐसार न करके तो रूरल इंडस्टीलाईजेशन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उसमे एक हरिजन लाजमी लेना चाहिए अगर यह चीज उडा दी जाती है तो क्या वे लोग इस फायदे से वंचित नही हो जाएगे।

चौधरी भजन लालः– अध्यक्ष महोदय, इस पालिसी को इसलिए चेज करना पडा कि आपको पता हे कि सांझेदारी तो आज

सेग भाईयों की भी नही चलती है मै माननीय सदस्य को बताना चाहता हु कि इडिविजुयली पिछले दो सालों में 498 अनुसूचित जाति के लोगों ने उदयोग लगाए ओर अब पिछले सात महीनों में 526 हरिजनों ने उदयोग लगाए हे।

श्री टेक रामः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने इन योजनाओं में देहातों के लिए प्रोत्साहन दिया था, लेकिन यह सरकार बड़े भाहरों को प्रोत्साहन दे रही है, इसका क्या कारण है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम तो देहातियों को प्रोत्साहन देने के लिए हैं जो देहातों में उद्योग धन्धे लगायेंगे, इससे उनको सहूलियतें मिलेंगी।

सरदार सुखदेव सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मोम का और कागज का कोटा गल्त तरीके से अलाट किया गया था और इस रूरल इंडस्ट्रीयलाइजे ान की आड़ में उस समय की जनता सरकार के मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री ने जो ..... की थी, क्या उसकी मुख्य मंत्री जी जांच करवा कर दोश्यी आदमियों को सजा देंगे ?

Dr. Mangal Sein: Sir, I highly object to these words.

श्री अध्यक्षः यह हेराफेरी भाब्द एक्सपंज किया जाए।

Dr. Mangal Sein: Supplementary, Sir..... (Interruptions.)

Mr. Speaker: Ch. Bhajan Lal Ji..... (Interruptions.)

Dr. Mangal Sein: Speaker Sahib, have you decided not to vie me any time on this question?

Mr. Speaker: I have tried to give you the maximum time. (Interruptions).

Dr. Mangal Sein: Not on this question, Sir..... (Interruptions)

Mr. Speaker: Every member cannot get opportunity on every question.

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे पास ऐसी कोई ि ाकायत आई कि फलां आदमी ने फैक्ट्री लगाई नहीं और उसको मोम का या कागज का कोटा दिया गया है तो हम इसकी पूरी जांच करवायेंगे और जो आदमी दोशी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक ान लिया जाएगा और उसका कोटा भी कैन्सिल कर दिया जाएगा।

श्री मूल चन्द जैनः अध्यक्ष महोदय, इनको इन यूनिट्स की कामयाबी में जो मु ि कलात हैं, उसमें एक यह मु ि कल पाई गई है कि रा–मैटीरियल और बिजली की कमी है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप बड़े कारखानों से कटौती करके इन छोटे यूनिट्स को रा–मैटीरियल देंगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, रा–मैटीरियल की और बिजली की कमी की दिक्कत सारे दे ा में है फिर भी हम कोि ा ा कर रहे हैं कि देहातों में जो छोटे उद्योग धन्धे हैं, उनको जरूर प्रोत्साहन दिया जाए।

तारांकित प्र न संख्या 1582 पर आधे घंटे की चर्चा के लिए मांग

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। सरकार ने इसका बिल्कुल सैटिसफैक्ट्री जवाब नहीं दिया है। इसलिये इस सवाल पर आधे घंटे की डिस्क ान अलाऊ की जाए। इन्होंने सारी पालिसी चेंज कर दी और इस स्कीम का मकसद ही खत्म कर दिया है। (ाोर)

Mr. Speaker: Please give me in writing and I will consider it.

तारांकित प्र न एवं उतर (पुनरारम्भ)

Hafed Woollen Mill at Loharu

***1467. Sh. Hira Nand Arya:** Will the Minister for Co-operation & Planning be pleased to state whether it is a fact that the Haryana a plan to set up a Woollen Mill at Loharu; if so, the time by which it is likely to be set up?

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह):

1. हां।

2. परियोजनाओं की आर्थिक सम्भावनाओं की जांच की जा रही है और वर्तमान स्थिति में समय की कोई निि चत सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हरियाणा राज्य सहकारी विपणन एंव वितरण प्रसंघ लि. लोहारू में ऊन की कताई मिल लगाने की योजना पर विचार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, उस इलाके में ऊन काफी मात्राा में उपलब्ध है और स्टेट की इन्कम के लिहाज से यह पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह विचार कब से किया जा रहा है और इस पर कब तक विचार कर लिया जाएगा?

ठाकुर बीर सिंह: अध्यक्ष महोदय 2–6–1976 को एक मैमोरेन्डम लोहारू के आदमियों की तरफ से पिछले मुख्यमंत्री चौ. देवी लाल जी के सामने पेश हुआ था। उस वक्त से सरकार ने इसकी जांच करवानी शुरू की। आल इंडिया स्पीनिंग मिल्ज फैडरेशन के जरिये इसकी जांच करवाई गई है। 1200 स्पीन्डल के मिल लगाने की जहां योजना बनाई गई थी, जांच करवाने पर मालूम हुआ कि उस परियोजना में 2438 लाख किलो ग्राम ऊन चाहिए जबकि स्टेट में कुछ ऊन की पैदावार 8 लाख किलोग्राम

थी। इसी वजह से फैडरेशन ने यह सिफारिश की कि यह यूनिट वायएबल नहीं होगा। अध्यक्ष महोयद, सदन की जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि हमने दोबारा इस क्वैशचन को रैफर किया है। इसके साथ–साथ एक कार्डिगन प्लांट भी हम लगाना चाहते हैं क्योंकि सारे नारदर्न इंडिया में ऐसा कोई और प्लांट नहीं है ताकि इसकी वायएबल यूनिट बनाया जा सके। मेरा ख्याल है कि इस हफ्ते के अन्दर ही जो मामला हमने रैफर किया हुआ है उसके बारे में जवाब आ जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि चौ. देवी लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसको शीघ्र लगाने की घोशणा की थी?

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, मंत्री जी ने बड़ा ही साफ जवाब दे दिया है और इसका इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Fair Price Shops in the State

***1485. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state –

(a) the district-wise total number of Fair Price Shops in the State as on 31-3-77, 31-3-78, 31-3-79 and 31-1-80 separately;

(b) the details of commodities supplied to public through the Fair Price Shops in the State

during teh period as referred to in part (a) above, separately;

(c) the sale price of wheat, wheat atta, sugar, rice and vegetable ghee per Kg. at Fair Price Shops as referred to in part (a) above, separately; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to open more Fair Price Shops in the States, if so, the district-wise number thereof?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौ. गजराज बहादुर नागर): वांछित सूचना सदन की मेज पर रखी जाती है।

(क) हरियाणा राज्य में उचित मूल्य की दुकानों की स्थिति निम्न प्रकार हैः—

सर्कल का नाम	31.3.77	31.3.78	31.3.79	31.1.80
अम्बाला	423	462	463	449
भिवानी	430	395	370	361
फरीदाबाद	यह जिला दिनांक 16.8.79 से बनाया गया हैं।			356
गुडगांव	615	652	646	313

हिसार	569	436	238	438
जींद	272	320	254	322
करनाल	400	449	438	438
कुरूक्षेत्र	200	195	184	180
कैथल	173	173	184	167
नारनौल	396	380	320	304
रोहतक	421	472	438	405
सिरसा	225	276	266	278
सोनीपत	294	306	254	274
कुल जोड़	4418	4486	4255	4285

(ख) खाद्यान वितरण की स्थिति निम्न प्रकार है:–

	31.3.77	31.3.78	31.3.79	31.3.80
	29936 टन	63096 टन	18299 टन	14000 टन
चावल	6771 टन	8185 टन	6416 टन	787 टन

चीनी	47374.8 टन	52325.6 टन	24708.9 टन	6728 टन मास 12/79 व 1/80 के लिए

(ग) उचित मूल्य की दुकानों पर वितरण किये गये गेहूं, गेहूं आटा, चीनी चावल तथा वनस्पति घी की कीमतों का विवरण निम्न प्रकार है:–

	31.3.77	31.3.78	31.3.79	31.3.80
	प्रति किलो	प्रति किलो	प्रति किलो	प्रति किलो
गेहूं	1.32	1.32	1.37	1.37
चावल परमल	1.94	1.94	2.04	2.04
चावल बेगमी	1.69	1.73	1.89	1.89
चावल बासमती साधारण	2.05	2.05	2.16	2.16
चावल बासमती बढ़िया	2.57	2.57	2.57	2.57

चीनी	2.15	2.15	नो कन्ट्रोल	2.85

गेहूं, आटा तथा वनस्पति घी पर नियंत्रण नहीं है तथा यह उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम द्वारा वितरण नहीं किया जाता।

(घ) उपभोक्ताओं की आवश्यकता तथा मांग अनुसार उचित मूल्यों की दुकानों की स्थापना की गई हैं इसके अतिरिक्त आवश्यक हिदायतें पहले ही जारी की हुई हैं कि जहां कहीं आवश्यकता/मांग हो, वहां पर उचित मूल्यों की दुकानें स्थापित कर दी जाएं व किसी भी क्षेत्र के लिये कोई संख्या (उचित मूल्यों की दुकानें) निर्धारित नहीं की गई हैं।

चौ. राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो यह सर्कल्ज बताये हैं इन सर्कल्ज में शहरों में कितनी दुकाने हैं और देहातों में कितनी हैं?

Mr. Speaker: I think this requires a separate notice. अगर फिर भी मंत्री जी सूचना देना चाहते हैं तो बता दें।

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, कुल दुकानें 4285 जिनमें से 939 अर्बन एरियाज में हैं और 3346 रूरल एरियाज में हैं।

डा. बृज मोहन गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 31.3.1977 को 4418 दुकानें थीं और 31.1. 1980 को घट कर 4285 रह गई तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनके घटने का क्या कारण है?

चौ. गजराज बहादुर नागर: अध्यक्ष महोदय, इनके घटने का कारण यह है कि चीनी का डी–कंट्रोल हो गया था इसलिये बहुत सारी दुकानें बन्द हो गई थीं। अब दोबारा चालू हुई हैं और आगे जहां से भी किसी की मांग आती है और डिपार्टमेंट समझता है कि वहां दुकान खोलना जरूरी है तो वहां पर हम दुकान खोलने के लिये एक्शन लेते हैं।

चौ. गंगा राम: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, इनको महकमा चलाता है या प्राईवेट आदमी भी चलाते हैं, यदि प्राईवेट आदमी चलाते हैं तो क्या देहातों में जो रिटार्यड फौजी आदमी हैं, उनको इन दुकानों को चलाने के लिय प्राथमिकता दी जाएगी?

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, सबसे पहले तो हरिजनों की कोआप्रेटिव सोसायटियों को प्रैफ्रेंस देते हैं उसके बाद कोआप्रेटिव सोसायटीज को फिर कंज्यूमर स्टोर हैं यदि वे कोई अपनी ब्रांच खोलना चाहें तो उनको देते हैं उसके बाद एक्स–सर्विसमैन को और उसके बाद इनडिवीजुअल हरिजन को

तथा उसके बाद अगर कोई और आदमी खोलना चाहे तो उसको प्रैफ्रेन्स देते हैं।

चौ. गंगा राम: क्या मंत्री महोदय कोई एक मिसाल दे सकते हैं कि हरियाणा में कोर्ठ एक्स–सर्विसमैन फेयर प्राईस शॉप चला रहा है?

चौ. गजराज बहादुर नागर: इसके लिये सैप्रेट नोटिस दीजिए।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, फेयर प्राईस शॉप्स में वनस्पति घी, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल तथा और कई चीजें इस समय उपलब्ध नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय, फेयर प्राइस शॉप्स में ये चीजें उपलब्ध कराने के लिये कदम उठायेंगे।

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मैंने अपने जवाब में दो आइटम्ज के बारे में साफ तौर पर लिखा है और वे आइटम्ज हैं वैजिटेबल घी और आटा। ये दोनों आइटम्ज ओपन मार्किट में बिक रही हैं।

चौ. राजेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने हल्के के कई हरिजनों को मन्त्री महोदय के पास फेयर प्राईस भॉप्स खोलने के सिलसिलें में बातचीत करने के लिये भेजा था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में किसी हरिजन को फेयर प्राइस शॉप खोलने के लिये इजाजत दी है?

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मेरे पास कोई हरिजन नहीं आया।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं जरा क्लीयर कर देता हूं। डा. मंगल सैन ने जो सवाल पूछा है, उसके बारे में अर्ज यह है कि सरकार ने फैसला किया है कि जो चीजें फेयर प्राइस शॉप्स में नहीं मिलतीं या जिनकी प्राइस ज्यादा है, गरीब आदमी के लिये खरीदना मुश्किल है, इनके लिये उन गांवों में जिनकी आबादी दो हजार से ज्यादा है, वहां पर कोआप्रेटिव कंज्यूमर्ज स्टोर्ज खोल रहे हैं। चाहे घी का ताल्लुक है, चाहे दूसरी चीजों का ताल्लुक है, ये सारी चीजें गरीबों को मुहैया करने की चेश्टा कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि दो हजार की आबादी वाला कोई गांव न रहे जिसमें कोआप्रेटिव कंज्यूमर्ज स्टोर न हो।

चौ. राजेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन्होंने किसी हरिजन को फेयर प्राइस शॉप्स खोलने की इजाजत दी है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय ने बताया है कि एक्स–सर्विस–मैंन और हरिजनों का प्रैफरेंस दी जाएगी। वैसे इसके लिये सैप्रेट नोटिस चाहिए। लेकिन मैं गवर्नमेंट को यही रिकमैंड करूंगा कि एक्स–सर्विस–मैंन को फेयर प्राइस शॉप्स देने में प्रैफरेंस देनी चाहिए।

चौ. भजन लाल: अगर किसी जगह पर कोआप्रेटिव कंज्यूमर स्टोर नहीं हुआ तो वहां एक्स–सर्विस–मैंन और हरिजनों को डीपो देने में सबसे पहले प्रैफ्रेंस दी जाएगी।

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, फेयर प्राइस शॉप्स में कई किस्म की गड़बड़ होती है। क्या मंत्री जी इस गड़बड़ को रोकने के लिये पंचायत को अधिकार देंगे ताकि पंचायत का उन पर कंट्रोल रहे और पंचायत समय–समय पर चैक कर सके?

चौ. गजराज बहादुर नागर: फेयर प्राईस शॉप्स के थ्रू जो डिस्ट्रिब्यूशन होती है, उसको वहां के पांच आदमी सुपरवाईज करते हैं – सरपंच, हरिजन पंच, हैडमास्टर, पटवारी और ग्राम सचिव। ये पांच आदमी उसको बंटवाते हैं और रजिस्टर पर उनके दस्तखत होते हैं। इसके इलावा मेरे अपने डिपार्टमैंट का इन्सपैक्टर भी गाहेबगाहे सुपरवाईजन करता रहता है। अगर किसी के खिलाफ कोर्ठ कम्पलेंट हो, तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि जिन गांवों की आबादी दो हजार से ज्यादा है, वहां पर दुकानें खोलेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में कितने गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी दो हजार से ज्यदा है?

श्री अध्यक्ष: इसके लिये सैप्रेट नोटिस दें।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, फेयर प्राइस शॉप्स खोलने का ताल्लुक सिर्फ दो हजार की आबादी वाले गांवों से तो

है ही, इसके अलावा भी जहां से शॉप खोलने के लिये मांग आयेगी, हम वहां खोलेंगे लेकिन वहां पर कोआप्रेटिव कंज्यूमर्ज स्टोर नहीं होना चाहिए।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आज एक आदमी को राशन कार्ड पर कितनी चीनी मिलती है? जितनी चीनी आज एक आदमी को मिल रही है, क्या सरकार की कोई ऐसी पालिसी हे जिसके तहत इस कोटे को और बढ़ाया जाए? मेरे कहने का मतलब है कि क्या कोटे को इन्क्रीज करने की बात सरकार के विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष: इसके लिये सैप्रेट नोटिस चाहिए, अगर मिनिस्टर साहब जवाब देना चाहें तो दे दें।

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, हम 400 ग्राम पर–हैड चीनी देते हैं अेर यह कोटा ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार से हम कहते रहते हैं कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: इनका कहना है कि दिल्ली में 600 ग्राम चीनी पर–हैड मिलती है लेकिन हरियाणा में 400 ग्राम मिलती है। क्या सरकार कोटा बढ़ाने की कोशिश करेगी?

चौ. गजराज बहादुर नागर: कोटा बढ़ाने के लिये सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है।

चौ. देस राज: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि फेयर प्राइस शॉप्स पर मिट्टी का तेल मुहैया करवाने की कृपा करेंगे ताकि गांव वालों को जो कठिनाई हो रही है, उससे छुटकारा मिल सके?

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, जहां से मिट्टी के तेल की मांग आती है हम फौरन वहां भिजवा देते हैं।

श्री अध्यक्ष: इसका मतलब यह हुआ कि फेयर प्राइस शॉप्स में मिट्टी का तेल मिलता है।

चौ. हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, राशन की दुकानों पर 1970 की मर्दमशुमारी के आधार पर चीनी आती है जबकि आज आबादी बहुत बढ़ गई है और यह कोटा अब मर्दमशमारी के आधार पर आना चाहिए, क्या मंत्री महोदय इस बात पर गौर करेंगे?

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, मैंने दो रोज पहले कहा था कि हम दोबारा राशन कार्ड बनाने जा रहे हैं। इस वक्त चीनी पुराने राशन कार्डो पर बांटी जा रही है क्योंकि चीनी का कंट्रोल जनवरी से शुरू हुआ है।

श्रीम उप–मंत्री (चौ. लाल सिंह): स्पीकर साहब, ये पहले अपने वोटरों को कहे कि जिसका राशन कार्ड नहीं बना है, वह जल्दी बना लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं समयझता हूं, जो प्वायंट श्री हुक्म सिंह ने रेज किया है यह बड़ा इम्पौर्टैन्ट है। अगर एक कुनबे में 10 आदमी हैं, इनमें से केवल 5 के नाम पर राशन कार्ड बना हुआ है तो मैं गवर्नमैंट से रिकमैन्ड करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी राशन कार्डो को दरूस्त करवायें। I hope, the Govt. will keep this aspct in view.

चौ. गजराज बहादुर नागर: जिस घर में 10 आदमी हैं, इनमें से 5 के राशन कार्ड बने हुए हैं और जो 5 आदमी बाकी रहे हैं, उनका राशन कार्ड बनाने के लिये हमने उनको मना नहीं कर रखा है, कोर्ठ रोक नहीं है। जो आदमी राशन कार्ड बनाने के लिये गवर्नमैंट को ऐप्रोच करता है हम उसका राशन कार्ड बना देते हैं। सारी स्टेट में राशन कार्ड बनाने का जहां तक सवाल है, इसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार दोबारा राशन कार्ड बनाने जा रही है।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो चीनी भारत सरकार हमें अलाट करती है, उसको आबादी के लिहाज से हम आगे बांटते हैं। जैसे 60 हजार टन चीनी को कोटा भारत सरकार से आता है। महीने के हिसाब से हम इस कोटे को प्रदेश की आबादी के हिसाब से तकसीम कर देते हैं। आबादी के हिसाब से जो राशन कार्ड बनते हैं उनके मुताबिक 400 ग्राम पर–हैड के हिसाब से चीनी मिलती है। 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से नये

राशन कार्ड बनाने जा रहे हैं और भारत सरकार से अब जे चीनी मिलेगी उसको इन्हीं राशन कार्डों के हिसाब से तकसीम करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1496

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य कैप्टल मांगे राम, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Recognition to the Shiksha Shastries

***1480. Swami Aditya Vesh**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to recognise Shiksha Shastries as equivalent to O.T. Shastries in the State; and

(b) if so, the time by which such recognition is likely to be given?

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती शान्ति देवी): (क) तथा (ख) जी हां, निर्णय शीघ्र लिया जायेगा।

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, सकारात्मक उत्तर देने के लिये तो मैं मुख्य संसदीय सचिव महोदया को बधाई देता हूं लेकिन जानना यह चाहता हू कि यह कब तक मान्यता दे देंगे?

श्रीमती शान्ति देवी: प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो जाए।

Representation/Memorandum from the School Cadre Lecturers

***1543. Dr. Mangal Sein**: Will the Chief Minister be pleased to state wehther any representation/memorandum has recently been received from the School Cadre Lecturers for their pay-scales in the State; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House together with the action taken thereon?

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती शान्ति देवी): जी हां। उनके ज्ञापन की प्रति पटल पर रखी जाती है तथा इस बारें में जांच की जा रही है।

MEMORANDUM

Haryana School Lecturers Association

Ref. No. HSLA/80-81/1384-89 Dated 22-2-80

The Haryana Scholl Lecturer's Association expresses its sense of gratitude to teh Haryana Govt. for granting Rs. 700/1600 pay scale to the school Lecturers and thus maintaining parity with the high school, headmasters.

By granting the pay scales on the basis of division in M.A./M.Sc. the Govt. has, however, overlooked the fact that about one third of the school lecturers cadre has been hit hard since a wide gap has crept in within the cadre itself. To serve the ends of justice, it should be bridged up by granting a uniform pay scale of Rs. 700/1600 irrespective of the division in M.A./M.Sc. keeping in view the following facts:-

1. That the Public Service Commission prepares Joint Merit lists of M.A./M.Sc.;s I, II & III class school lecturers and the department frames seniority strictly on the basis of merit determined by the commissiion irrespective of the division in M.A./M.Sc. As the distinction based on division is quite irrational, it should go.

2. That about one third of the school lecturers are third class M.A./M.Sc.'s and almost all of them are B.T./B.Ed's. To deny the III class shcoll lecturers the pay scale of Rs. 700/1600 while headmasters with B.A.B.T./B.Ed. qualifications and no criterion of division in B.A.B.T./B.Ed. stand placed in the pay scale of Rs. 700/1600 is tantamount to a sheer injustice to the former which shouls be given a serious thought of by the Government.

3. That when compared with all other categories of Govt. staff in general and teaching personnel in particular, the granting of pay scales on the basis of division is unprecedented and illogical. to stick to a past practice simply because it was there need not to be adhered to and be discarded as done in the case of our counterparts in Punjab and Himachal Pradesh.

4. That if there is any one category to be most adversely affected in both the pre-revised and revised pay scale, it is in the lot of third division school Lecturers who constitute about one third of the cadre who were, are and will stagnate at the maximum of their pre-revised and revised pay scales for years together and in some cases till retirement if the much needed relief in the shape of regular annual increment is denied to them because of the basic flaw in the revised pay scales applicable to them which needs to be improved upon by granting the uniform pay scales of Rs. 700/1600.

It is earnestly hoped that the Haryana Government's gesture would not be wanting to ensure justice to the long neglected schools lecturers.

Sd/-

H.S. UPPAL, President

H.S.L.A. H.O. Govt. Hr. Sec. S.,

Hissar.

डा. मंगल सैन: क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदया बतायेंगी कि आपने जिस ज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रखी है उसे ये किन–किन पहलुओं ऐ ऐग्जामिन कर रही हैं?

श्रीमती शान्ति देवी: स्पीकर साहब, प्रधान, हरियाणा स्कूल लैक्चरार्ज ऐसोसिएशन की तरफ से हमें नवीनतम वेतनमानों के बारे में दिनांक 22.2.80 को प्राप्त हुआ था। क्योंकि एम.ए. ओर

एम.एस.सी. फर्स्ट डिविजन और सैकिंड डिविजन तथा एम.ए. ओर एम.एस.सी. थर्ड डिवीजन के वेतनमानों में कुछ अन्तर है, इसलिये वह मामला सरकार के विचारधीन है। हम इसको बारीकी से ऐग्जामिन करवा रहे है।

श्री रण सिंह मान: क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहिबा के नोटिस में यह बात है कि जो स्कूल टीचर्ज सिक्स मंथस बेसिज पर काम कर रहे हैं वे अगर नए वेतनमान लागू होने पर दोबारा सिक्स मंथन बेसिज पर अप्वायंट होंगे तो उनकी तनख्वाह कम हो जाएगी?

श्रीमती शान्ति देवी: इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। (विघ्न)

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, बहिन जी ने अभी कहा कि बारीकी से जांच की जा रही है। क्या वे बताएंगी कि वह बारीकी से जांच कब तक पूरी हो जाएगी?

श्रीमती शान्ति देवी: शीघ्रतिशीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे।

Allotment of Ministers Bungalows to Officers

***1508. *Ch. Satvir Singh, Ch. Jagdish Kumar Beniwal**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the I.A.S./H.C.S. Officers are living in the Ministers Bungalows in Sector 7-A, at present; and

(b) if so, whether the officers referred to in part (a) above are entitled to reside in those Bungalows?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) और (ख) कोई आई.ए.एस. अथवा एच.सी.एस. अधिकारी इन कोठियों में नहीं रह रहा तथापि इनमें से कुछ कोठियां राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों को अलाट की गई हैं। सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृश्टिगत ऐसी अलाटमैंट करने में सक्षम है।

चौ. सतवीर सिह मलिक: क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि वे सर्विस रूल्ज के मुताबिक इन हाउसिज के लिये एनटाइटल्ड हैं? (विघ्न)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह प्रथा इन्ही के राज में डली है। हम तो उसी पर चल रहे हैं।

चौ. सतवीर सिह मलिक: स्पीकर साहब, यह कोई जवाब नहीं। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या वे सर्विस रूल्ज के मुताबिक इन हाउसिज के लिये एनआइटल्ड हैं?

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कहा कि प्रैसिडैन्ट पड़ गया है और सरकार उस प्रैसिडैन्अ को फालो कर रही हैं। (विघ्न)

चौ. सतवीर सिह मलिक: क्या यह सरकार हमारे सभी प्रैसिडैन्टस को फालो करेगी?

चौ. भजन लाल: अच्छे जरूर मानग, बुरे नहीं मानेंगे। (विघ्न)

चौ. सतवीर सिह मलिक: स्पीकर साहब, आज बहुत से मिनिस्टर्ज साहेबान किराये के मकानों में रह रहे हैं। अगर ये मिनिस्टर्ज हाउसिंज रूल्ज के मुताबिक मिनिस्टर्ज साहेबान को ही अलाट किए जाते तो इससे सरकार को कितना फायदा होता?

श्री अध्यक्ष: इसके लिये तो सैपरेट नोटिस चाहिए।

चौ. सतवीर सिह मलिक: इतना तो ये बता ही सकते हैं कि मिनिस्टर्ज के मकानों पर कितना खर्च पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: फिर तो आपका प्रश्न इस प्रकार होना चाहिए था कि मिनिस्टर्ज के लिये कितने मकान लिये गये हैं और उनका क्या किराया है? (विघ्न)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें इतना बता देता हूं कि ये कोठियां उन्हीं लोगों को अलाट की गई हैं जो इनके लिये एनटाइटल्ड हैं यानी जिनको ये कोठियां सरकार की तरफ से मिलनी चाहिएं।

चौ. संत कंवर: क्या मुख्य मंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे कि जो मिनिस्टर्ज साहेबान बाहर प्राईवेट कोठियों में रह रहे हैं उनको तो इन कोठियों में लाया जाएगा और जो आफिसर्ज इनमें रह रहे है उनको कोई दूसरे मकान अलौट किए जाएंगे?

Mr. Speaker : I think, this is a pointless question and has no relevance.

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, इनको पता होना चाहिए कि श्री दौलत राम, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मैम्बर हैं, और ओ.एस.डी.सी.एम. यानी चौ. देवी लाल को इन्हीं की सरकार ने ये कोठियां अलौट की थीं। (विघ्न) मैंने नहीं की हैं।

Construction of Link Roads from Ding to Bodiwali

***1518. Chaudhri Jagdish Kumar Beniwal** : Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) whether there are any gaps between the road from Ding to Bodiwali ;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to complete this road by constructing these gaps with metalled roads ; and

(c) if so, the time by which it is likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(क) हां

(ख) हां

(ग) भूमि अभिग्रहण के बाद 6 महीने में।

चौ. जगदीश कुमार बैनिवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह सड़क कितने दिनों से रूकी हुई है और कब तक भूमि अभिग्रहण कर ली जाएगी?

कंवर राम पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सड़क 11.11.77 को मन्जूर की गई थी। इसमैं 0.1 किलोमीटर और 0.8 किलोमीटर के दो गैप पड़े हुए हैं। भूमि अभिग्रहण इसलिये नहीं हो सकी कि एल.ए.ओज. की ट्रांसफर जल्दी जल्दी होती रही। अब हम यह सब काम जल्दी करके इसे जल्दी तैयार करा रहे हैं।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मंत्री जी बताएंगे कि एल.ए.ओज. ट्रांसफर केन्द्रीय सरकार करती है या राज्य सरकार करती हे?

कंवर राम पाल सिंह: करती तो स्टेट गवर्नमेंट ही है लेकिन अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि किस तरह से ये लोग ट्रांसफर करवाने आते रहते हैं।

श्री भले राम: अध्यक्ष महोदय, सड़कों में गैप सारे हरियाणा में बाकी हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जहां कहीं भी इस तरह के गैपस बाकी हैं उनको क्या ये पूरा कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल से इसका कोइ सम्बन्ध नहीं है।

श्री भले राम: यह जनरल सवाल है।

श्री अध्यक्ष: वही तो मैं कह रहा हूं कि आप जनरल सवाल पूछ रहे हैं जबकि मेन कवैश्चन पर्टिकुलर रोड के बारे में है।

श्री भले राम: क्या मंत्री जी बताएंगे कि छतरा से सिवानका सड़क जो बीच में रूकी पड़ी है उसका काम कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

कंवर राम पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसके लिये अगर माननीय सदस्य नोटिस दे तो मैं बता दूंगा।

चौ. उदय सिंह दलाल: क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि जिन डुप्लिकेट रोडज पर गांवों के लोग खुद मिट्टी डाल दें या डाल दी हो, उनको प्रायरिटी बेसिज पर बनाने पर विचार करेंगे?

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, सरकार ने फैसला किया है कि पहले सिंगल रोडज को प्रायरिटी बेसिज पर बनायेंगे

क्योंकि कई गांवों में तो जाने के लिये बिल्कुल ही रोडज नहीं हैं इसलिये डुप्लिकेट रोडज को बाद में टेक–अप करेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मिनिस्टर महोदय ने जवाब दे दिया कि पहले सिंगल रोडज बनायी जायेंगी और बाद में डुप्लिकेट रोडज बनायी जायेंगी।

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि भूमि अभिग्रहण इसलिये नहीं किया जा सका कि औफिसर्ज की ट्रांसफर्ज होती रही। मैं मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की इन–एफिसेन्सी और इन–कैपेबिलटी नहीं है?

श्री अध्यक्ष: उसके जवाब में मिनिस्टर साहब ने यही कहा है कि पोलीटीकल इन्टरफीयरेन्स की वजह से औफिसर्ज के जल्दी जल्दी ट्रांसफर होते रहे हैं इसलिये यह पोलीटीकल इन्टरफीयरेन्स बन्द होनी चाहिए।

श्री जय नारायण वर्मा: क्या इसके लिये वोटर जिम्मेदार हैं?

कंवर राम पाल सिंह: क्या सन् 1977 से लेकर 1979 तक जो ट्रांसफर होते रहे हैं उनकी जिम्मेवार भी हमारी सरकार है? उस समय की जिम्मेदारी तो इनकी है, आज की सरकार को ये कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं?

चौ. हरस्वरूप बूरा: क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि सैक्शन चार और छः के नोटिस पर जब तक पूरी कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक पोलीटीकल बेसिज पर उस पीरियड में उस पर कार्यवाही करने वाले अफसर का ट्रांसफर नहीं करेंगे?

कंवर राम पाल सिंह: सरकार फैसला ले रही है कि जो अफसर इस पोस्ट पर लगेगा उसका कम से कम एक साल तक ट्रांसफर नहीं किया जायेगा।

चौ. जगदीश कुमार बेनिवाल: अध्यक्ष महोदय, इस रोड का सन् 1977 से काम रूका पड़ा है जिसके कारण सारी जनता को तकलीफ होती हैं। इस गैप के कम्पलीट न होने के कारण बसें भी नहीं चल सकती हैं और दूसरी विहकल्ज को भी काफी दिक्कत आ रही है। मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट को आये हुए 7–8 महीने हो गये हैं फिर भी कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब यह सड़क सन् 1977 में मन्जूर हुई थी। सरकार ने इस सड़क को बनाना शुरू कर दिया था परन्तु लैन्ड ऐक्ववायर न होने के कारण पूरी नहीं बनायी जा सकी। जहां पर विलेज पार्क है वहां पर सड़क बना दी गई है परन्तु जहां पर इंडीविजुअल की लैन्ड आयी है वहां पर

जमीन ऐक्वायर न होने के कारण सड़क नहीं बनायी जा सकी। उसकी प्रोसिडिंग्ज चल रही हैं।

Haryana Roadways Depot at Sirsa

***1524. Sh. Bhagi Ram**: Will the Minister for Transport be pleased to state –

(a) the date on which the construction of the building of Haryana Roadways Depot at Sirsa was sanctioned; and

(b) whether the construction of the building referred to in part (a) above has been started; if not, the reasons therefor?

परिवजन मंत्री (श्री जगन नाथ):

(ए) अभी तक कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(बी) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे सवाल के ''बी'' पार्ट का जवाब दिया है कि 'प्रश्न ही नहीं उठता'। जब वहां पर बस डिपो बना दिया है तो बस स्टैन्ड भी एक दिन जरूर बनना है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह जवाब कैसे दिया है कि 'प्रश्न ही नहीं उठता'।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, चौ. देवी लाल ने 1.4. 1978 को सिरसा डिपो का उद्घाटन किया। उस टाईम पर मैं चचौ. भले राम चौ. राम किशन और चौ. देस राज दिल्ली जा रहे थे। हम तो दिल्ली चले गये और उन्होंने उदघाटन कर दिया। जब उदघाटन किया था उस टाईम पर यह फैसला नहीं किया था कि यह जगह प्रोपर है या नहीं और डिपो के लिये कितनी जगह चाहिए यह सारे का सारा मामला यों ही चलता रहा। एक जगह उन्होंने बस अड्डे के लिये जमीन ऐक्वायर की थी परन्तु हाईकोर्ट में दूसरी पार्टी ने रिट दायर कर दी और स्टे आर्डर ले लिया। स्टे आर्डर लेने के बाद चौत्र भजन लाल की नयी सरकार आयी तो वहां के लोगों ने कहा कि जो जगह ऐक्वायर की गई है वह शहर से बहुत दूर पड़ती है और बीच में रेलवे फाटक पड़ता है जिसके कारण लोगों को असुविधा होगी। इसलिये जहां पर अब बस स्टैन्ड बना हुआ है, वह बाजार के नजदीक है, शहर के नजदीक है, वहां पर ही बस स्टैन्ड बनना चाहिए परन्तु वहां पर भी बस स्टैन्ड के लिये पूरी जगह नहीं है। इसलिये अब फैसला यह किया गया है कि बस स्टैन्ड तो वहीं पर बना दिया जाये और कर्वशाप तथा दफतर को बारह हिसार रोड पर रेलवे फाटक के पास जो जगह है वहां पर बना दिया जाये। अगले साल तक हम जल्दी से जल्दी बस स्टैन्ड बनाने की केाशिश कर रहे हैं।

चौ. ईश्वर सिंह: स्पीकर साहब, सरकार बड़े बड़े शहरों में बस डिपो बनाने जा रही है। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन

देंगे कि जहां पर छोटे छोटे बस स्टैन्ड भी नहीं हैं और लोग सड़कों पर ही खड़ रहते हैं उन छोटे शहरों को भी बस स्टैन्ड बनाने में प्राथमिकता देंगे? (विघ्न)

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब लोगों को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिये बस स्टैन्ड बनाये जायेंगे। जैसे इस साल चौ. उदय सिंह दलाल के हल्के बहादुरगढ़ में, चौ. हरस्वरूप बूरा के हल्के महम में और चौ. गंगा राम के हल्के गोहाना में बस स्टैन्ड बनाने जा रहे हैं। ये सभी बस स्टैन्ड अपोजीशन के सदस्यों की कांस्टीच्यूऐंसी में बनने जा रहे हैं। हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं।

चौ. कर्म सिंह: स्पीकर साहब, जैसे * * * * इसी तरह से ड्राइवर्ज को भी शराब पीनी की आदत है (शोर)

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): He is casting an aspersion on the Minister concerned. These words should be expunged (Interruptions).

Mr. Speaker: I would request the hon'ble Members to behave in a proper manner (Interruptions).

Public Works Minister (Kanwar Ram Pal Singh): Speaker Sabib, the hon'ble Member should be asked to withdraw these words.

श्री अध्यक्ष: आदरणीय सदस्य ने मंत्री महोदय पर कोई एस्पर्शन कास्ट किया है तो वे अपने शब्द वापिस लें। (शोर)

चौ. कर्म सिंह: मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। (शोर) ....

..

Mr. Speaker: He has apologised and withdrawn the words. These may be expunged.

चौ. कर्म सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ड्राईवर्ज शराब पी कर गाड़ियां चलाते हैं, क्या उनकी रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी? (विघ्न)

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब ये सारे पाली भर्ती कर लिये हैं। (विघ्न)

चौ. सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर को मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पाली भर्ती कर लिये हैं, इसलिये ये शब्द मिनिस्टर साहब को नहीं कहने चाहिएं। (विघ्न)

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Retirement of Employees

***1539. Sh. Mani Ram**: Will the Minister for Finance be pleased to state :-

(a) the time by which the revised pay scales recommended by the Haryana Pay Commission

for the employees of Haryana Government are likely to be enforced; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to retire those Government employees who seek retirement after completion of twenty years of their service; if so, the time by which the said proposal is likely to be implemented?

वित्त मंत्री (श्री बलवंत राय तायल):

(क) कोई समय अवधि निश्चित करना मुश्किल है लेकिन वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार से सक्रीय एवं तत्कालीन विचारधीन है।

(ख) जी हां। मामला सरकार के विचाराधनी है और इस पर जल्दी निर्णय लिए जाने की संभावना है।

Provision of Jeeps to Tehsildars

***1455. Ch. Jagjit Singh Pohloo**: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide jeeps to the Tehsildars during the year 1980-81 in the State; if not, the reasons therefor?

राजस्व मंत्री (चौ. शेर सिंह): हां। राज्य के सभी तहसीलदारों को एक फेज्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत जीपें 5 वर्श की

अवधि में दी जाएंगी। वर्श 1980–81 में 8 तहसीलदारों की जीपें दी जाएंगी।

शोक प्रस्ताव

10.00 बजे

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, तीन मार्च को हमारा सैशन आरम्भ हुआ था। तीन मार्च के पश्चात हमारे देश के दो महानुभाव हम से विदा हो गये। मैं आपकी आज्ञा से उन दोनों महानुभावों के बारे में शोक प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

स्पीकर सहाब, हम सदन पंजाब के भूतपूर्व सिंचाई एवं बिजली मंत्री श्री गुरबख्श सिंह सीबिया के 10 मार्च, 1980 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री गुरबख्श सिह सीबिया का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सीबिया गांव में 11 अक्तूबर, 1921 को हुआ। श्री सीबिया एक प्रगतिशील किसान थे। उन्हें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों का व्यापक अनुभव था। उन्होंने एक कृशक शिश्टमण्डल के नेता के तौर पर इंग्लैण्ड और यूरोप के देशों का भ्रमण किया। उन्होंने अपने जिले में विकास कार्यो के लिये लोगों को नेतृत्व दिया। सन् 1966 में जयपुर में हुए पंचायती राज सम्मेलन में भाग लिया और सन् 1968 में हैदराबाद में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के

अधिवेशन में सम्मिलित हुए। मार्च, 1972 से अप्रैल, 1977 तक वह पंजाब राज्य के मंत्रिमण्डल में सिंचाई एंव बिजली मंत्री के पद पर रहे। वह संगरूर जिले के कई राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों तथा शिक्षा संस्थाओं से संबन्धित थे।

उनके निधन से देश देहाती क्षेत्र के एक निश्ठावान नेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–ग्रस्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है।

यह सदन उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री चन्द्रभान गुप्त के 11 मार्च, 1980 को हुए निधन पर गहरा दुख प्रकट करता है।

श्री चन्द्र भान गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में गांव बिजौली में 14 जुलाई, 1902 को हुआ। उन्होंने लखनऊ से एम.ए.एल.एल.बी. की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसके बाद वह भारतीय राश्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सदस्य के तौर पर भाग लिया। वर्श 1925 में उन्होंने कानून की वकालत आरम्भ की। वह अखिल भारती कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। वर्श 1960 तथा 1964 में वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर रहे। वह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और उन्होंने देश की आजादी के लिये कई बार जेल यात्रा की। श्री चन्द्रभान गुप्त वर्श 1937, 1946,

1952, 1961, 1967 और 1969 से 1974 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वर्श 1946 में वह मुख्य मंत्री के साथ संसदीय सचिव नियुक्त हुए। 1947–57 की अवधि में वह खादय एवं आपूर्ति, जन–स्वास्थ्य, उद्योग तथा आयोजना विभागों के मंत्री रहे। वह 1960–62 तथा 1962–63 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने परन्तु उन्होंने अक्तूबर, 1963 में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। वर्श 1967 में वह पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने किन्तु अप्रैल, 1967 में त्याग पत्र दे दिया। 1967–68 में वह विरोधी दल के नेता रहे ओर 1969–70 में उन्होंने पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभाया। 1970–74 के दौरान वह कांग्रेस (संगठन) विधायक दल के नेता बने। उनका कई सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से सम्बन्ध था।

श्री गुप्त के निधन से देश ने एक राजनीतिज्ञ, देश भक्त और सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है। यह सदन दिवंगत के शोक–ग्रस्त परिवार के सदस्यों से अपनी संवेदना प्रकट करता है।

श्री मूल चन्द जैन (सभ्भालखा): अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो मातमी मोशन यहां हाउस में रखा है, मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ हुआ हूं। इन दोनों महानुभावों से मेरा निजी सम्पर्क रहा है। सरदार गुरबख्श सिंह सीबिया एक बहुत ही शानदार स्वीट परसनैलिटी के पुरूश थे। जहां तक मेरा ख्याल है उनकी हमारे यहां हरियाणा के अन्दर जींद में सम्पत्ति है। इस प्रकार से वे हरियाणा के भी निवासी कहै जा सकते हैं। वे बहुत

ही सज्जन और बहुत ही अच्छा नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। उनके निधन से यह हमारा सारा हाउस अफसोस जाहिर करता है। इसी प्रकार से श्री चन्द्रभान गुप्त जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से थे। उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी जन–सेवा में व्यतीत की। उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी में कहीं पर कोई जायदाद नहीं बनाई। बचपन से ही वे स्वतंत्रता सेसानी रहे। श्री चन्द्रभान गुप्त ने छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता की जंग में हिस्सा लेना आरम्भ किया। भारतवर्श स्वतंत्र होने के उपरान्त वे कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रस्मी तौर पर हम ऐसे प्रस्ताव यहां हाउस में ले आते हैं और पास भी हो जाते हैं लेकिन मैं मैम्बर साहेबान से अपील करूंगा कि ऐसे महानुभाव जो हमारे से जुदा होते जा रहे हैं ओर जिनका जीवन नौजवानों को प्रेरणा देने वाला रहा है, उनके जीवन से हम कुछ सींखे हमारे सामने आज कल यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि लोगों में अपने स्वार्थ के अलावा और कोई लक्ष्य नहीं रहा। हम अपने जाने वाले इस महानुभावों से सबक लें और जिस प्रकार इन महानपुरूशों ने अपना जीवन बिताया है उसी प्रकार से हमारे आज कल के नौजवान अपना जीवन बितायें और अपने देश की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा. मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने जो शोक प्रस्ताव यहां सदन के सामने पेश किया है मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब से यह अधिवेशन शुरू हुआ है इन दिनों के बीच में हमारे से दो महानुभाव पुरूश सरदार गुरबख्श सिंह सीबिया और चन्द्रभान गुप्त का देहावसान हो गया है। सीबिया साहब के शायद मैंने दर्शन किए हों लेकिन मरेा उनके साथ नजदीक का सम्बन्ध नहीं रहा है। जैसा कि सुनने में आया है कि वे बहुत ही सज्जन पुरूश थे और बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन पर निस्संदेह जहां पंजाब की जनता को उनकी सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा वहां हरियाणा की भी जनता उनकी सेवाओं से वंचित रहेगी। श्री चन्द्रभान गुप्त जिसका कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं बल्कि सारे देश की राजनीति में बड़ा महतवपूर्ण स्थान रहा है। शिक्षा काल से ही वे कांग्रेस में रहे और उनकी अपनी धुन में जो बात आ गई सारा जीवन उसी में बिताया। उन्होंने अपना विवाह तक नहीं करवाया। कोई सम्मति उन्होंने नहीं बनाई और दिन रात देश की सेवा करते रहे। बचपन से ही वे स्वाधीनता के कार्य में जुटे रहे और जब तक उन्होंने भारत मां को आजाद नहीं करवाया तब तक चैन की सांस नहीं ली। भारतवर्श के आजाद होने पर वे कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। स्वर्गीय पं. जवाहर लाल नेहरू जी के वे समकालीन नेता थे। श्री चन्द्र भान गुप्त अपनी विचारधारा पर अड़ने वाले थे। उनका उस समय के कई बड़े नेताओं से मतभेद भी हो गया था जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस

पार्टी को छोड़ा था और उस समय उन्होंने संगठन कांग्रेस का साथ दिया। इसके लिये उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से भी वंचित रहना पड़ा। लेकिन वे अपनी विचारधारा पर दृढ़ रहे। स्पीकर साहब मेरा उनके साथ नजदीका सम्बन्ध भी रहा है। मैं उनसे कई बार मिला हूं। आपातकाल के बाद जब केन्द्र में जनता पार्टी आई तो वे जनता पार्टी के खजान्ची बने। अभी कुछ दिन पहले हम दिल्ली में कार्य समिति की बैठक में बैठे हुए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि वे बहुत स्वस्थ हैं। लेकिन वे इतनी जल्दी हमसे विदा हो जायेंगे हमें उम्मीद नहीं थी।

अभी बाबू मूल चन्द जैन साहब ने ठीक फरमाया है कि ऐसी महानुभूतियां जिनमें बड़े गुण हैं और जो देश के लिये प्रेरणा का स्त्रोत बने रहे हैं उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। स्पीकर सहाब, भगवान का यह विचित्र नियम है कि इस संसार में जो भी आया है वह जरूर जाता है।

स्पीकर साहब, जाने वाले महापुरूशों ने जिन आदर्शों के लिये जीवन यापन किया, जिन सिद्धान्तों के लिये जीवन भर संग्राम किया, जिन उदेश्यों के लिये वह रात दिन लगे रहे भगवान से प्रार्थना है कि हम भी और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसी मार्ग पर चलती रहें। अपने मार्ग पर अडिग रह रक एक आदर्श प्रस्तुत करें। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करते हुए मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं। स्पीकर साहब, मेरा ख्याल यह था, कि शायद यह शोक प्रस्ताव शुरू में ही क्वैश्चन आवर से पहले ही

आयेगा। मैं यह चाहता हूं कि आज यदि यह हाउस इन महान पुरूशों की याद में और उनके सम्मान में एडजर्न हो जाये तो अच्छी बात होगी। इससे एक आदर्श पेश होगा। इस सुझाव को रखते हुए मैं अपनी हार्दिक भावनाओं को व्यक्त करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री शमशेर (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो यह शोक प्रस्ताव रखा है, उसमें श्री चन्द्रभान गुप्त और सरदार गुरबख्श सिंह का नाम शामिल है। श्री गुप्त देश के अग्रली पंक्तियों के नेताओं में से एक थे। मेरा कभी उनसे व्यक्तिगत तौर पर तो परिचय नहीं हुआ लेकिन उनकी मौत के वाकई देश को बड़ा भारी आघात हुआ है। सरदार गुरबख्श सीबिया जिनका निधन 10 तारीख को पी.जी.आई. में हुआ, उनसे मेरा सम्बन्ध पिछले 20–25 साल से रहा है। अध्यक्ष महोदय, वे मेरा बड़े नजदीकी और घनिश्ट मित्रों में से एक थे। वे मेरे एक बड़े भाई की तरह से थे। सरदार गुरबख्श सिंह सीबिया ने 1972 में पंजाब में चुनाव लड़ा और वे पंजाब के इरीगेशन एण्ड पावर मंत्री रहे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, संगरूर में सिवाय एक रहने के मकान के उनकी समूचे पंजाब में कोई प्रौपर्टी या कोई जायदाद नहीं है। दरअसल उनके परिवार के जो सदस्य यानी दो लड़के और परिवार के दूसरे सदस्यगण है, वे पिछले कई सालों से जीन्द के निकट दो किलोमीटर पर एक शादीपुरा गांव हैं, वहां पर उनका मॉडर्न फार्म है, वहीं पर स्थायी तौर पर रहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है

कि उनकी परमानैंट रिहायश हरियाणा में है। यह भी मैं इस सदन को बता देना चाहता हूं कि सरदार गुरबख्श सिंह सीबिया, जब 1962 में पंचायती राज के इलैक्शन हुए, तो जीन्द की जिला परिशद के एक मैम्बर चुने गए। उस समय जीन्द जिला संगरूर का ही एक हिस्सा हुआ करता था। फिर वे जीन्द जिला परिशद के चेयरमैन भी चुने गए और 7–8 साल तक वहीं पर रहे। अध्यक्ष महोदय, 1952 में सरदार गुरबख्श सिंह सीबिया, असैम्बली के चुनावों में सफीदों हल्के से जो कि पंजाब का ही एक हल्का हुआ करता था, चुने गए। अध्यक्ष महोदय, सरदार गुरबख्श सिंह सीबिया के पिता से बहुत बड़े बिसबेदार थे। उनके पास शादीपुरा ओर उसके आस–पास के 5–6 गांवों की सारी जमीन थी। अपने पिताजी के स्वर्गवास होने के पश्चात् जब श्री सीबिया मालिक बने तो सारी जायदाद पर जो मजारे थे, जो टेनैन्टस थे, उन्होंने उनको ट्रांसफर कर दी। किसी भी आदमी के साथ उनका किसी भी किस्म का झगड़ा जायदाद के बारे मे नहीं हुआ। जिस तरह से पिछले दिनों में यह देखने में आया है कि मालिकों के साथ मुजारों के झगड़े होते रहे हैं, उन्होंने किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं किया और सारी जायदाद मुजारों को दे दी। उनका जो शादीपुरा गांव में आजकल एक फार्म है, वह एक माडर्न फार्म है, सारे हरियाणा में वह सबसे बढ़िया ओर अच्छा फार्म है जहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेती की जाती है। अध्यक्ष महोदय, जहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेती की जाती है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक उनकी व्यक्तिगत परसनैलिटी का सवाल है,

पंजाब में और सारे हरियाणा में इतना अच्छा और नेक इन्सान कहीं नहीं मिलेगा। चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव साईड वाले अफसर लोग हैं, या चाहे वह गांव का एक सर्वसाधारण व्यक्ति है, वह सब में एक सर्वप्रिय व्यक्ति थे। अध्यक्ष महोदय मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, मेरी नौलेज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ळै, जो सरदार गुरबख्श सिंह जी से ज्यादा सर्वप्रिय रहा हो। उनकी उम्र अभी 60 साल की भी नहीं हुई थी। उनसे पंजाब को और हरियाणा को बहुत उम्मीदें थे। उनके बेवक्त चेल जाने से जहां पंजाब को और हरियाणा को बहुत नुक्सान हुआ है, वहां मैं यह समझता हूं कि मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर बड़ा भारी आघात लगा है। इन शब्दों के साथ मैं सरदार गुरबख्श सिंह सीबिया ओर सी.बी. गुप्ता जी के परिवार को इनके निधन पर शोक प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker: Hon. Members, I fully associate myself with the deep feelings of sorrow expressed in this House at the sad demise of Sardar Gurbax Singh Sibia and Mr. C.B. Gupta. their selfless service to the nation, as pointed out by various members of the House, will be a shining example for all of us. It will be my sad duty to convey the condolences expressed in the House to the bereaved families. I would now request you all to kindly observe silence for two minutes while standing as a mark of respect to the departed souls.

(इस समय दिवंगत आत्माओं के सम्मान मैं सदन ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

ध्यानाकर्शण सूचनाएं

(i) हथनी कुंड बैरेज के निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मध्य 1974 का समझौता लागू करने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: साहेबान, मुझे चौ. हर स्वरूप बूरा की ओर से हथनी कुंड बैरेज के सम्बन्ध में हरियाणा और यू.पी. गवर्नमैंट के बीच 1974 में हुए एग्रीमैंट को इम्प्लीमैंट करवाने के बारे में एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस मिला है जिस मैं कल मन्जूर कर चुका हूं। माननीय सदस्य कृपया अपना नोटिस पढ़ दें।

(ii) ओलावृश्टि से फसलों आदि के नश्ट होने सम्बन्धी

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, एक काल अटैन्शन मोशन मेरा भी था। .....(शोर)

श्री अध्यक्ष: एक दिन में एक काल अटैन्शन मोशन ही आ सकता है।

चौ. संत कंवर: तीन दिन पहले का है। (शोर एवम् व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शायद रिजैक्ट हो गया होगा।

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, मेरा काल अटैन्शन मोशन ओला वृश्अि के बारे में था।

श्री अध्यक्ष: ओलावृश्टि के बारे में मुझे 4–5 मैम्बर साहेबार की तरफ से काल अटैन्शन मोशन प्राप्त हुए थे, वे मैंने नामन्जूर कर दिय हैं। गवर्नर एड्रैस पर और बजट पर जनरल डिस्कशन के वक्त मैम्बर साहबान को ऐसी बातों पर रोशनी डालने का काफी मौका मिलेगा। जिन मैम्बर साहेबान का नोटिस आया है, उनको मैं यह बात स्पश्ट करना चाहता हूं कि उनको मैं 4–4 या 5–5 मिनट का टाईम जरूर दूंगा ताकि वे इस विशय पर बोल सकें।

चौ. हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान हथनी कुंड बैरेज के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा सरकार के मध्य 1974 के समझौते को लागू करने के लिये राज्य सरकार द्वारा तत्काल उठाए जा रहे पगों सम्बन्धी हाल ही के तथा लोक महत्व के एक विशेश मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

यह मामला और गंभीर तथा तीव्र हो गया है विशेशकर जब फरवरी, 1980 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बैरेज पर अपनी पुलिस भेजी तथा उत्तर प्रदेश मुख्य अभियंता, सिंचाई के निदेश पर चल रहा काम बन्द कर दिया गया है।

सदन यह भी जानना चाहता है कि क्या सरकार 1974 के उक्त समझौते का पुनर्विलोकन कर रही है या उत्तर प्रदेश सरकार उसका पालन करेगी। क्या हरियाणा सरकार बैरेज के स्थान को बदल रही है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस बैरेज से वापस बुला ली गई है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय अब जवाब देना चाहेंगे या फिर कभी।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी): स्पीकर साहब मैं अभी इसका जवाब देता हूं।

वक्तव्य

सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा हथनी कुंड बैरेज के निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मध्य 1974 का समझौता लागू करने सम्बन्धी

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी): स्थित ताजेवाला वैयर जो कि उत्तर प्रदेश में पूर्वी यमुना नहर और हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर को 1954 में दोनों राज्यों में हुई सहमति अनुसार पानी देता है। इस सममति अनुसार दरिया का पानी पंजाब (अब हरियाणा) तथा उत्तर प्रदेश में 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, जब कि दरिया का निकास 10.900 क्यूसिकस से

अधिक है, यदि निकास 10.900 तक है, तब नया फारमूला यह वैयर 100 वर्श पुराना है तथा इसको असुरक्षित घोशित यिा गया तथा इसको नये बैरेज में बदला जायेगा जो इन दोनों नहरों की दशा को और सुधारने में सहायता करेगा। नये बैरेज को स्थित करने बारे अध्ययन पिछले 10 वर्शों से विचारधीन हैं। केन्द्रीय सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मुख्य मंत्रियों ने सितम्बर, 1972 में निर्णय किया कि नये बैरेज का निर्माण कार्य हरियाणा सरकार द्वारा किया जावे तथा इस बैरेज की स्थिति का निर्णय तकनीकी कमेटी जिसके प्रधान केन्द्रीय जल आयोग के मैम्बर डी.एण्ड आर. होंगे और राज्यों के मुख्य इंजीनियर इस कमेटी के मैम्बर होंगे, निर्णय करेगे। इस तकनीकी कमेटी की तीन बैठकें हुई। अतः तीसरी मीटिंग जो 23.10.73 को हुई थी, की मिनटस के पैरा–3 द्वारा निम्नलिखित बताया गयाः–

''कमेटी ने इंजीनियर ज्योलिजिस्ट की उपरोक्त सिफारिश को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया कि नेय ताजेवाला बैरेज के लिये हथनी कुंड तथा कलेसर के बीच की साइट उचित होगी। उपरोक्त तीनों क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का निर्णय, निदेशक, सी.पी. डब्ल्यू.आर.एस. पूना द्वारा हाईड्रोलिक माडल का अध्ययन करने के बाद लिया जावेगा (अर्थात पहला हथनीकुंड दूसरा हथनीकुंड, के ऊपर की ओर आधा मील पर तथा तीसरा कलेसर में हथनीकुंड की उपर की ओर एक मील पर)।''

तत्पश्चात भूतपूर्व केन्द्रीय सिंचाई तथा बिजली मंत्री, श्री के.सी. पन्त द्वारा उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। उस समय उन्होंने भूतपूर्व केन्द्रीय सिंचाई एवं बिजली मंत्री के निर्णय को मानने के लिये बैरेज की ठीक स्थिति के बारे में हस्ताक्षर किये। अन्त में इस सहमति को सामने रखते हुए श्री के.सी. पन्त ने बैरेज की स्थिति के बारे में किये गये निर्णय को मुख्यमंत्री हरियाणा को अ.स.पत्र क्रमांक पी. डब्ल्यू. II/78 (46) 76, दिनांक 13.9.74 जो निम्न प्रकार है, सूचित किया:—

''आप को दिनांक 21.7.74 को ताजेवाला तथा औखला बैरेज के सम्बन्ध में सहमति पर आप द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बहुगुणा द्वारा किये गये हस्ताक्षरों के बारे याद दिलाऊं। हमने दिनांक 6.9.74 बाद दोपहर शुक्रवार को इस मामले पर विचार किया था। इस समय केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग के अध्यक्ष ने दो प्रश्नों पर तकनीकी तत्वों की व्याख्या की थी। मैंने 7.9.74 की सायं को श्री बहुगुणा से भी विचार विमर्श किया था। आप द्वारा 21.7.74 की सहमति में बताए गये दोनों मामलों पर तकनीकी विचार से ध्यान पूर्वक अध्ययन के बाद मैंने यह निर्णय किया कि ताजेवाला बैरेज की स्थिति हथनी कुंड पर होनी चाहिए और औखला बैरेज का पौंड लेबल 660 आर.एल. नियत होना चाहिए और डिजाईन तथा निर्माण पौंड लेकवन आर.एल. 660.50 आवश्यकता पड़पे पर बढ़ाया जावे। मैं इस निर्णय से श्री बहुगुणा

को भी सूचित कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि दोनों राज्य इन दोनों बैरेजों को पूर्ण करने के लिये शीघ्र कदम उठायेंगे। सादर सहित।''

इसके पश्चात भारत सरकार ने पत्र क्रमांक 28 (46) 71 पी.डब्ल्यू.डी.–II दिनांक 21.11.75 द्वारा एक पुनर्निरीक्षण कमेटी की पहली तथा दूसरी मीटिंग जो 17.2.76 तथा 19.8.76 को हुई थी, में निर्णय किया कि माडल स्टडी केन्द्रीय जल, बिजली अनुसंधान स्टेशन, पूना जो केन्द्रीय सरकार की बड़ी तकनीकी तथा पृथक अनुसंधान संस्था है, हथनी कुंड बैरेज की स्थिति बारे तथा बैरेज का डिसचार्ज जो पश्चिमी यमुना नहर तथा पूर्वी यमुना नहर से निकलते हैं। तीसरी तथा चौथी बैठक 15.1.77 तथा 10.6.77 को हुई थी, में उत्तर प्रदेश इंजीनियरों ने बैरेज के डिजाईन तथा एक्सिस हथनी कुंड के बारे अपने विचार रखे। केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने तीसरी पुनर्निरीक्षण की बैठक जो 15.1.77 में हुई थी, निम्न प्रकार कहाः–

''अध्यक्ष ने कहा कि दोनों नहरों के संतोशजनक चलने बोर समस्या अनुसन्धान स्टेशन को पता है तथा वह ऐसी सलाह देंगे जो दोनों राज्यों को स्वीकार होगी। यह बैरेज के एक्सिस, स्थिति इत्यादि से सम्बन्धित होंगे। इसलिये उन्होंने सलाह दी की माडल निर्माण अधीन है तथा दो राज्य इसमें हिस्सा लेंगे। केन्द्रीय जल आयोग का एक अधिकारी इस संयुक्त यात्रा के लिये भेजा जायेगा।''

उपरोक्त निर्णय के अनुसार यह मामला केन्द्रीय जल, बिजली अनुसंधान स्टेशन को सौंपा गया। वह नये बैरेज विस्तार माडल स्टडीज के एक्सिस तथा दूसरे तकनीकी डिटेल में लग गये। हथनी कुंड बैरेज की स्थिति बारे 18.7.77 को उत्तर प्रदेश, हरियाणा केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय जल बिजली अनुसंधान के प्रतिनिधियों ने सयुंक्त निरीक्षण किया तथा विचार विमर्श के आधार पर इसमें कुछ सुधार करने का निर्णय लिया। 1978 के बाढ़ रिकार्ड बाद जो 7 लाख कयूसिक्स से अधिक था इस माडल को अन्तिम सर्वे के आधार पर बनाया गया। उत्तर प्रदेश इंजीनियरों ने माडल के पूना से सिद्ध करने से पहले ही एतराज उठाने आरम्भ कर दिये। इस संदर्भ में 4/79 में दो राज्यों के इंजीनियरों के बीच हुई बैठक की ओर ध्यान दिलाया आजा है जबकि उत्तर प्रदेश ने नये बैरेज की आवश्यकता बारे बताया इसकी बजाय वह ताजेवाला बैरेज को ठीक स्थित करने का कोई ठीक साधन प्रस्तावित करते। उत्तर प्रदेश के प्रतितिनिधियों ने इस माडल स्टडी के लिये भाग लेने के लिये इन्कार कर दिया जबकि उन्हें अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग द्वारा ने कहा जावे। 16/17.10. 79 को उत्तर प्रदेश, हरियाणा केन्द्रीय जल आयोग के इंजीनियरों की माडल के संयुक्त निरीक्षण का प्रबन्ध किया गया तथा माडल को सिद्ध किया गया। केन्द्रीय जल बिजली अनुसंधान स्टेशन, पूना ने 3.12.1979 को इस बारे में अपनी अन्तरिम सिफारिश भेजीः—

(1) हरिया खासकर हथनी कुंड के ऊपरी भाग में अस्थाई रूप से बहता है। हथनी कुंड और स्पर 10–6 के बीच में दरिया एक ही धारा के रूप में बहता है जिसमें कि हथनी कुंड बैराज की स्थिति नियत की जा सकती है। बैरेज तथा इसके ट्रेनिंग वर्कस की स्थिति तथा एलाईनमैंट इस प्रकार होनी चाहिए कि यह इन्तजाम दरिया की सीधी स्थायी दिशा में खलल न पड़े।

(2) माडल स्टडीज ने दर्शाया है कि बैरेज यदि एक्सिस II ए या III ए पर स्थित किया जाये तो इसके काम करने में बड़ा संतोशजनक अवसर है। असल में माडल स्टडीज बैरेज के साथ स्थिति को जरूरी समझा गया।

केन्द्रीय जल आयोग ने इस सिफारिश पर अपने पत्र क्रमांक 8.3.79 बी.एंड.सी.डी.–I/1605, क्रमांक ?–/12/79 द्वारा टिप्पणी भेजी जिसका उदारण निम्नलिखित है:–

''बैरेज की स्थिति सम्भवतः दो तरीकों II ए या III ए में से हम यह महसूस करते हैं कि मार्ग रेखा II ए का माडल करवाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अधिक विकास के समय हैड रैगुलेटर और बैरेज के भली प्रकार कार्य करने की स्थिति उचित होगी। फिर भी हमने जो अध्ययन किया है वह यह बताता है कि मार्ग रेखा II ए में इसके ऐंगल को एक्सिस के नीचे की ओर एक्सिस II के साथ 20^0 से 10^0 तक बदलने का सुधार किया

जा सकता है। फिर भी जो उचित एक्सिस है, का निर्णय आवश्यक अध्ययनों के पश्चात् किया जाए।''

यदि इस मार्ग रेखा का परिणाम संतोशजनक नहीं मिलता है तो हम एक्सिस–III ए पर विचार कर सकते हैं।

हरियाणा सरकार ने बैरेज की स्थिति II-ए पर मानने के लिये अपनी टिप्पणी/सिफारिशें केन्द्रीय जल बिजली अनुसंधान स्टेशन को भेज दी हैं। अब बैरेज का ढांचा वास्तव में माडल द्वारा किये गये अध्ययन अनुसार रखा है। ऐसा ज्ञान होता है कि अध्ययन को अन्तिम रूप दे दिया है और उनकी अन्तिम सिफारिशें शीघ्र ही प्राप्त होनी चाहिएं।

1978 की बाढ़से यह पता चला है कि स्थित ताजेवाला बान्ध पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यह बाढ़ के समय मैं कभी भी गिर सकता है तथा इस प्रकार हरियाणा के 50 प्रतिशत सिंचाई वाला क्षेत्र अलग हो जायेगा। इस कठिनाई को हल करने के लिये हरियाणा सरकार ने वोफर डैम बनाया और चालू वर्श के बीच बैरेज की स्थिति से पानी की सप्लाई को मोड़ लिया। यू.पी. सरकार ने 1974 की सहमति से निकलने तथा इसमें देरी करने के लिये एतराज उठाए। उत्तर प्रदेश सरकार को बताया है कि हमारा एतराज केवल यह है कि इस वर्श बनाये जा रहे कुछ भाग को बचे हुए चालू वर्श के लिये प्रयोग करना है।

केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री द्वारा 1972 में बैठक में किये गये निर्णय अनुसार जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, हरियाणा ने हथनी कुंड बैरेज बनाया है और इसका एक भाग उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है।

हमने यह मामला प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री को बता दिया है। हाल ही में अभी बताया कि वह इस मामले को हल करने के लिये दोनों राज्यों की बैठक बुलायेंगे।

हमने यह मामला प्रधानमंत्री, गहमंत्री तथा केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री को बता दिया है। हाल ही में अभी बताया कि वह इस मामले को हल करने के लिये दोनों राज्यों की बैठक बुलायेंगे।

ज्यों ही मामला तय हो जाता है, चालू वर्श में बैरेज का एक भाग बनाना प्रस्तावित है।

चौ. हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या वहां पर काम बन्द है या काम चल रहा है?

चौ. मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, वहां पर इस समय काम बन्द है। दोनों सूबों के चीफ सैक्रेटरीज के लैवल पर बातचीत चल रही है।

चौ. हरस्वरूप बूरा: स्पीकर सहाब, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि चैनल पर काम शुरू किया गया था। स्पीकर साहब, कहीं यहां पर वैसी ही हालत ने हो जाए जैसे कि एस.वाई.एल. की हुई है। हमने अपनी यहां पर तो नहरें बना लीं और पंजाब साइड पर कोई काम नहीं हुआ है जिसका नतीजा यह है कि हरियाणा में जो नहरें बनी हैं वे बेकार पड़ी हैं। यहां पर भी वैसी ही हालत न हो जाए कि चैनल तो बन जाए और बैराज ने बन पाए जिससे चैनल पर खर्च किया हुआ पैसा बेाकर ही चला जाए?

चौ. मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले बताया है कि वहां पर इस टाईम काम बन्द है। दोनों चीफ सैक्रेटरीज के लैवल पर बातचीत चल रही है। सैन्ट्रल गवर्नमैंट के पास मामला गया हुआ (व्यवधान)।

चौ. हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि चैनल पर काम बन्द है या चल रहा है?

चौ. मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, इस वक्त कोई काम नहीं चला रहा है, बिल्कुल बन्द है (व्यवधान)।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हिसाबर ज्यों का त्यों, कुनबा डूबा क्यों? यह तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, मैं क्या कर सकता हूं। जब मैंने बताया तो उस वक्त आनरेबल मैम्बर ने ध्यान से सुना ही नहीं होगा। (शोर)

वर्श 1980–81 के बजट पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब वर्श 1980–81 के बजट पर जनरल डिसकशन शुरू होगी।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्श 1980–81 के बजट पर अपने विचार इस सदन के सामने रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, बजट का जो मकसद है, जहां तक मैं समझता हूं वह यह होता है कि पिछले साल हरियाणा सरकार की तरफ से जो राज्य में कार्य हुआ और उन कार्यों के लिये जितनी राशि रखी गई, खर्च की गई क्या वे कार्य ठीक तरीके से सम्पन्न हुये? दूसरी बात यह है कि जो अनुमान पिछले साल के बजट में लगाये गये, क्या वे अनुमान पूरे हुए या नहीं? खासतौर पर जिन जिन लक्ष्यों को मदेनजर रखते हुए बजट बनाया गया, क्या वह लक्ष्य पूरे हुए हैं उनमें जितनी कमियां थीं, क्या उन कमियों को पूरा करने के लिये सरकार ने नए बजट में कोई ठोस कदम उठाये हैं? स्पीकर साहब इन सब कसौटियों से बजट को परखा जाता है। देखना यह होता है कि इन कसौटियों पर बजट खरा उतरा है कि नहीं। मेरे विचार से यह बजट बिल्कुल, कतई

जीरो है। जैसे कोई रूटीन का बजट हो, काम चलाऊ बजट हो, इस तरह का फायनेन्स मिनिस्टर जी ने यह बजट पेश किया है। (विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): जैन साहब, आपको पूछ कर बजट थोड़ा पेश करना था।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा श्री जगन नाथ जी से यह कहना चाहता हूं कि उनको यूंही बीच में इंटरवीन करने की आदत सी हो गई है। अब वे मिनिस्टर हैं, उनको अब मैच्योर हो जाना चाहिए। इममैच्योरिटी उनको शोभा नहीं देती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बाबू जी, आप कृपया जारी रखें। I would also request the Hon'ble Minister not to interrupt the hon. Member.

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, यू ही बीच में इंट्रप्ट करते हैं, कोई मैम्बर प्वायंट आफ आर्डर लेकर खड़ा हो जाता है और कोई बीच में इस तरह से इंट्रप्ट करता है (विघ्न एवं शोर) और साथ में आपको यह भी कहना चाहता हूं कि श्री जगन नाथ जी अपनी सीट से भी नहीं बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बाबू जी, आप अपनी स्पीच जारी रखें। मैं हाउस के दोनों साइडज के मैम्बर साहेबान से रिक्वैस्ट करूंगा, कि जब कोई मैम्बर बोल रहा हो तो इंट्रप्ट न करें।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर तायल साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारी उनसे बहुत पुरानी एसोसीऐशन रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनका कांग्रेस पार्टी के काफी देर का वास्ता रही है और उन्होंने काफी अर्से तक अपना जीवन कांग्रेस पार्टी के साथ ही व्यतीत किया और फिर उन्हें 1968 में कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया और मैंने 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी।

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: There is nothing which attarcts any point of order. Therefore, I disallow your point of order.

श्री मूल चन्द जैन: लगातार 30 वर्श तक हम पब्लिक जीवन में रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे और उसी कांग्रेस का यह लक्ष्य रहा है कि प्रजातंत्र द्वासरा देश में समाज वाद की स्थापना करे। इसी लक्ष्य को इसी रूलिंग पार्टी ने, जिसका अभी अभी कांग्रेस में विलय हुआ है, अपने इलेक्शन मेनोफेस्टो में दोहराया था। स्पीकर साहब, जहां तक देश का उत्पादन बढ़ाने का सवाल है उससे किसी को मतभेद नहीं है लेकन इतना ही महत्वपूर्ण सवाल वितरण का है उसके बारे में सरकार को अपनी नीति निश्चित करनी चाहिए कि जो उत्पादन किसान मजदूर अपने खेतों व फैक्टरियों से करें उसका वितरणप किस प्रकार से हो। कहीं ऐसा न हो कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वे लेबर को किसान को एक्सपलायट

करें और देश का सारा धन, गरीब जनता की कमाई का पैसा खुद ही खा जाएं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे विचार से ऐसे लोग देश से तो क्या, अपनी इस गरीब जनता के साथ भी गदछारी करेंगे। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक माननीय सदस्य श्री के.एल. पोसवाल पदासीन हुए)

चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि बड़े बड़े मगरमच्छ लेवर को एक्सपलाइट करें। इस सम्बन्ध में मैं आपको कुछेक बड़े बड़े कारखानेदारों और इंडस्ट्रीलिस्टस के आंकड़े बताना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमैन साहब, यह सेन्टर का मसला है, इनको कहा जाए कि यहां पर हरियाणा के वार्शिक बजट पर चर्चा हो रही है, उसी तक ही अपनी स्पीच सीमित रखें।

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, बिरला के कारखाने हमारे हरियाणा में भी हैं, और बैकवर्ड एरियाज से सम्बन्धित जो कारखाने हैं, उनका जिक्र भी इस बजट में किया गया है, तभी कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीलिस्टस के आंकड़े मैं यहां देना चाहता हूं। बिरला ग्रुप के 1170.15 करोड के असैटस हैं उसका टर्न ओवार है 1374.56 करोड़ और प्रोफिट 98.81 करोड़। यह एक साल का प्रौफिट है। इसी प्रकार से टाटा है, उसका निजी मुनाफा 81 करोड रूपए सालाना है। तीसरा मफल लाल ग्रुप है, उसकी प्रौफिट की फिगर्ज 41.67 करोड़ हैं।

श्री सभापति: जैन साहब, इसका कंसर्न हरियाणा से है या कि आल इंडिया से।

श्री मूल चन्द जैन: सारे इंडिया से, चेयरमैन साहब।

श्री दीप चन्द भाटिया: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जैन साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, सुलझे हुए हैं लेकिन इनको यह नहीं पता कि यहां पर असैम्बली की बात हो रही है, सारे हिन्दुस्तान की बात नहीं हो रही।

श्री सभापति: भाटिया जी, मैंने पहले ही यह प्वायंट आउट कर दिया है।

श्री दीप चन्द भाटिया: चेयरमैन साहब, अगर इन्होंने सारे हिन्दुस्तान की बातें करनी हैं तो पहले ये इलैक्शन लड़े, फिर पार्लियामेन्ट में जाकर के इन बातों का वहां जिक्र करें।

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, मैंने शुरू में ही बोलते हुए कहा था कि अब हम यहां पर बजट पर डिस्कशन का रहे हैं। मैं अपने साथी को यह बता देना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल रेलेवेन्ट बोल रहा हूं। मैं उनको सफा नम्बर भी देखकर बता देता हूं। बजट स्पीच के 22 पेज पर लिखा है:—

"The State Government is considering a set of measures to import greater dynamism and flexibility to its industrial policy. The Government has under its active consideration the decleration of a few more areas as

insutrirally backward and, with a view to inducing the industrialists to establish industrial units in these areas, to grant a subsidy there in as well .....

At page 21 of the Budget speech it is mentioned-

"The entrepreneurs are also being encouraged to set up industries in the Backward areas of the State, and a subsidy of Rs. 66.28 lakhs has been granted to 36 industrial units set up in these areas ....."

स्पीकर साहब, सरकार ने कुछ उद्योगों में इकविटी पार्टीशिपेशन 15 प्रतिशत कर दिया है जोकि पहले 10 प्रतिशत होता था। बजट भाशण में एफ.एम. साहब ने कहा है कि 36 यूनिटस को बैकवर्ड एरियाज के नाम पर बड़ी फैक्टरियों के लिये 66.28 लाख रूपए की सबसिडी दी है और आज ही चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरे सवाल के जवाब में बताया है कि जब रूरल इंडस्ट्रीलाईजेशन का प्रोग्राम चालू हुआ तब से 1.1.1980 तक 1900 यूनिटस लगाये गए हैं। चेयरमैन साहब, मैंने पूछा था कि आपने बैंकस के द्वारा ओर दूसरी इंस्टीटयूशंज के द्वारा कितनी मदद दी है। मैं यह सुनकर हैरानी रह गया कि जो कर्जे की रकम थी, वह लगभग 1–2 करोड़ या इससे कुछ ज्यादा थी लेकिन ग्रान्ट जो थी, वह 3–4 लाख से ज्यादा नहीं दी गई। वैसे तो सरकार गांव गांव में दहाई देती है है जो नवयुवक हैं, तालीमयाफता नौजवान हैं, उनको चाहिए कि वे खेती बाड़ी छोड़कर गांवों में इडस्ट्रीयल यूनिटस लगाएं लेकिन दूसरी तरफ

आप देखेंगे कि इन दो हजार यूनिटस को तो कुल ग्रांट की मात्रा है 3–4 लाख रूपए लेकिन ओर 30 बड़े यूनिटस को 66 लाख रूपये सबसिडी दी है। (विघ्न) मैं भाटिया साहब और अपने दूसरे सज्जनों को यह कहना चाहात हूं कि कृपया इसे पार्टी लाईन में न लें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं इस प्वायंट को पार्टी लाईन से नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारा जो एटीच्यूड है वह तो प्रो रिच नहीं होना चाहिए। अगर हमारा एटीच्यूट प्रो रिच होगा तो इस देश की समस्याएं हल नहीं होंगी। समस्याओं का हल तो तभी होगा अगर हम लक्ष्य की प्रान्ति के लिये पूरा अमल करेंगे। लेकिन अमल करते वक्त हमारे कदम डगमगाने लग जाते हैं। अब लैन्ड रिफार्मज की मिसाल ले लीजिये उसके बारे में मैंने नहीं कहा बल्कि प्लानिंग कमिशन की एक कमेटी ने कहा कि इस देश में लैंड रिफार्म इसलिये फेल हुआ कि ऐसा करने के लिये पोलिटीकल विल नहीं थी। जो मिनिस्टर लोग हैं या जो आल इंडिया सर्विस वाले हैं वे फेल हो गये। आज नाम तो लिया जाता है कि हम इस देश में समाजवाद लाएंगे लेकिन जब काम करने का मौका आता है तो अपने भाई भतीजे याद आ जाते हैं। इसीलिये मैंने बिड़ला और टाटा आदि का नाम लिया था। चेयरमैन साहब, सन् 70 या 71 मैं एक बहुत बड़ा इकोनोमिस्ट मि. गुनार मिरडल यहां आए थे। उनकी पत्नी भी एक बड़ी इकोनोमिस्ट हैं। वे पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने टाइम में हिन्दुस्तान में आया करते थे। वे जब 1970–71 में इस देश में आये तो उन्होंने खासतौर पर एक आबजरवेशन की जो

अखबारों में भी छपी। वह सारी बात तो मेरे याद नहीं लेकिन मैं उसका सार बताता हूं। उन्होंने यह कहा कि हिन्दुसतान जैसे प्रगतिशील देशों का यह दुर्भाग्य है कि यहां के एलाइट लोग (एलाइट में ऐसे पढ़े लिखे लोग आते हैं जो अमीर हैं) समाजवाद की बातें करते हैं, गरीब लोगों के भले की बातें करते हैं लेकिन जब भी कोई कदम गरीब लोगों की भलाई के लिये उठाया जाता है और जब भी कोई कदम समाजवाद की तरफ बढ़या जाता है तो ये एलाइट लोग इन कदमों में रोड़ा अटकाते हैं। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह हमें बताए कि हम समाजवाद के लिऐ यह कदम उठाने जा रहे हैं। अगर सही ढंग से एक एक करके भी ये कदम उठाये जाएं तो भी यह रास्ता बहुत लम्बा है। आजादी के पहले भी आप और हम गुलामी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। उस वक्त भी यह बहुत लम्बा रास्ता था। लेकिन गांधी जी के पद चिन्हों पर हम चलते रहे। जब मैं 13 महीने की नजरबन्दी के बाद मुलतान जेल से निकला था उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि अभी एक और लड़ाई आजादी के लिए हमें लड़नी पड़ेगी क्योंकि उस वक्त हालात ही ऐसे पैदा हो गये थे परन्तु सन् 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद हमने सोचा कि अभी एक और लम्बा रास्ता हमारे सामने है कि इस देश के गरीब आदमियों को आर्थिक तौर पर कैसे आजाद किया जाए। गरीब आदमियों में सभी लोग शामिल हैं चाहे वह गरीब बनिया है या जाट है या और किसी जाति का है हरिजन तो प्रायः गरीब हैं ही। यानी जिनकी इकोनोमिक कंडीशन खराब है वह गरीब आदमी में शामिल है।

क्या आप इन लोगों को स्टैंडर्ड इसी तरीके से बढ़ाएंगे कि शहरों में बैठे हुए करोड़पतियों को बैकवर्ड इलाके का नाम देकर लाइसैंस देते चले जाएं? मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही इरादों पर अमल करोंगे तो मैं इन इरादों को नापाक कहूंगा। हमें चाहिए तो यह कि जो नीति हाउस सर्वसम्मति से तय करे उस पर ईमानदारी से अमल करवाएं। मैं इस प्वायंट को ज्यादा नहीं खींचना चाहता। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी को यही प्रार्थना करूंगा कि वे जब कोई पौलिसी निर्धारित करें तो कम से कम बीस सूत्री प्रोग्राम का ही ध्यान कर लें। चौ. शमशेर सिंह जी ने गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए इस संबंध में सरकार का ध्यान दिलाया था। चेयरमैन साहब, ये बीस सूत्री प्रोग्राम पर अमल तो क्या करेंगे ये तो बीस सूत्री प्रोग्राम को गिनवा भी नहीं सकते (शोर)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): चेयरमैन सहाब, हम तो 9 प्वायंट और जोड़ कर 29 तक भी बता देंगे। हमें बीस सूत्री प्रोग्राम को गिनना नहीं है बल्कि उस पर अमल करना है। काबलियत की गठरी तो इनके पास ही है। (शोर)

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैंन साहब, एक गुस्ताखी का मैं हल चाहता हूं कि जब मैं हाउस में कुछ प्वायंटस रखता हूं तो रूलिंग पार्टी की तरफ से यह कह दिया जाता है कि में बहुत काबिल हूं। तो मैं कैसे अपने सिर या टांगों को काटुं। ये जो कुछ कह रहे हैं अगर यह वाकई में सच है तो अगर ये मेरे कहे से कोईं सबक ले लें तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई बुरी बात नहीं

है। इसके अलावा मुझे यह गिला भी करना है कि कल मैंने सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस पर बोलने हुए खास तौर पर प्वायंट उठाया था और मिनिस्टरों को कहा था कि मेरे सवालों का जवाब दो। लेकिन मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। मैं एक बात फिर दोहराता हूं कि बी.एंड.आर., जंगलात और एजुकेशन डिपार्टमैंटस में जो इन्होंने 1 करोड़ 20 लाख की सेविंग दिखाई है उसके बारे में फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यह सेविंग 6 प्रतिशत कटौती की वजह से हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि वह सेविंग 6 प्रतिशत कटौती की वजह से नहीं है बल्कि वह किसी और प्रकार की सेविंग है। मैंने जब इससे पूछा कि आप बताएं कि यह सेविंग कैसे हुई तो इन्होंने जवाब नहीं दिया बल्कि यह कहा कि इनको जो विरासत में स्टेट का ढांचा मिला था उसमें 36 कराड़ रूपये का घाटा था। हमने 6 प्रतिशत की कट लगा कर इस स्टेट के ढांचे को बचा लिया। चेयरमैन साहब, यह सरकार बिल्कुल गल्त क्लेम करती है। जब मैं उस समय की जनता सरकार में फाईनेंस मिनिस्टर था उस समय मैंने खास तौर से जिक्र किया था और मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि जो हमें यह 36–37 करोड़ रूपए का घाटा नजर आ रहा है इस घाटै में से 14 करोड़ रूपए तो भारत सरकार ने देने का वायदा कर लिया है और वह 14 करोड़ रूपया हरियाणा सरकार को मार्च–अप्रैच, 1979 से पहले–पहले ही मिल गया था। बाकी रह गया 22 करोड़ का घाटा उसके लिये मैंने, जो आज चीफ मिनिस्टर हैं और जो मिनिस्टर्ज हैं तथा इसके अलावा जो मैम्बर्ज हैं जो उस समय की जनता

सरकार में या पार्टी में थे उनसे कहा कि समस्याओं को फेस करने से समस्याएं हल होती हैं। समस्याओं से दूर भागने से समस्याएं हल नहीं होती है लेकिन यह सरकार समस्याओं से दूर भाग रही है। चेयरमैन साहब, उस समय की जनता सरकार जिसमें मैं फाईनेंस मिनिस्टर था, उन समस्याओं को फेस करते हुए हमने जो टैक्स लगाये थे जैसे पैसेन्जर टैक्स बढ़ाया था और कई दूसरे टैक्स लगाए थे और हमने करीब अढ़ाई तीन करोड़ रूपए के टैक्स वापिस भी लिये थे ओर 6–7 करोड़ के टैक्स लगे रहे। चेयरमैन साहब, आज यह सरकार क्लेम करती है कि हमने फाईनेंस की पोजीशन को बचा लिया है लेकिन मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि ये ऐकर्टस तो उस समय की जनता सरकार के हैं उस सरकार के नतीजे के तौर पर यह पैसा बचा है। इस सरकार के ऐफर्टस से कोई बचत नहीं हुई है।

स्वामी आदित्यवेश: सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा जैन साहब से कहना चाहता हूं कि उस समय की जनता सरकार ने गवर्नर साहब के खर्चे के लिय 15 लाख रूपए दिये थे लेकिन अब हमारी सरकार ने उसको घटा कर 11 लाख रूपए कर दिया है।

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन सहाब, ये जो 6 प्रतिशत कटौती की बात कर रहे हैं यदि इन्होंने वाकई इस स्टेट के फाईनेंस को ठीक करना है तो मैं इनको सुझाव देता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरे इन सुझावों पर अमल करें। चेयरमैन

साहब, यह जो फिजूल खर्ची है, जैसे गवर्नर साहब का जो खर्चा है उस पर वोटिंग तो नहीं हो सकती लेकिन हमारे कांस्टीच्यूशन में यह लिखा हुआ है कि उस पर डिस्कशन हो सकती है। हमारा यह फर्ज बनता है कि स्टेट मैं अगर कोई फिजूल खर्ची हो तो हम सरकार को बतायें और इस सरकार का यह फर्ज है कि उस फिजूल खर्ची को कम करने की कोशिश करें। चेयरमैन साहब, उस समय की जनता सरकार ने गवर्नर साहब के लिए जो गेस्ट हाउस रखा था वह इसलिए रखा थ कि उस समय जो गवर्नर साहब थे वे नजदीक के रहने वाले थे इसलिए उनसे मिलने वाले ज्यादा आते थे लेकिन अब तो हमारे गवर्नर साहब महाराश्ट्र के रहने वाले हैं इनके पास तो मिलने वाले इतने नहीं आएंगे। गवर्नर साहब ने मिलने के लिऐ महाराश्ट्र से तो एक या दो आदमी ही आ सकते हैं इसलिए गवर्नर साहब के लिए इतने बड़े गेस्ट हाउस की क्या जरूरत है। चेयरमैन सहाब सरकार ने एक तो पहले ही 15 एकड़ में गवर्नर हाउस बना कर छोड़ दिया है ओर उसके बाद यह कहते हैं कि गवर्नर साहब के लिए एक और गेस्ट हाउस चाहिए तो यह बिल्कुल गलत है। चेयरमैन साहब, यह जो अब गवर्नर साहब के लिए गेस्ट हाउस छोड़ा हुआ है इसको भी किसी मिनिस्टर को दे दें यासिकी सरकारी कर्मचारी को दें दे। चेयरमैन साहब, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे उचन्ती सौदा है, तायल साहब तो बिजनैस फैमिली से हैं यह तो जरूर जानते होंगे कि उचन्ती सौदा क्या होता हैं। चेयरमैन सहाब, उचन्ति सौदा वह हेाता है कि जो सौदा करने वाले दुकानदार होते हैं वे अपनी इनकम टैक्स ओर

सेल टैक्स को बहियों में दर्ज नहीं करते हैं। वे उस सौदे का उचन्ती रखते हैं। चेयरमैन साहब, ऐसे सौदे हमारी स्टेट में अरबों रूपए के होते हैं। इस उचन्ती सौदे पर गवर्नमैंट आफ इंडिया ने वांचू कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि हमारे देश में अरबों रूपए के उचन्ती सौदे होते हैं। चेयरमैन साहब, मैं इस प्वायंट को इसलिए उठा रहा हूं कि मेरी एक्साइज एण्ड टैक्सेशन के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई थी तो उसमें भी मैंने इस प्वायंट को उठाया था तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ऐसे सौदे होते हैं। चेयरमैन साहब, ये उचन्ती सौदे कंट्रोल क्यों नहीं हो पाये? इसलिए कि महकमे के 80 से 90 प्रतिशत कर्मचारी उन दुकानदारों के साथ मिले रहे हैं जोकि इस उचन्ती सौदे को डील करते हैं। चेयरमैन साहब, आप शाम को पानीपत रेलवे स्टेशन पर चले जाईये, रोहतक चले जाईये, सोनीपत चले जाईये और गुडगांव चले जाईये आपको हजारों आदमी हजारो रूपए की कीमत का सामान दिल्ली से लाते हुए मिलेंगे और वे बिक्री टैक्स देते नही । वंहा पर टैक्स का गबन किया जाता है। इसके अलावा चेयरमैन साहब एक बात और मैं हाउस के ध्यान मे लाना चाहता हूॅ और वह यह है किइस स्टेट में 30–40 के करीब पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज है और इसमें बिजली बोर्ड को छोड कर 70 करोड रूपये के करीब लगा हुआ है और यह 70 करोड रूपया आज से नही किसी में 10 साल से, किसी मे 8 साल से और किसी मे 6 साल से लगा हुआ है। चेयरमैन साहब, उस समय की जनता सरकार जिसमें मै फाईनेस मिनिस्टर था, मैनें

अपनी बजट स्पीच में कहा था कि ये यूनिटस सिक यूनिटस बनते जा रहे है लेकिन कुछ दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि नही हमारी कोई यूनिट सिक यूनिट नही है, जबकि उनमें लाखों रूपए का घाटा है। चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चहाता हूॅ कि कोई ऐसी यूनिट जो पब्लिक सैक्टर में है उनमें किसी ने एक , दो को छोड कर मुनाफा दिया हो तो फाईनेंस मिनिस्टर साहब बैठे है, मुझे बता दे। चेयरमैन साहब, कुछ दिन के लिए मैं भी पब्लिक अन्डरटैकिंग्ज कमेटी का चेयरमैन रहा हूॅ। इस कमेटी का चैयरमैन बनते ही मेरे नोटिस में यह बात आई कि कार पोरे ांज में जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्ज होते है यह सरकार उनको बहुत जल्दी बदल देती है। किसी को एक महिने के बाद, किसी को दो महिने के बाद और किसी को चार महिने के बाद बदल दिया जाता है। चेयरमैन साहब, हमने पब्लिक अन्डर टेकिंग्ज कमेटी में युनानीमसली फैसला करके सरकार को लिखा कि जो इन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज मे चेयरमैन या मैनेंजिंग डायरैक्टर्ज बनते है उनके साथ यह खिलवाड न किया जाए उन्हे जल्दी न बदला जाए। आज बेचारा कोई मैनेजिंग डायरैक्टर चण्डीगढ मे है और हरियाणा की गरीब जनता के साथ है। चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा फाईनेंस मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूॅ कि जब उन्होने अपनी बजट स्पीच पढी तो उस समय उन्होने पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज के मामले में क्या कोई ध्यान दिया ? चेयरमैन साहब ऐसा लगता है कि उन्होने ध्यान नहीं दिया।

चेयरमैन साहब, एक दो यूनिट को छोड कर सारी यूनिटस घाटे में है।

चौधरी दे ा राजः चेयरमैन साहब, जैन साहब फरमा रहे है कि सारी की सारी यूनिटस घाटे मे जा रही है। मै इनको बताना चाहता हूॅ कि स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरे ान में पिछले साल 28 लाख रूपए का फायदा हुआ है। (थम्पिंग)

श्री मूल चन्द जैनः चेयरमैन साहब, मैनें पहले ही कहां था कि एक–आध यूनिट में एक लाख, दो लाख या चार लाख का मुनाफा हो सकता है लेकिन पब्लिक 11.00 अंडरटेकिंग्ज की ओवर–आल पिक्चर डार्क है। पिछले साल हमारी गवर्नमैंट ने फाईनैंस डिपार्टमैंट में एक इनवेस्टमैंट सेल क्रिएट किया था ताकि यह सैल पब्लिक अडंरटेकिंग्ज को देखे कि किस अंडरटेकिंग्ज में कितना भोयर कैपिटल है, कितना लोन है और वह किस तरह स चल रहे है। पिछले साल की बजट स्पीच में इस सैल का बाकायदा जिक्र है लेकिन इस बजट स्पीच में इसका बिल्कुल जिकर नही है। इस साल की बजट स्पीच में इस का जिकर होना चाहिए था जाकि पता लग सके कि पिछले साल जो कमिंया थीं उनमें कंहा तक सुधार हो पाया है और कंहा तक घाटा कम हुआ है। अगर यह सरकार इन सब बातों को ध्यान मे रखती तो 46 करोड रूपये का घाटा न होता। यह अनप्रैसिडैंटिड है। 1966 में हरियाणा प्रान्त बना । 1966 से लकर अब तक इतना बडा घाटा किसी सरकार ने नही दिखाया जितना इस सरकार ने दिखाया है। फाईनैंस

मिनिस्टर की स्पीच से जाहिर होता है कि 46 करोड का ही घाटा नहीं बल्कि इससे ज्यादा है। अगर घाटा कम करने की कोि ा ा करते तो यह घाटा कम हो सकता था। इतनी बडी वजारत बना रखी है। इसको कम करो, गवर्नर हाउस के खर्चे को कम करों, पब्लिक अंडरटेकिंग्ज को कट्रोंल करो, तब घाटा कम हो सकता है।

चेयरमैन साहब, अब मैं बेरोजगारी के सिलसिले में कहना चाहता हूॅ । कुछ आकडे पिछली वजट स्पीच मे से और कुछ इस बजट स्पीच में से लेकर कह रहा हूॅ। 1978 के माली साल में 2 लाख 26 हजार नौजवानो ने एम्पलायमैंट एक्सचेजिंज में रोजगार के लिए नाम रजिस्टर करवाये जिन में से 36,533 नौजवाना को रोजगार मिला। अगर साल नवम्बर 1979 तक 2 लाख 7 हजार नौजवानों ने नाम रजिस्टर करवाये और 33,996 नौजवानों को रोजगार मिला है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की वजारत का बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ध्यान नहीं । जितने नौजवान रजिस्टर हुए उन में से 16 परसैंट लडकों को रोजगार मिला और 84 परसैंट बेरोजगार घूम रहे है। हर साल स्कूलों और कालेजो से लडके अपनी एजुके ान पूरी करके निकलते है। किसी देहात से 80 लडके, किसी से 100 लडके निकलतें है। अगर इसी तरह से बेरोजगारों की तादाद बढती रही तो क्या इस स्टेट मे बैचनी नहीं बढेगी, नौ–जवानो में अ ाान्ति नहीं बढेगी? अगर यह अ ाान्ति बढं गई तों ला एंड आर्डर कैसे कट्रोल होगी? चेयरमैन

साहब, मुझे बडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि देहाती और गरीब नौजवाना बसते है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? चेयरमैन साहब, मुझे बडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि देहाती और गरीब नौजवानों के लिए खादी बोर्ड में 20–30 लाख रूपया डिस्ट्रिब्यूट देहाती और गरीब नौजवानों अपना काम–धन्धा चला सके, लेकिन जब से यह सरकार आई है, इसने खादी बोर्ड का मलियामेट करके रख दिया है। इसका नजीता यह हुआ कि हाउस में एस सवाल के जवाब मे चीफ मिनिस्टर को यह मानना पडा कि इस साल केवल 2 लाख रूपया डिस्ट्रिब्यूट हुआ है और बाकी 20–22 लाख की रकम वैसे ही पडी हुई है। सी0एम0 साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि वे कोि ा ा करेगें कि यह रूपया 31 मार्च तक तकसीम हो जाए। चेयरमैन साहब, इस कोि ा ा का क्या नतीजा होगा, मै चाहूगा कि फाईनैस मिनिस्टर साहब इसके बारे मे बतायेगं। मै इनसे यह भी जानना चाहूंगा कि बोर्ड को क्यां मलियामेट किया और जो रकम गरीब लोगो में तकसीम हो सकती थी, वह क्यो नही हुई ? चेयरमैन साहब , मै देहाती दस्तकारी के बारे में दोबारा जिक नही करूगां क्योंकि मै पहले ही इस पर बोल चुका हुं। मै इतना ही कहूगां कि जो स्कीम इस हाउस ने पिछले साल या इससे पहले पास की है,उनको मेहरबानी करके न बदले। हरियाणा के लखपति या करोडपति दस दस लाख रूप्या सबसिडी के नाम पर ले गये थे। फाइनैस मिनिस्टर ने इस बजट स्पीच में खूद कहा कि 20–25 पूजिपतियों को 66 लाख रूप्या मुफत दे दिया लेकिन इसके मुकाबले में दो

हजार देहाती नौजवानो को , जिन्होने देहात में 1900 इंडस्ट्रियल युनिटस लगाने की हिम्मत ही है, उनको सरकार ने कुल मिलाकर पिछले दो वर्शो मेंं तीन चार लाख रूप्या दिया है, इससे ज्यादा बूरी बात इस सरकार के लिए और क्या हो सकती है? मै चीफ मिनिस्टर साहब से कहूगां कि इस पालिसी को बदले और करोडपतियो को इतना पैसा न देकर गरीब देहातियो मे ज्यादा से ज्यादा रूप्या बांटे । आपके हाथ मे जो पावर है उसका सही इस्तेमाल करे। मैं लोक दल की तरफ से आपको यकीन दिलाता हुं , डा0 मंगल सैन भाायद मुझे इस बात की इजाजत न दें, अगर आप धनरा ि ा का वितरण न्यायपूर्ण करेंगे तो लोकदल आपको सैन्ट–पर–सैन्ट सहयोग देगा। अगली बात , चेयरमेन साहब , पे–कमी ान के बारे में कहना चाहता हूं । इस हाउस में यह नही बताया गया कि वर्क–चार्ज्ड के पे–स्केल्ज के बारे मे क्या फैसला किया है। क्लास थ्री और फोर के बारे मे तो फैसला कर लिया लेकिन वर्क–चार्ज्ड को छोड दिया गया है जो सबसे ज्यादा गरीब तबका है और जिनकी तादाद हमारे प्रान्त में लगभग 25 हजार है। आज वर्क–चार्ज्ड ऐम्पलाईज असैम्बली प्रिमिसिज के बाहर हडताल पर बैठे है। इनके पे–स्केल का मामला पहले भी किसी पे–कमी ान ने टेक–अप नही किया। एज ए फाइनैंस मिनिस्टर जब मेरे सामने वर्क–चार्ज्ड की पे का मामला आया तो मैने इस पर गौर किया था। 1968 मे जो पे–कमी ान बना था उसने भी इसके पे–स्केल पर विचार नहीं किया, यानि उसने भी इनको नजरअन्दाज कर दिया। 1970–71 से काग्रेस सरकार के जमाने से ये

वर्क–चार्ज्ड पिछे लगे रहे लेकिन इनकी तन्खाह नही बढ सकी। पिछले पे–कमी ानों ने सब कैटेगरीज की तन्खाह बढाई लेकिन वर्क–चार्ज्ड के केस को टच नही किया। ये कर्मचारी भी दूसरे कर्मचारियों की तरह है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि वे कर्मचारी जो गरीब है, ि ाडयूल्ड कास्टस से है उनको क्यों इग्नौर किया यह सबसे ज्यादा पूअर क्लास है, इसकी दुर्द ाा न करे और इनकी तन्खाहें भी दूसरे कर्मचारियों की तरह बढनी चाहिंए। जंहा 15–16 करोड रूपये का खर्चा बढा है वहां इनकी तन्खाह बढने से एक आध करोड और हो जाएगा, क्या फर्क पडता है, हमें इसमें कोई एतराज नहीं होगा। फाईनैस मिनिस्टर हिम्मत करें, हम उनका साथ देगें। चेयरमैन साहब, इसके साथ ही साथ मै एक और बात कहना चाहता हूॅ। गजेटिड आफिसर्ज का जंहा तक सवाल है, मुझ अफसोस है कि टक्नोकटस एच0सी0एस0 और आई0ए0एस0 आफिसर्ज का आपस मे मतभेद है, इनके मनमुटाव है। 1969 में पिछले पे–कमी ान ने जो फैसला किया था उसने एच0सी0एस0 आॅफिसर्ज , इंजिनियर्ज और डाक्टर्ज के पे स्केल में इक्वे ान कायम की थी । जो टौप के स्टुडैन्टस होते है , उन में से कूछ इंजिनियरिंग कालेज मैं चले जाते है और कुछ मैडिकल कालेज में चले जाते हैं और जो बाकी बचते है , वे एच0 सी0 एस0 या आई0 ए0 एस0 के कम्पीट ान मे बैठते है। ये चाहे कुछ भी बने लेकिन ये सब एक ही लेवल के होते है, एक ही कैटेगरी मे फाल करते है। अगर इनके पे स्केल का फैसला करते समय भेदभाव से काम लिया गया तो मै समझता हूं कि ठीक नही

होगा । टैकनोकेटस जो डोक्टर है, इंजिनियर्ज है, उनके पे–स्केल एच0सी0एस0 के पे–स्केल से कम रखे जाये तो मै समझता हूॅ कि टैकनोटेकस के साथ बडा भारी अन्याये होगा। इससे टैकनोटेकस मे बडी बेचनी फैली हुई है। मेरी प्रार्थना है कि इसी हाउस मे फाईनैस साहब, जवाब देते समय एलान करे की इस तरह का भेद भाव किसी के साथ न होगा। चैयरमैन साहब, यह बात ठीक नही है कि एच0सी0एस0 को तो 1200–1500 का भी ग्रेड भी दे दें, सिलेक ान ग्रेड भी दे दे, लेकिन एस0डी0ओ0 की भी तन्खवाह कम कर दे। (विघ्न) मुझै पता लगा है कि सहगल साहब, जो पे–कमी ान के सैकेटरी थे, ने उनकी तन्खवाह और भी घटा दी है। उनके लिये सिलैक ान ग्रेड भी नहीं रखा है। और रिपोर्ट से उन्होने यह सबूत दिया है कि उच0सी0एस0 और टैक्नोकैटस के बीच में डिसकिमिने ान की जाती है। मुझै वि वास हैकि सकेटरीज की जो कमेटी मुकर्रर की गई है वह इस पिजुडिस से उपर उठेगी और यह सरकार आखिरी फैसला करते वक्त उन टैक्नोकेटस के साथ इन्साफ करेगी।

चेयरमैन साहब, इसप्रकार की प्रो–रिच पालिसी के बारे मे मैने काफी कुछ कह दिया है लेकिन दो बाते और हाउस के नोटिस में लाए बगैर मै नहीं रह सकता। चेयरमैन साहब, आप यमुनानगर के पास वाले इलाके सेएम0एल0ए0 बन कर आए और आप जानते है कि यमुनानगर और दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज में कुछ बडे–2 कारखानेदारों ने लोगेाका जीना मु कल कर दिया है

उनके कारखानो से जो आउट फलो निकलता है, गन्धा पानी निकलता है वह ऐटमासफियर को पौल्यूट कररहाहै। इसके बारे मे एक कानून बना हुआ है।, पल्बिक हैल्थ डिपार्टमैंट के मातहत एक बोर्ड एक बोर्ड भी बना हुआ है लेकिन इस तरह कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। चेयरमैन साहब, आप हैरान होगे कि रिपीटडेली सवाल पूछने के बावजूद , सित्मबर के सै ान में मैनें सवाल भेजा और अब भी एक सवाल भेजा, उस बोर्ड ने जिसका काम पौल्यू ान का कंट्रोल करना है, एक भी कारखानेदार का चालान नहीं किया। अगर किया है तो फाइनैंस मिनिस्टर साहब बताएं। बोर्ड ने लिखा है कि पौल्यू ान हो रहा है। फिर भी ऐक्ा ान नहीं लेते। मै उस रिपोर्ट को यंहा नही लाया लेकिन यह फैक्ट है कि सैंकडो कारखाने ऐटमासफियर को गन्दा कर रहे है। (विघ्य)

चेयरमैन साहब, इस सरकार की जो अब काग्रे ा (आई) की सरकार बन गई है, वीकर सैक्ा ंज की दुहाई देने की एक आदत बन गई है लेकिन मै फाइनैंस मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूॅ बाकी मिनस्टिर्ज भी बैठे ह, वे भी इस बात को नोट कर लें, कि हरिजन चौपालों के लिए इनहेनें कितना पैसा दिया है? हरिजन चौपाल के लिये हमने 96 लाख रूपया रखा है। मैने सोचा कि हमने जो स्कीम चलाई थी, यह भी उसे चला रहे है, यह अच्छी बात है लेकिन इनका जो ऐक्सप्लेनेटरी मैमोरैन्डम है उसमें सिर्फ 25 लाख रूपये हरिजन चौपाल के लिय रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि इनकी बजट स्पीच ओर ऐक्सप्लेनेटरी मैमोरैन्डम् में

फर्क है। मुझै आ ाा है कि फाईनैंस मिनिस्टर साहब इसकी जरूर व्याख्या करेगें।

चेयरमैन साहब, मैनें तफसील से आंकडे लिखे हुए है लेकिन आर्ठम की कमी की वजह से मै दे नही सकता परन्तु उनसे यह जारिह है कि रूरल डिवैल्पमैंट के कामों की तरफ इन्होने बहुत कम ध्शान दिया है। मिसाल के मौर पर डैरी डिवैल्पमैंट को आप लीजिए। हमने 1500 देहीती नौजवानों के लिए 50 लाख रूपया प्रोवाइड किया था लेकिन इस साल इन्होने उस 50 लाख से घटा कर 39 लाख कर दिया है। हमने 1500 तालीमयाफता नौजवाना को कहा थ कि गाय लो, भैंस लो और दूध पेदा करके बेचों तथा अपना रोजगार चलाओं लेकिन ये कहते है कि दो सौ नौजवानो को लोन देगें। यह है इनकी रोजगार दिलाने की अचीवमैंट । उन बेरोजगार नौजवानो के लिए जिसकी सख्ंया दिन प्रति दिन बढती जा रही है। (विध्न)

चैयरमैन साहब , एक बात मै तालीम के बारे में भी कहना चाहता हूॅ। ऐजुके ान किसी भी दे ा को बिल्ड करने का एक महत्वपूर्ण जरिया होता है। लेकिन इस क्षेत्र में ये क्या कर रहे है? आज टीचर्ज बडी मु कल में है। हमारी सरकार ने, चौधरी देवी लाल की सरकार ने प्राईवेट स्कूल्ज और कालेजिज को 75 परसैन्ट ग्रान्ट दी थी। 30 मई 1979 को हमारी एक मींटिंग हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 75 परसैन्टस ग्रान्ट को पिछले साल की आमदनी न समझा लाए लेकिन उस फैसले के

बावजूद आज की सरकार उस 75 परसैन्ट की ग्रान्ट को पिछले साल की आमदनी समझने पर तुली हुई है। इसका नजीता यह होता है कि घाटे का घाटा बना रहता है। जब एक हायर लैवज पर, जिसमें फाईनैंन्स मिनिस्टर थे ऐलके ान मिनिस्टर थे, सैकेटरी थे, एक फैसला हो लिया, फिर वही बात की जाए तो ठीक नहीं है।

नैनिक और स्प्रिचुअल ऐजुके ान के बारे मे, चेयरमैन साहब, हमारे कोर्सिज में कुछ नहीं हैं न प्राईमरी स्कूल में है, न मिल स्कूल मे है, न हाई स्कूल मे है और न कालेजिज में है। नतीजा क्या है? स्कूल एण्ड कालेज से निकल कर हमारे लडके और लडकिंया सीनिक बन रहे है। क्योकि उनका कोई आधार नही है। हाउस मे बारबार सवाल पूछने के बावजूद भी इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है जबकि सभी धर्मो के मु तरका विचारो की कोई किताब स्कूलो मे बडी आसानी से लगाई जा सकती है। तों मै इस गवर्नमैट से कहूंगा कि वह इस मामले पर विचार करे, तब जाकर हम नोजवानां को सही किस्म की तालीम देगें औश्र वे अच्छी प्रकार से हरियाणा तथा दे ा की सेवा करेगें। (विघन)

चेयरमैन साहब, एक बात और कह कर मै अपना भाशण खत्म कर दूंगा । वह बात भी वीकर सैक ान के बोर में है । हरिजन कल्याण निगम सन 1970–71 में बनाया गया था। उस निगम को बने आज कोई 9–10 वर्श हो गये है लेकिन मै आपको बताना चाहता हूॅ कि इन 9–10 वर्शो मे चार हजार से ज्यादा

आदमिंयों को इससे कर्जा नहीं दिया गया और उस कर्जे की मिकदार भी एक करोड रूपये के करीब होगी। हमारे यहां 20 लाख के करीब हरिजनों की आबादी है। चेयरमैन साहब,10 वर्शो मे अगर केवल 4 हजार आदमियों को कर्जा दिया जाए तो इस हिसाब से तो सारे 3–4 लाख हरिजनो परिवारों को कर्जा देने के लिये कोई 500–700 साल चाहिंए। इससे जाहिर होता है कि से किस तरीके से वीकर सैक ान की समस्याओ को हल कर रहे है। क्या यह विदे ियों का राज है कि समस्याओं को केव टिंकरिग करते जाइए, छोडते जाइए और हल करने की कोई बात न हो? आज हिन्दुस्तान का गरीब , बेरोजगार आदमी इन समस्याओं का समाधान चाहता हे। अगर इनका समाधान नहीं होगा तो सन 1977 में जो हाल आपका हुआ था वह फिर होने वाला है। इन भाब्दो के साथ में अपनी बात खत्म करता हूॅ । धन्यवाद (विघन)

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल) चेयरमैन साहब, सन 1980–81 का बजट सदन में प्रस्तुत हुआ है। आज इस बजट पर चर्चा आरम्भ हुई है। मेरे बुजुर्ग फाजिल दोस्त जैन साहब ने उस पर काफी कुछ कहा है। इस सारे बजट को पढने के प चात मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट लक्ष्यहीन , उदासीनता पुर्ण और अनबैलेन्सड बजट है । इस बजट में आम जनता को राहत देने के विशय मे कोई प्रोग्राम नही है और यह भी सच है कि लक्ष्यहीन सरकार के लिए लक्ष्यपूर्ण बजट लाना मु कल है । किसी भाायर ने ठीक ही कहा है –

जरके गौआई खामो ाी से बदलता क्यों नहीं।

मेरे आइने से यह जोहर निकलता क्यो नही।।

अब जबां खोली हमारी लजते गुफतार ने ।

फूंक डाला जब चमन को आत ो बेकार ने ।।

(तालियां)

चेयरमैन साहब , परे ाानी हमारी भी है परे ाानी सरकार के सामने भी है। आज जिस सरकार को अपनी कूर्सी बचाने की फिक्र पडी हुई हो वह इतने थोडे अर्से में आम जनता की भालई के बारे में क्या सोच सकती है। इस बारे में मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहता । यह तो इनकी अपनी जमीर का सौदा है। मुझै भारत के इतिहास का पुराना वाक्य याद आ गया, वह हाउस में सुना दूॅ।

श्री सभापतिः बेहतर तो यही रेगा कि आप बजट पर ही बोलें। आपका अपना टाईम जाया होगा।

चौधरी राम लाल वधवाः सभपति जी मैनें ऐसे फैक्टस लिखे है कि मै टाईम से पहले ही खत्म कर दूगा लेकिन इस ऐतिहासिक घटना को बताना बहुत जरूरी है । दिल्ली का भाान जब कमजोर हो गया ओर आपस मे फुट पड गई तो उस वक्त चगंजखां ताना ाही ने दिल्ली पर हमला करके उसको कब्ज में ले लिया। जब वह दरबार लगा कर वहा बैठा तो उसने दिल्ली

के बाद ाह की सारी रानिंया को बुलाया। सारी रानिंयों चगंजखां के सामने पे ा हुईं। उसने कहां कि आप सारी मेरे सामने अपने कपडे उतार दो। पहले तो रानियों ने सकोच किया लेकिन जब दूसरी बार धमकी दी तो उन्होने अपने ओरिजनल कपडे उतार दिये । उस वक्त चगेंजखा ने एक सवाल पूछा कि आप अपने महाराज की इतनी वफादार रानिंया होने के बावजूद भी एक धमकी मे कपडे उतारना भुरू कर रही हो तो तुम्हारी वफादरी बाद ाह के प्रति क्या हुई। उन रानियों ने जवाब दिया कि हमें तो अपनी सुख–सुविधा से मतलब है। हमें किसी की लायलटी से कोई मतलब नही है। इसलिऐं दे ा के इतिहास मे हमारे मुख्य मन्त्री चौधरी भजन लाल जी ने एक नया इतिहास जोडा है। मैं समझता हूॅ कि हरियाणा में आने वाली नसलें सिर झुकाया करेगीं।

श्री सभापति : आप बजट पर ही बोलिए।

चौधरी राम लाल वधवाः चेयरमैन साहब, मै इस बजट पर क्या बोलूं, यह बजट ही ऐसा है और जिसने यह बजट बनाया है वह सरकार भी ऐसी ही है। चेयरमैन साहब मै वितमन्त्री जी से एक बात कहना चाहूॅगा कि–

जरा देख इसको जो कुछ हो रहा , होने वाला है।

धरा क्या भला अहरे कहन की दास्तानों में ।।

इस सरकार ने जनता पार्टी की बजट स्पीच को छाल दिया है और कुछ नहीं किया है। (ोर) चेयरमैन साहब बजट का क्या मकसद होता है? बजट का मकसद हेाता है कि जो गरीब जनता की जेब से टैक्स के द्वारा पैसा लिया जाये उसका ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाये, उसके द्वारा लोगो की आर्थिक अवस्था को सुशार जाये परन्तु यह बजट इस सम्बन्ध में बिल्कुल खामो ा है। चेयरमैन साहब टाईम मेरे पास थोडा है वरना मै इस बजट स्पीच के बारे मे डिटेल मे बताता लेकिन फिर भी मैनें इस स्पीच को पढने के प चात दो हिस्सों कमें बाटा है अब तो मै आपके सामने मोटे मोटे प्वांयटस पर ही रो ानी डालना चाहूगा। एक तो यह है कि इनको किसर सिद्वान्त को ले कर आना चाहिए था। लोकतन्त्र का ढांचा पार्टी द्वारा ही स्वास्थ किया जा सकता है। मजबूत किया जा सकता है। पार्टी के अपने सि्द्धान्त अपनी विचारधारा और आद र्ा ही जनता की समस्याओं का समाधान कर सकते है। लेकिन जिस सरकार के अपने कोई लक्ष्य न हों, पार्टी के प्रति लायलटी न हों, केवल यही लक्ष्य हो कि अढाई याल के लिये असैम्बली को किस तरह से बचाया जा सकता है। अढाईसाल कैसे मैम्बरी कायम रखी जा सकती है, वे लोग जनता को समस्याओं को कैसें समझेंगें। मै तो यहीं कहूगां। कि भले ही आज असैम्बली डिजाल्व कर दे और चुनाब करायें । फिर चुनाव के बाद उनके सामने कोई लक्ष्य और सिद्धान्त है तो उसके द्वारा बजट पेरू करे।

चेयरमैन साहब, मै अभी कह रहा था कि मैने बजट को दो हिस्सों में बाटा है एक तो य हहै कि पिछले जनता राज की क्या–2 उपलब्धिया है और दूसरा हिस्सा है कि मौजूदा सरकार ने जो लक्ष्यहीन बजट हामरे सामने पे ा किया है। चेयरमैन साहब मैनें इस सार बजट स्पीच और एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम को सन 1977 से लकेर 1980–81 तक पढा है। जनता सरकार ने अपने दो साल के रात मे जो सामुदायिक और अमली कार्य किये है भाायद सन 1966 से 1976 तक हरियाणा में काग्रेस पार्टी की सरकार ने न किये हों मै मोटी मोटी उपलब्धियां हाउस के सामने रखना चाहता हूॅ। सबसे पहले तो जनता सरकार ने रा ान की दुकानो को समाप्त किया था। जो लोग तीस साल से लाईन जगा कर खडै होते थे उनकी लाईन ही खत कर दी थी। सारी ओपन मिलने लगी थी।

चेयरमैन साहब, बाजार में चीजो काभावा इतना कम हुआ जिसके बारे मे कुछ नहीं कहा जा सकता । मै यहां चीनी का उदाहरण देना चाहता हूॅ। जनता रात मे अढाई रूपये के हिसाब से चीनी बजार मे खुली बिकती थी। बाजार मे दुकानो आवाजे लगाते थे, ढैर के ढैर पडै रहते थे लेकिन आज काग्रेस पार्टी के राज मे चीनी का भावा सात रूपये किलो हो चुका है।

जनता पार्टी की सरकार ने फल्डज को रोकने का काम हरियाणा में सब से पहले भाुरू किया, इस सरकार के आने से पहले किसी सरकार ने उस तरफ को ध्यान नही दिया। जब

हरियाणा में ुल्ड आये तो जनता को हर सुविधा दी गई । भाायद हिन्दुस्तान की तारीख में इतनी सुविधयें किसी भी सरकार ने दी हो।

चौधरी राम लाल वधवा : मै जल्दी ही पांच मिनट में खत्म कर रहा हूं । चेयरमैन साहब मै कह रहा था कि हमने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अमली कदम उठाये । हमारी सरकार ने रुरल इंडस्ट्रीलाईजे ान स्कीम को चालु किया । जैसा कि बाबु मुल चन्द जैन ने विस्तार में पहले ही वर्णन कर दिया है। इसलिए मै इस विशय में ज्यादा कुछ नही कहना चाहूगां । गांवो की बेहतरी और बहबुदी के लिए हमारी जनता सरकार ने मैचिंग ग्रान्टस को चालु किया और इसी प्रकार से गांवो की बहबुदी के लिए फुड फार वर्क का कार्यक्रम भी चालु किया जिससे गांवो के देहाती भाईयो केा काम के बदले अनाज उपलब्ध हो सके । किसानो को टैक्स के अन्दर राहत दी गई जिसका उल्लेख इन्होने इसी बजट स्पीच मे किया है। भाहरो में , हरिजनों और दीगर गरीब लोगो के लिए राहत दी गई । हाउस के टैक्स की माफी 120 रूप्ये से बढा कर 600 रूप्ये की गई और इस प्रकार से काफी गरीब लौगो को हाउस टैक्स में राहत मिली । भाहरो में जो लोग हरा चारा लाते थे उन पर जो महसुल लगता था उसको खत्म करके हमने गरीब किसानो को राहत दी। जो लोग ाहरो में गाय और भैंस रखते थे उन पर 10 रूप्ये और पांच रूप्ये टैक्स लगा हुआ था उसको हमने समाप्त किया जिससे काफी गरीब

व्यक्तियो को राहत मिली । इसी प्रकार से हमारी सरकार ने टांगे वालो पर , रेहडी वालो पर , तथा रिक ाा वालो पर एमरजैन्सी के दोरान जो 60–70 रूप्यें फीस लगी हुई थी उसकी वापस ले कर गरीब आदमियों को राहत प्रदान की । हमारी जनता सरकार टोटल प्रोहिबि ान का प्रस्ताव लाई थी और इस प्रस्ताव को अमली भाकल दी गई थी लेकिन मुझे दुख है कि जब हमारे वित मन्त्री श्री बलवन्त राय तायल यह बजट पढ रहे थे तो मुझे आपातकालीन के समय जब हम दोनो जेल मे थै , उस समय की बात याद आ जाती है। जब मैं अण्डा खाने लगता था तो तायल साहब मुझसे घृणा करते थे क्योकि वे गांधी वादी विचारधारा के है लेकिन उन्होने अब भाराब की पालिसी का समर्थन किया है। जो विता मन्त्री गांधी वादी हो और टोटल प्रोहिबि ान के हक मे रहे हो, मोरार जी भाई का फालोअर रहे हो और इस प्रोहिबि ान को एक साल मे खत्म करने के हक में रहे हो आज वही इस प्रोहिबि ान पालिसी का समर्थन करने जा रहे हो यह कितने दु:ख की बात है।

हमने हाउसिगं बोर्ड के लिए 10 हजार मकान बनाए और हुडा ने जो प्लाट एलाट किए हैै वे इनसे अलग है। हमने बांध बधवाए और खाल पक्के करने के लिए स्कीम चालु की जिससे बेरोजगारी कम हुई और देहाती लोगो का फायदा हुआ। चेयरमैन साहब लोकतात्रिक ढांचे को मजबुत करने के लिए जो सबसे अच्छी पालिसी अपनाई थी वह यह थी कि सत्ता का

केन्द्रीयकरण खत्म किया जाये और सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया जाये हमने यह भी फैसला किया था कि सत्ता को पंचायत के लेवल तक ले जायेंगे । हमारी जनता सरकार ने जिला परिशदो , मार्किट कमेटियो , मार्किटगं बोर्ड मे चुनाव की पद्धति को फिर से लागु किया । चौधरी बिरेन्द्र सिह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । माननीय सदस्य 1980 के बजट पर बोल रहे है या 1979 के बजट पर बोल रहे है।

चौधरी राम लाल वधवा : हमने पंचायतो के चुनाव करवाए और म्युनिसपल कमेटियो के चुनाव कराने के लिए तिथि मुकर्रर कर रखी थी , परन्तु इस सरकार ने म्युनिसिपल कमेटियो के चूनाव की तिथियो को आगे कर दिया है। हमारी सरकार ने एडल्ट एजूके ान स्कीम को चालु किया । बडी–बडी इन्डीस्ट्रीज की बजाय स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया गया । इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्डस्ट्री सेन्टर खोले । जहां तक प्लानिंग का ताल्लुक है यह हरियाणा की पहली जनता सरकार थी जिसने प्लानिंग कमी ान से 42 परसैन्ट इन्क्रीज ली थी जिसके कारण सारी स्टेट को राहत मिली । हमारी सरकार द्वारा किसानो को टैक्सो से राहत प्रदान की गई । जनता सरकार द्वारा जिन किसानो की फसलो को नुकसान होता था उनको मुआवजा देने की स्कीम चालु की गई । बैकवर्ड क्लासिज को 3 परसैन्ट की रिजर्ववे ान की घोशणा की गई थी। बालमिकियो को 50 रू0 तक तनख्वाह मे राहत प्रदान की । 191 प्राईमारी स्कूलो को मिडल

स्कूलो में अपग्रेड किया गया और 158 मिडल स्कूलो को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है। हमारी सरकार ने प्रोपटी टैक्स को समाप्त किया । सरकार ने हरिजनो की चौपालो के लिए एक कार्यक्रम भुरू किया । दो साल की अवधि में जो जनता सरकार ने काम किया है वह कांग्रेस सरकार नै 30 साल मे भी नही किया । चेयरमैन साहब इस मौजुदा सरकार ने जो बजट पे ा किया है उसके 48 पेज पर जो इनकी तकरीर है उससे कोई आ ाा नही मिलती है ? इस सरकार ने आने के वाले साल के लिए कोई नई योजना या नई राहत के लिए कोई आंकडे नही दिए । यदि कुछ दिया है तो वह केवल लोकतांत्रिक ढांचे को, प्रजातांत्रिक ढांचे को फिर से ताना ाही में बदलने की कोि ा ा की है। चुनाव पद्धति को समाप्त कर दिया है और जाति पाति का दौर फिर से भुरू किया जा रहा है।

लोगो को फिर से रा ान के लिए लाईन मे खडा कर दिया है। फिर भी लोगो को पुरी चीजे उपलब्ध नही हो पा रही है । मार्किट मे आव यक चीजो का दिन प्रतिदिन अभाव बढता जा रहा है। चीजो के दाम आसमान को छु रहे है । चीनी , दाल ,घी , तथा नमक जैसी दुसरी चीजें भी इन दो महिनो के अन्दर आसमान को छुती जा रही है। डीजल और बिजली की कमी का तो जिक्र क्या करना है , इस बारे में हाउस मे पहले ही कई बार काफी कहा जा चुका है और मन्त्री महोदय ने भी इस बात को माना है। रूरल इन्डस्ट्रीलाईजे ान का जो सिस्टम हमने चालू

किया था उसमें हरिजनेा को सबसे पहले स्थान दिया था आज उसको बदल कर इस सारे बजट के अन्दर हरिजनेा के लिए कोई भी सविधा प्रदान नही की है । ला एण्ड आर्डर की जो बुरी हालत इस प्रदे ा के अन्दर है उसके बारे में तो कुछ कहना ही नही चाहिए । 15 करोड रू0 ज्यादा इस बजट के अन्दर पुलिस पर खर्च किए जाने का अनुमान है। ला एण्ड आर्डर की हालत बहुत बुरी है। चौधरी वास , खानपूर , हांसी , करनाल , अम्बाला जैसे स्थानो पर जो वाक्यात हुए हैं व बडे भार्मनाक है। इस सरकार के समय जो हरिजनो पर जुल्म बढ रहे है वे किसी से भी छिपे नही है। आप इसके बारे मे ट्रब्यून और इण्डियन एक्सप्रैस के आर्टिकल पढ सकते है। हरिजनो के साथ जो जुल्म इस समय हो रहे है ऐसी मि ाल पिछले 20 सालो मे भी नही मिलती। हरिजनो की झोपडियो को जला दिया गया। रिवाडी के अन्दर वकीलो के साथ जो व्यवहार किया गया ऐसी भी मिसाल किसी स्टेट के अन्दर नही मिलेगी । इस सरकार ने बजट के अन्दर जो घाटा दिखाया है , आज तक यह घाटा 31 करोड रू0 तक का दिखाया है जबकि यह घाटा 50 करोड रू0 तक पंहूचने का अनुमान है। इस बजट के मुताबिक दो ही बाते होगी या तो हरियाणा की जनता को बडे भारी टैक्सो के लिए तैयार रहना चाहिए या फिर डिवैल्पमैन्ट के जो कार्य पुरे किए जाने है वे पुरे नही किए जायेंगे । यह बजट बडा दुर्भाग्य पूर्ण है। (घन्टी) चेंयरमैन साहब मै एक ही मिनट मे खत्म करता हूं। सभापति जी, बजट की ओवरआल पोजी ान यह है कि 1977–78 में जनता सरकार ने आते ही 90

करोड से ज्यादा की बढोतरी की और 1979–80 मे जनता सरकार ने 100 करोड के लगभग बढोतरी की लेकिन इस सरकार ने 1980–81 के बजट मे 50 करोड रू0 की बढोतरी दिखाई है जो कि गलत है।(व्यधान एवं भाोर)

श्री सभापति : आप जल्दी खत्म करे।

चौधरी राम लाल वधवा : इस बजट के अन्दर बिजली की कमी को पुरा करने के बारे में कोई भी जिक्र नही किया गया है और न ही अन – एम्लायमेंट की समस्या को साल्व करने के बारे में कुछ भी जिक्र किया गया है। एजुके ान के बारे में कुछ जिक्र नही है और न ही ट्रान्सपोर्ट के बारे में कुछ जिक्र नही किया गया है । चेयरमैन साहब , अन्त मे मै करनाल की कुछ डिमान्डज के बारे मे कहना चाहता हुं और करनाल की डिवैल्पमैन्ट के बारे मे कुछ सुजे ान देना चाहता हुं । चेयरमैन साहब , करनाल को काफी दिनो से इग्नौर किया जा रहा है। यहां पर अस्पताल की बिल्डिंग बनाये जाने के बारे मे मुख्य मन्त्री जी ने घोशणा की थी लेकिन उसके बारे में भी बजट के अन्दर कोई प्रोविजन नही किया गया । इसी प्रकार से करनाल जिले के अन्दर करनाल में गवर्नमैंट कालेज बनाये जाने के बारे में जो जमीन ली हुई है उसके बनाये जाने के लिए इस बजट के अन्दर पैसे का कोई प्रोविजन नही किया गया । इसी तरह से करनाल के अन्दर मिन्नी सचिवालय बनाये जाने के बारे में एलान किया गया था कि लेकिन उसके लिए भी पैसे का कोई प्रबन्ध इस बजट में नही है।

कुंजपुरा के आगें यमुना पर पुल बनाया जाना चाहिए , क्योंकि वहां पर पुल काफी दिनो से नही बन रहा है। (घन्टी) मैं आ ाा करता हुं कि सरकार मेरी बातो की ओर ध्यान देगी चेयरमैन साहब जो जन–विरोधी बजट इस हाउस में पे ा किया गया है मै इससे सहमत नही हुं । मैं सदन से यह भी आ ाा करूंगा कि इस बजट को स्वीकार न करे ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई) : चेयरमैन साहब, आज जो बजट हमारे तायल साहब ने पे ा किया है, उसकी मिसाल सारे दे ा मे किसी जगह पर भी नहीं मिल सकती । (व्यवधान एंव भोर) बजट के पेज 6 और 7 पर ह बताया गया है कि हरियाणा का वर्श 1979–80 का अनुअल प्लान 227ण्30 करोड रूपये का था जिसे अब हमने वर्श 1980–81 के लिये 240.50 करोड का बनाया है। यी भी तब बनाया गया है जबकि एक पैसें का भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। चेयरमैनें साहब, इससे बढिया बजट और नही हो सकता। मै इस बात के लिये भी फाईनैन्स मिनिस्टर रह चुके है वह भी एक किसान के बेटे है। (व्यवधान एव भाोर) लेकिन उन्होने भी किसानों को बख्भाा नहीं था। काग्रेस सरकार के बाद लोक दल की सरकार आयी थी। (व्यवधान व भाोर) जिसके चीफ मिनिस्टर आनरेबल चौधरी देवी लाल जी थे बे एक किसान के बेटे थे वे यह चाहते थे कि एक किसान के बेटे को प्राईम मिनिस्टर बनाया जाये चेयरमैन साहब एक किसान के बेटे की सदारत बना हुआ बजट भी ऐसा था

जिसमें किसानों के उपर टैक्स लगाये गये थे। (व्यवधान व भाोर) उन टैक्सों को हमने कहकर वापिस करवाया था। लाला बलवन्त राय तायल जोकि एक व्यपारी तबके से ताल्लुक रखते है, उन्होने इस अजट में एक नये पैसे का भी टैक्स नहीं लगाया है, इससे बेहतर बजट और क्या हो सकता है?

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर । मैरे साथी पोहलू साहब ने सारी बजट स्पीच को बढा नही है। इन्होने यह देखा है कि किसानों के लिये एक नये पैसे की राहत देने की कोई योजना भी नहीं है जबकि व्यापारियों को कोई किस्म की राहत देने की कोि ा ा की गयी है। यह उस बजट की तारीफ कर रहे है। (व्यवधान व भोर)

Mr. Chairman: This is no point of order. Please sit down.

Local Government Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed) : He will have his say on his own turn.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः चेयरमैन साहब, जैन साहब बडे पुराने सियासी लीडर है यह आजादी से पहले लडते आ रहे है। यह ज्वायंट पंजाब में भी वजीर रहे है। और सरदार सिह कैरो के वक्त में भीयह मिनिस्टर रहे हैं यही नही जैन साहब , चौधरी देवी लाल की सरकार मे भी वजीर रह चुके हैं। पांच साल तक बगैर वोट मांगे , पार्लियामैन्ट के मैम्बर भी रहे है। उन्होने अपनी सारी स्पीच मे सिवाय जली कटी बाते कहने के और कुछ नही

कहा । उन्होने एक भी ऐसी मिसाल नही दी कि मैने अपने समय मे गरीबो की भलाई के लिए यह काम किया । (व्यवधान व भाोर) तब तक जनसंघ को चैन नही आया जब तक चौधरी सतबीर सिह मलिक को मिनिस्टरी से उल्टा ले लिया गया ।

श्री सभापति : पोहलु साहब , आप बजट पर ही बोले ।

चौधरी जगजीत सिह पोहलू : चेयरमैन साहब , मैं यह कह रहा था कि तब तक इन भाइयो को चैन नही आया जब तक इन भाइयो ने एक किसान के बेटे को मिनिस्टरी से नही हटवा लिया ।(व्यवधान व भाोर)

डतण् बींपतउंद रू जीपे पे दव चवपदज व िवतकमत ण

चौधरी खुर ाीद अहमद : चेयरमैन साहब, यह एक आनेरबल मैम्बर पर एक्यूजी ान यानी चार्ज लगाया गया है जो कि अन–सबस्टैन्र ाीयेटिड है। इसलिए इसे एक्सपंज किया जाना चाहिए।

डतण् बींपतउंद रू जींज ोवनसक इम मगचनदहमकण्

चौधरी जगजीत सिह पोहलू : पिछले साल हरियाणा की बदकिस्मती यह थी कि जैन साहब फाईनैंस मिनिस्टर थे । जो पार्टी उस समय पावर में थी उसी पार्टी के एक सदस्य चौधरी सतबीर सिह मलिक ने उस बजट के को फाडा था । 10 तारीख को जो बजट हमारे तायल साहब ने पें ा किया है , अपोजि ान

की इतनी हिम्मत को जो बजट के बारे में कुछ नुक्ताचीनी कर सके । इसका मतलब यह है कि यह भी इससे खु ा थे। इससे यह भह साबित होता है कि इस बजट को यह सारा हाउस युनानी मसली पास करेगा। चेयरमैन साहब , मै सन 1967 मे राव साहब की वजारत मे एक मिनिस्टर था आज यह लोग गरीब हरिजनो के ठेकेदार बने फिरतें है, इन्होने क्या किया है, उन लोगो के लिए ? (व्यवधान व भाोर) मै आपको बताना चाहता हूं कि (इस समय सभापतियो की सुचि मे से एक सदस्य चौधरी प्रताप सिह ठाकरान पदासीन हुए ।) मै कैथल मे गया । वहां पर एक जलसे मे चंकि वर्मा साहब वाला महकमा मेरे पास था , मुझसे यह मांग की गई कि साहब दुध बहुत महंगा मिलता है। इसका भाव सस्ता किया जावे । चेयरमैन साहब , मैने उसी वक्त यह हुक्म दिया कि गर्मियो के दिनो में हलवाई लोग खोए से बनी हुई मिठाई नही बनाया करेंगे । आपसे पहले जो चेयरमैन साहब थे , वे भी उस वक्त असैम्बली के मैम्बर थे । (व्यवधान व भाोर)

चौधरी गंगा राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर , सर। अभी पोहलू साहब ने मिठाई की बात की है। मै आपके द्वारा हाउस के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि लाला बलवन्त राय तायल ने पोहलू साहब को बर्फी खिलाकर यंहा पर बोलने के लिये भेजा है। (व्यवधान व भोर)

श्री सभापतिः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है।

चौधरी जगजती सिंह पोहलू : उस राब साहब की मिनिस्टरी को 13 जनसंधियों की राम लाल वधवा जैसों की स्पोर्ट थी। इन लोगों ने राव साहब को बहुत मजबूर किया कि वह आर्डर विदड्रा कर लिया जाये। लेकिन राव साहब बडै तगडे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होने वापिस नहीं लिया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसी लाल बने। उन्होने उस आर्डर को वापिस नहीं लिया । वह आर्डर आजतक यों का यों ही कायम है। (व्यवधान व भोर) चेयरमैन साहब, अब मैं बजट के बारे में कुछ सुजे ान देना चाहता हूॅ ताकि हरियाणा की काया प्लट हो सके। चेयरमैन साहब बिजली और पानी का महकमा हमारे एक बहुत ही अच्छे आदमी के पास है। पानी हरियाणा के लिये एक जिन्दगी और मौत का सवाल है। जिस तरह से बिजली का एक के ा प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसी तरह से पानी यंहा पर लाने के लिये भी एक के ा प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। अपने आपको किसानों का हितैशी कहने वाली सरकार दो साल तक तो कुछ कर नहीं सकी। लेकिन हमारी इस सरकार को चाहिए कि चाहे वह मामला आजकल सबजुडिस है, उसे किसी न किसी तरह से हल करने की कोि ा ा करें। आप को पता है कि हरियाणा के नहरी महकमें के वजीर ऐसे है जो किसानो के बडै हमदर्द है। हम यह चाहते है कि छोटे रजबाहे तो लोग खुद खोदें, एम0एल0ए खोदें वजीर खोदें लेकिन बडी बडी नहरों का काम ठेके पर देकर करवा जायै। इससे हरियाणा का भला हो सकता है, इस में कोई दो राय नही होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, पहला मेरा सुजै ान यह है।

चेयरमैन साहब, अब मै एग्रीक्लचरल प्रोडुयुस के बारे मे कहना चाहता हूं। कई दिन से यहां पर भाोर हो रहा है कि चरनी बहुत मंहगी हो रही है, चरनी सात रूपए किलो बिक रही है। चेयरमैन साहब, मै बताना चाहता रहूं कि चीनी क्यो महंगी बिक रही है। इसका कारण यह है कि किसान को पिछले सालो मे गन्ने का भाव नही मिले रहा हैै। 1967 में जब हमारी सरकार आयी थी। उस समय हमने किसान को गन्ने का भाव 22 रूपए क्विंटल दिया था। लेकिन रयह सरकार या पिछली सरकार जो अपने आपको किसान की सरकार कहती थी, असल मे यह किसान की सरकार नही थी उसने किसान को गन्ने का भाव ठीक नही दिया। चेयरमैन साहब, लकडी का भाव आठ दस रूपये क्विंटल आप अन्दाजा लगाएं कि कौन किसान गन्नना बोएगा। किसान को दो साल तक गन्ने का भाव नही मिला इसलिये उसने गन्ना बोना ही छोड दिया। जब गन्ना ही नही बोया जाएगा तो चीनी कहां से पैदा होगी। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अगर वह चीनी की मिकदार बढाना चाहती है तो उसको भाूगर मिल और बढाने चाहिए। औ़र सरकार को गन्ने पैदावार बढानी पडेगी। गन्ने की पैदावार तभी बढेगी जब किसान को गन्ने की पूरी कीमत मिलेगी । आज किसान की हालत बहुत दयनीय हो गई है। आज किसान के लडके लडकियां बहुएं और घर के दुसरे मैम्बर दिन रात खेत मैं काम करते है लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजुद उसको पूरा भाव नही मिलता है। किसान से हमदर्दी रखने वाला राज 1967 में आया था । उस पर मकई , जौ, बाजरा और ज्वार इन सारी

चीजों के उस सरकार ने ठाट करा दिए थे। उस सरकार ने गरीबी को आठ आने किलो आठा दिया था। उस टाईम हमारी सरकार थी और हमने हरियाणा का बेडा पार कर दिया था।

चेयरमैन साहब अब मै प ा पालन के बारे में कहना चाहता हूॅ। यह महकमा वर्मा साहब के पास है। ये बडे सुलडे हुए आमदी है। मै वर्मा जी को एक सुजे ान देना चाहता हूॅ कि हिसार से बढिया सांड लाकर हरके गाांव में एक–एक साडं छोडना चाहिए जिससे कि हमारे प ाुओं की नस्ल बढिया हो। चेयरमैन साहब, इडंस्ट्रीज का जो महकमा है उसके द्वारा सरकार बेरोजगारी को दूर करने की काफी कोि ा ा कर रही है। मै कहना चाहता हूॅ कि केवल इससे ही बेरोजगारी दूर नही होगी। मै चाहूंगा कि जो मोम का कोटा है वह और देते रहे है। अब आप उसको गांव में भेज दो और गांव में जो हरिजन है या दुसरे गरीब लोग है उनको यह मोम का कोटा दिया जाना चाहिंए। दो–तीन साल तक गांव के लोगों को मोम का कोटा दे दो इससे आपकी बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी।

चेयरमैन साहब, अब मै ऐजुके ान के बारे मे कहना चाहता हूॅ। पिछली सरकार ने जिसमें आर्य ऐजुके ान मिनिस्टर थे, कैथल के प्राईमरी स्कूल को हाई स्कूल बनाया था। इन्होने यह बहुत अच्छा काम किया था। चेयरमैन साहब, दूसरे हल्को में पन्द्रह पन्द्रह स्कूल अपग्रेड किए जा रहे है लेकिन मेरे हल्के पाई में सिर्फ एक स्कूल को ही प्राईमरी से हाई स्कूल को (बालक,

चन्दाना और नेनादोश) अपग्रेड करने के बारे मे एलान करके आए थे। मेरी ि ाक्षा मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि जंहा उन्होने तीन स्कूल मन्जुर किए है एक और स्कूल मुंदडी को भी अपग्रेड कर दिया जाए। चेयरमैन साहब, मै एजुके ान विभाग से एक और बात कहना चाहता हूॅ कि लडकिंयों के स्कूलों मे मास्टर नहीं रखने चाहिए। जब लडकिंयों के स्कूल अलग है जब को–ऐजुके ान नही है तो फिर लडकियों के स्कूल में मास्टर क्यों रखे जाते है। मेरी प्रार्थना है ि कवे नहीं रखे जाने चाहिए। हमारे इलाके में खरल में एक कन्या गुरूकल है यह बहुत अच्छा गुरूकल है और इसमें लडकियों को बहुत अच्छी ि ाक्षा दी जाती है। सरकार को इस गुरूकल की अधिक से अधिक मदद करी चाहिए। सरकार से मेरी एक प्रार्थना और है कि हरियाणा में लडकियों के ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाए।

चेयरमैन साहब अब मै बेरोजगारी के मसले पर बोलना चाहता हूॅ चेयरमैन साहब यह मामला ऐसा है कि जिसको न तो पिछली सरकार हल कर सकती और न ही यह सरकार कर पाएगी। आज हजारों नौजवान बेकार फिर रहे है। जब पिछली सरकार में श्री मूल चन्द जैन वित मन्त्री थे और श्री वधवा प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन थे, क्या ये बात सकते है कि इन्होने कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलवाया था? चेयरमैन साहब, मै कह सकता हूॅ कि उस वक्त भी हजारो ंपढै लिखे नौजवान बेकार फिर रहे थे लेकिन ये लोग उनके लिए कुछ नही कर सके। मै

सरकार को कहना चाहता हूॅ कि वह पढे लिखे बेरोजगार नौजवानों को बेराजगारी भता दे वरनपा बच्चों को पढाने बन्द कर दिया जाए। बेरोजगारी भता दिया जाएगा तभी यह बेरोजगारी की समस्या का हल होगी। चेयरमैन साहब, सरकार ने अपने मुलाजिमों के लिए पे–कमी ान की रोपोर्ट लागू की है, यह सरकार का बडा सराहनीय कदम है, बहुत बढिया कदम है सरकार के मुलाजिम अगर खु ा होगें तो वे अच्छी तरह से काम कर सकेगें। चेयरमैन साहब, मै एक बात और कहना चाहता हुॅ कि पुलिस में ज्यादा भर्ती की जाए। पुलिस का काम ला एंड आर्डर मैनटेन करना है। पुलिस में ज्यदा भर्ती की जाए। पुलिस का काम ला एंड आर्डर मैनटेन करना है पुलिस को मजबूत करना इसलिए भी जरूरी है कि अब कुछ पार्टीज ने सर उठाना भाुरू है। इसलिए पुलिस को मजबुत करना निहायत जरूरी है। चेयरमैन साहब सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जुडि ायल को और फैसिलिटी दी जाए । उनका पब्लिक के साथ कौंटेक्त नही रहता है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उनको बुलाकर उनकी तकलीफो ंकके बारे मे दरयाफत किया जाए और जो भकी बनकी तकलीफ है बनको दूर किया जाए जिससे कि हमारे प्रान्त की जुडि ायरी का स्टैन्डर्ड उंचा उठ सके। चेयरमैन साहब, बहुत सालों से लैड रिफार्म के बारे मे काफी भाोर हो रहा है। पार्लियामैट मे भी और असैम्बलीज में भी लैड रिफार्म का मसला काफी डिस्कस होता रहता है। पज ीं इमबवउम ं बीतवदपब कपेमेंमण प्ज ीवनसक इम मतंकपबंजमक पउउमकपंजमसलण चेयरमैन साहब, किसानो के पास जमीन नही है

जो उनसे लेने के बारे में सरकार सोच रही है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि हिन्दू सक ौन जिसमे लडकी का हिस्सा होता है, चौधरी चरण सिंह ने मन्जूर नही किया। वे लोग आपस में ही लडते रहे। मेरा कहना यह है कि हिन्दू सक ौन एक्ट मे जो हमारी असम्बलो ने अमैडमैट की है उसको मन्जूर किया जाना चाहिए। चेंयरमैन साहब, अगर सरकार गांव के लोगो की जमीन लेना चाहती है, जमीन पर सीलीग लगाना चाहती है तो जो भाहरो मे जायदाद है उस पर भी पाबन्दी लगनी चाहिए। भाहरो के अन्दर जितने कारखाने है, सिनेमा हैं, बडी–बडी आडत की दुकाने है उन पर भी पाबन्दी लगनी चाहिए। चेयरमैन साहब अगर इस दे ा में सो ालिज्म लाना है तो सरकार को मजबूत होना पडेगा और अर्बन प्रोपर्टी पर सींलिंग लगाकर एक साल के अन्दर अन्दर इस सारे पाप को काट देना पडेगा। चेयरमैंन साहब, अब मै कैथल के बारे मे कहना चाहता हॅू। वहां पर तीन–चार बिल्डिग नही है । उनको इस बजट में रखा जाना चाहिए । वहां पर तीन–चार बिल्डिग तो जरूर बनाई जानी चाहिए । एक तो वहां पर तहसील की बिल्डिग बनाई जानी चाहिए । दुसरे वहां पर सब–जेल की बिल्डिग बननी चाहिए । सब जेल की बिल्डिग नरवाना और कैथल मैं बनाने की बहुत जरूरत है। एमरजैन्सी के अन्दर जब हम जेल में थे तो वहां पर सांस लेना भी बडा मु कल था। वहां पर हवा बिल्कुल नही आती थी । इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि नरवाना और कैथल में जेल बिल्डिग अव य बननी चाहिए। तीसरे वहां पर ट्रेजरी की बिल्डिग बनाने की सख्त जरूरत है । ट्रेंजरी

की बिल्डिंग वहां पर टुटी हुई है। चेयरमैन साहब , कैथल में जो पुलिस स्टे ान है वह किराए की बिल्डिंग में है और भाहर से बाहर है। लोगो को इससे काफी परे ाानी का सामना करना पडता है। जो पुलिस स्टे ान है वह काफी छोटा है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पुलिस स्टे ान की बिल्डिंग भाहर के बीच मे बनाई जाए ताकि अच्छा इन्तजाम हो सके । चेयरमैन साहब , मेरी सरकार से प्रार्थना है यें चारो बिल्डिंग जितनी जन्दी हो सके , सरकार को बना देनी चाहिए।

चेयरमैन साहब, कैथल मे इस समय पचास बैड का अस्पताल है । कैथल काफी बडा भाहर है और आसपास के लोग भी वहां पर आते है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कैथल के पचास बैड के अस्पताल को सौ बैड का अस्पताल बनाया जाए और इसके लिए हमारे सी0 एम0 साहब भी वादा करके आए थे इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको अव य ही सौ बैड का बना दिया जाए।

चेयरमैन साहब, आज मैने तहसीलदारो को जीप देने के बारे में सवाल पुछा था और उसका जवाब दिया था कि पांच साल से अन्दर हम तहसीलदारो को जीप दे देगें । चेयरमैन साहब , मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पांच साल की मियाद को घटाकर दो साल कर दिया जाए। मेरा मतलब यह है कि तहसीलदारो को दो साल के अन्दर–अन्दर जीप सप्लाई कर दी जाए। तहसीलदारो को बहुत काम करना पडता है , उनको देहात में जाना पडता है तो उनको दुसरे महकमो से जीप मांगनी पडती है। इसलिए मेरी

सरकार से प्रार्थना है कि पांच साल की बजाए उनको दो साल के अन्दर दे दी जाए । यह ठीक है कि सरकार ने जीप देना मान तो लिया है लेकिन मेरी प्रार्थना है कि दो साल के अन्दर वे जीप दे दी जाए।

चेयरमैन साहब, हरियाणा के सिनेमा वगैरह से सरकार को काफी आमदनी होती है , मेरा यह सुझाव है कि इन सब को ने ानलईज किया जाए और उनका इन्तजाम सरकार अपने हाथ मे ले ले , इससे करोडो रू0 का स्टेट को फायदा हो सकता है और फिर हरियाणा का नक ाा ही बदल जाएगा।

चेयरमैन साहब , इससे आगें मैं ट्रान्सपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हुं कि मिनिस्टर साहब इस पर कुछ कडी निगरानी रखें , ठीक तरह से देखभाल करे ं। चेयरमैन साहब, इस डिपाटमैन्ट मे जनरल मैनजर्ज की पोस्ट भरी जाती है । जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इन पोस्टरो पर 50 परसैन्ट तो एच0 सी0 एच0 लगने चाहिएं और 50 परसैन्ट भर्ती विभाग से की जाए जो कि प्रोमो ान से होनी चाहिए। सेन्ट परसैन्ट ही एच0 सी0 एस0 ने लिए जाएं । इस धांधली को कम से कम खत्म किया जाए।

चेयरमैन साहब, इससे आगे मै एक और बात कहना चाहता हुं कि जो बसिज की बौडिज बनवाई जाति है, वह बाहर लुधियाना वगैरह से न बनवा कर अपने हरियाणा मे ही गुडगाव वगैरह में जो वर्क ााप हैं, वही से गनवाई जाए ताकि हरियाणा

स्टेट का पैसा हरियाणा में ही रहे। जिन अफसरो ने लुधियाना वगैरह से यह काम करवाने की तजवीज दी थी, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और उनका विभाग भी ठीक किया जाए। चेयरमैन साहब, इसके बाद मैं सैकेटेरिएट की हैवी एडजिनिस्टरे ान के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। और सरकार को यह रिक्वेस्ट करूगां कि उनकी तरफ भी खास तवज्जो दी जाए क्योकि वे लोग तो कभी गांवो में जाकर काम करने के हक मे नही है, और यही पर बैठे हूकम चलाते है। लोगो के काम भी काफी दिनो तक रूके रहते है। चेयरमैन साहब एक एम0 एल0 ए0 को मकान बनाने के लिये लोन देने का केस था, उस को अभी तक लटका रखा है और कई तरह की कंडी ांज लगवा दी है जैसे कि जिस का पहले कोई भी मकान होगा, उसको यह लोन नही दिया जाएगा। इसी प्रकार से और भी कई छोटे छोटे काम होते है जिन मे किसी प्रकार की कोई प्रैक्टीकल डिफीकलटी नही होती, फिर भी उन केसिज में जानबूझ कर डिले कर दी जाती है। इसलिये मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि सेक्टेरिएट लैवल पर काम जल्दी जल्दी से निपटाने का कोई तरीका निकाला जाए। यहां हरियाणा में तो दो ही छोरे काम चलाने के लिये बहुत हैं, जितने आई0 ए0 एस0 बडे बडे अफसरहैं, उन को सेन्टर में भेज दिया जाए। जब तक सरकार इस तरफ ध्यान नही देगी तब तक उसके कोई काम भी सुच0ारू रूप से नही हो सकेगे।

चेयरमैन साहब अब मैं बिल्डिग एंड रोड्ज के बारे में भी कुछेक बातें कहना चाहता हूं कि रोड्ज के मामले में पूरी तरह से निगरानी की जाए, किसी किस्म के ठेके न दिये जाए क्योकि जो 5 लाख कर काम होता है, सह बाद में 5 करोड का काम हो जाता है। और जो 50 रूपये का काम होता है। वह लाखो मे बदल जाता है। इस तरह से लाखों करोडो रूपये का गडबड घोटाला हो जाता है और गरीब किसान और मजदूर की जो मेहनत की कमाई होती है, उसका फायदा बडे बडे सरमायेदाद उठाते है। मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है ि कइस तरॅ पूरा ध्यान दिया जाए। च0यरमैन साहब, जो यह बजट इस सै ान मे प्रस्तुत किया गया है मैं इसकी पूरजोर ताईद करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू) : सभापति जी, इस सदन में माननीय वित मन्त्री महोदय ने बजट से सम्बन्धित जो अपना भाशण पढा है, उसको भाशण कहू या उसको ऐसे कहूं क्योकि सही मायनो में तो यह एक ऐसे है, जिसके उपर इस सदन में चर्चा चल रही है। इन्होने अपनी स्पीच में सरकार की काफी अचीवमैन्टस दिखाई हैं। मेरे विचार मे इसको एक दि ाहीन व्पीच कहा जा सकता है। चेयरमैन साहब, कोई भी बजट जब पे ा किया जाता है। तो उसके अन्दर पिछले साल की सरकार की उपलब्धियो और कार्यो के बारे में बताया जाता है। कि सरकार की यह यह उपलब्धियो और सरकार ने लोगो की कठिनाइयो को दूर

करने के लिये यह यह उचित कदम उठाये। चंयरमैन साहब, बाप जानते हैं कि पिछले साल बाढ से इस हरियाणा प्रान्त का कितना नुक्सान हुआ था और बसके बाद इस साल सूखा भी पडा और सरकार की तरफ से इस कभी को पूरा करने के लिये काफी प्रयास भी किये गये और इसमे अनेक प्रकार का घोटाला भी हुआ। इसके साथ साथ एक और बात की तरफ मैं सरकार का घ्यान दिलाना चाहता हूं। सरदार तारा सिंह जी यहां पर बैठे नही है भाायद उनके नोटिस मे यह बात नही है। सरकार ने चारे के लिये 20 रूप्ये प्रति क्विंठल के हिसाब से जो हाईऐस्ट टेन्डर था उसको मन्जूर किया गया जबकि 22 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लोऐस्ट टेन्डर भी था उसको किन्ही टैकनीकल ग्राउंडज पर रिलेक्ट कर दिया गया जिसकी बजह से स्टेट को कोई लगभग 40—50 लाख रूपयें का नुकसान हुआ। असके बाद 63—64 व्यापारियों ने ठेकेदारो ने आपस में मिलकर के जो परचेजिग कमेटी की भार्तो को भी ताक पर रख कर 32 रूपये के हिसाब से पेमैंट करवा दी। बाद में जब कुछ लोगो ने दरखास्त दी, उसके बाद रेट को घटा कर 32 से 27—28 रूपये पर किवंटल कर दिया गया। तब व्यापारियो ने इस फैसले के विरुद्व गुडगांव अदालत में एक केस दायर करवा दिया , वहां से मुकदमा रद्द होने पर उन्होने चण्डीगढ हाई कोर्ट में भी अपील कर दी , यह केवल इसलिए किया गया ताकि उनको कुछ टाईम मिल जाए और उनको चारे की कीमत तब तक 32 रु0 पर किंवटल के हिसाब से मिलती रहे। चेयरमैन साहब , आप खुद ही अन्दाजा लगा सकते है कि

किस तरह से यह लुट मार हो रही है और किस तरह से लोग नाजायज फायदा उठा रहे है। मेरा कहने का मतलब है कि जो टेन्डर था वह किस बिनाह पर रिजेक्ट किया गया , उसकी इंक्वायरी करवाई जानी चाहिए । क्या सरकार ने इस बारे मे भी कोई पुछताछ की कि गरीब जनता क जो पैसा था, गाढे खुन की जो कमाई थी, उसको ये व्यापारी लोग किस तरह से निगले जा रहे हैं? इसलिए मेरी आप के द्वारा सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि जो राहत किसानो को दी जाती है , उसका कोई गल्त आदमी फायदा न उठाने पाए , इस तरफ सरकार को खास तवज्जो देनी चाहिए।

चेयरमैन साहब, इससे आगे मैं ओला वृश्टि के बारे में भी यहां पर कुछेक बातें रखना चाहता हुं । पिछली सरकार ने किसानो को 300 रु0 पर एकड के हिसाब से मुआवजा दिया था पर सरकार ने इस बारे में अभी अपनी नीति स्पश्ट नीति की है भिवानी , महेन्द्रगढ और सिरसा व दूसरी और जगहों पर भी ओला वृश्टि के काफी नुकसान हुआ है। भिवानी के डी.सी. ने बताया है कि वहां पर कोई लगभग 45 से 50 लाख रूपये का नुकसान हो गया है और इसके साथ–साथ ही किसानों को टयबवैल्ज चलाने के लिये बिजली भी नहीं मिल रही है और बिजली न होने के कारण किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। भिवानी, लोहारू के 30–35 गांव ऐसे हैं, जहां पर ओला वृश्टि होने के कारण से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ था और

इस साल भी, वहां पर कहत की स्थिति है। उन इलाकों में किसानों को जो टयूबवैल्ज पर बिजली सप्लाई की जाती है उसमें राहत दिलाई जाए। इसके लिए सरकार को चाहिये कि उनके बिजली के जो बिल आएं, उनसे किसानों को माफी दी जाए। उन बिलों का भुगतान सरकार माफ कर दे ताकि किसानों को कहीं जाकर कुछ सुख का सांस मिलेगा। इसलिये मुझे अपने माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह पूर्ण आशा है कि जब वे इसका जवाब देंगे तो अवश्य ही किसानों के हितों को धन में रखैंगे और हर तरह की राहत किसानों को अवश्य देंगे। इसके साथ–साथ चेयरमैन साहब, आप जानते हैं कि आज छोटी–छोटी उपभोक्ताओं की चीजों के लिये कितनी भारी दिक्कत है। चाहे चीनी हो, चाहे मिट्टी का तेल हो या किसान का डीजन हो, इसे हासिल करने में बहुत कठिनाई होती है। इन कठिनाईयों के संबंध में सभापति जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप सुन कर हैरान होंगे कि यहां कई बार हाउस में कनफैड के संबंध में चर्चा हुई है। लगभग 17 आइटम्ज ऐसी हैं जो कनफैड को सप्लाई की जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि 17 चीजों में से मुश्किल से दो–चार चीजें उसे उपलब्ध हो पाती होंगी। ट्रिब्यून अखबार में छपा था और उसमें साफ बताया गया था कि कनफैड में पिछले अढाई सालों के दौरान 9 लाख रूपये का मुनाफा हुआ। उसके अलावा 10 लाख रूपये सरकार ने उसको मदद दी और 6 लाख रू. बैंक की क्रेडिट की लीमिट थी। यह सारा पैसा कहां हजम हो गया। सभापति महोदय, आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जहां इस प्रकार का

बदइन्तजाम हो वहां से चीजें किस तरह से सप्लाई हो सकती हैं। कोआप्रेटिव महकमें के संबंध में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ तो इस प्रकार की गड़बड़ है और दूसरी तरह उसमें अंधाधुंध अप्वांएटमैंटस की जा रही हैं। कोई एडवरटाइजमैंट नहीं की गई और कोठ ऐप्लीकेशन इनवाइट नहीं की गई लेकिन 15—15 सौ रू. की नौकरियां दी जा रही हैं। इनका लोगों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सभापति जी, कोआप्रेटिव बैंक के जो चेयरमैन हैं उनका 8 दिसम्बर, 1978 के ट्रिब्यून अखबार में एक ब्यान छपा है। मैं आपको वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—

"Mr. Zile Singh, Janata M.L.A. from Julana in Sonepat District, who is Chairman of the Haryana State Federation of Consumer's Co-operative Whole-sale Stores (CONFED). today alleged that 15 General Managers of CONFED stores had been appointed by the Managing Director, Mr. Lahmber Singh, without consulting him.

Mr. Zile Singh told reporters that these appointments were illegally made and that he would not be responsible if CONFED suffered in any manner at the hands of the new appointees."

There is another news item in the tribune dated the 4th November, 1979 which reads as under:-

"The Haryana State Federation of Consumer Co-operative Whole-sale Stores (CONFED) is in financial straits. It is authoritatively learnt that CONFED's coffers are empity. It

has no money to buy goods for supply to the consumers' co-operative stores in the State. Consequently, the much publicised Essential Commodities Distribution Scheme, which was lunched in July, is in difficulties.

CONFED has already eaten up its profit of Rs. 9 lakh it earned two and a half years back. The sum of 10 lakh given by the Government has already been spent. It raised a loan of Rs. 6 lakh, which has been used, Its bank credit limit of Rs. 6 lakh has been exhausted."

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह): आप शान्ति से पढ़ें घबरा क्यों रहे हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: घबराने की बात इसलिए है कि रोना आता है कि किस प्रकार से सरकार का खजाना लुटाया जा रहा है। किस प्रकार से गरीब किसानों और मजदूरों के टैक्स के पैसे की लूट मचाई जा रही हैं। चैयरमैन साहब, इसमें आगे लिखा है''..... The main job of CONFED is to buy essential goods direct from manufacturers and send them to the consumer stores from distribution. Sugar was badly needed during the recent festival period but was not supplied in sufficient quantities to the consumer stores....."

सरदार तारा सिंह: आर्य साहब, समझ में नहीं आ रहा है आप क्या पढ़ रहे हैं?

श्री हीरा चन्द आर्य: मैं आपको ही समझाना चाहता हूं आप मेहरबानी करके ध्यान से सुनें। (चौ. मेहर सिंह राठी की ओर से विघ्न) राठी साहब बड़े भारी अंग्रेजी के स्कालर हैं। (शोर)

श्री सभापति: आर्य साहब, आपका समय हो गया है अब आप वांइड–अप करें।

श्री हीरा नन्द आर्य: सभापति जी, अभी तो मैंने बोलना ही भुरू किया है। मैं आपकी इजाजत से ये अखबार की कटिंग्ज सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: सदन की पटल पर ये ऐसे नहीं रखी जाएंगी, पहले ये एग्जामिन होगी। You can give these to the Secretariat.

श्री हीरा नन्द आर्य: सभापति महोदय, इसके बाद मैं आपका ध्यान शिक्षा के बारे में दिलाना चाहता हूं। जब हमारी सरकार थी उस समय लगभग 349 स्कूल अपग्रेड किये गये। यहां कई बार यह चर्चा आई कि जब मैं शिक्षा मंत्री था तो उस वक्त मैंने अपने हल्के के काफी स्कूल अपग्रेड किये। मुझे यह बात कहने से कोई इंकार नहीं कि मैंने भिवानी जिले में भिवानी, तोशाम, लोहारू और बाढ़ड़ा में अधिक से अधिक स्कूल अपग्रेड करने का प्रयत्न किया और 11–11 स्कूल अपग्रेड किये। सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि वहां पर हकीकत में स्कूलों की जरूरत थी। आप सारे हरियाणा में देखें ऐसा कोई सब–डिवीजन नहीं है जहां

प्राइवेट या सरकारी कालेज न हो। लेकिन लोहारू सब–डीवीजन में कोई भी कालेज नहीं है। सभापति जी, जो स्कूल अपग्रेड किये गये थे उनके विरूद्ध लोग हाई कोर्ट में गये। इस सरकार ने सिरसा, हिसार और भिवानी जिले के 29 स्कूलों को डाउन ग्रेड किया। अगर आप कांस्टीच्यूशन में दिये गये डायरैक्टिव प्रिंसिपल्ज के मुताबिक भी देखें तो स्कूलों को अपग्रेड करने का तो सरकार को अधिकार है लेकिन हाउन ग्रेड करने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर कोई मन्दिर नाम की चीज हे तो वह सबसे बड़ा विद्या का मन्दिर होता है। अगर इस प्रकार से उन मन्दिरों को तोड़ा जाएगा तो आप ही अन्दाजा लगाएं कि इसका क्या हश्र होगा। मुझे विश्वास है कि जब वित्त मंत्री जी अपना जवाब देंगे तो इन स्कूलों को दोबारा अपग्रेड करने की घोशणा करेंगे।

श्री सभापति: आर्य साहब, आपका समय समाप्त हो चुका है। आप वाइंड अप करें।

श्री हीरा चन्द आर्य: चेयरमैन साहब, मैं शिक्षा के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं उसके बाद खत्म कर दूंगा। चेयरमैन साहब, हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद शिक्षा के सम्बन्ध में जितनी लापरवाही बरती गई है उतनी किसी और चीज में नहीं बरती गई है। पिछली जनता पार्टी की दो साल की सरकार ने शिक्षा में सुधार करने के लिए प्रयन्त किया था और जो प्राईवेट स्कूल और प्राइवेट कालजिज हैं उनको ग्रांट देने का प्रयत्न किया था। चेयरमैन साहब, जैसा कि बाबू मूल चन्द जैन जी

ने चर्चा की कि प्राइवेट स्कूलों/कालेजों के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने इन संस्थाओं की हालत में सुधान करने की सिफारिश की थी। लेकिन आज जो इस संस्थाओं का 75 प्रतिशन ग्रांट दी जा रही है इसका मोड आफ पेमेंट ठीक नहीं है। यही कारण है कि अभी तक इन संस्थाओं की हालत नहं सुधर पाई है। इनकी हालत बहुत कमजोर है। वे इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। चेयरमैन साहब, दूसरी बात यह है कि इन संस्थाओं को जो 75 प्रतिशत ग्रान्ट दी जाती है वह उन संस्थाओं की इनकम समझी जाती है। मेरा कहना यह है कि वह उन संस्थाओं की इनकम न समझी जाए। इसके अलावा इन संस्थानों में एक और गड़बड़ घोटाला हो रहा है कि वे किसी भी टीचर को एक साल से ज्यादा सर्विस में नहीी रखते, एक साल से पहले ही उनको सर्विस से निकाल दिया जाता है क्योंकि जिस टीचार की एक साल से ज्यादा की सर्विस हो जाती है उसको रैगूलर करना पड़ता है इसी वजह से वे उसको एक साल से पहली ही निकाल देते हैं। चेयरमैन साहब, आपके द्वारा मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस मामले की तरफ भी गम्भीरता से विचार किया जाए। इसके अलावा चेयरमैन साहब, आज सवालों के टाईम पर भी यह जिक्र आया था कि सिरसा, भिवाननी और मेवाल के एरिया में अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए हमने सरकार को एक सुझाव दिया था कि जहां टीचर्ज उपलब्ध नहीं है और दूर के टीचर्ज वहां पर जाना नहीं चाहते और जिन जगह पर जे.बी.टी. टीचर्ज की कमी हैं वहां पर इनका एक ट्रेनिंग सैन्टर खोला जाए

और उसी इलाके के जो इनटैलीजेन्ट लड़के हैं उनको मैरिट के आधार पर ट्रेनिंग देकर वहां पर लगाया जाए ताकि शिक्षा का काम सुचारू रूप से चला सके। चेयरमैन साहब, बातें तो और भी कहने के लिए काफी थीं, लेकिन समय के अभाव के करण मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार ने जो वायदे किये थे उनके बारे में न तो कहीं सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस में जिक्र है और नहीं इस बजट में जिक्र है। चेयरमैन साहब, समझ में नहीं आता कि यह कांग्रेस (आई) है या कांग्रेस (गई) है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): चेमरमैन साहब, तायल साहब ने इस प्रान्त का जो बजट इस हाउस में रखा है, मैं उसका स्वागत भी करता हूं और समर्थन करने के लिए मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखूंगा। चेयरमैन साहब, इस बजट के पेश होने से पहले जनता में बड़ी चर्चाएं और शंकाएं थी और जो मेरे विरोधी भाई सामने बैठे हैं, जो 10 मार्च, 1980 के दिन बजट हाउस में पेश किया गया था तो मेरे विरोधी भाइयों की जुबान पर यह बात थी कि तायल साहब तो बिजनैस मैन हैं ये व्यापारियों को रियायत दे कर सारे के सारे टैक्स किसानों पर ही लगायेंगे लेकिन चेयरमैन साहब, जब यहां सदन के अन्दर वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच शुरू से लेकर आखिरी पेज तक पढ़ी और जब कोई टैक्स कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया तो मेरे विरोधी भाई होकर

कुछ तो हाउस के सोने लगे और कुछ हाउस को छोड़कर यह कहते हुए बाहर चले गये कि हमारे पास कहने के लिए कोई बात बाकी नहीं रह गई है। चेयरमैन साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो 1977 में जनता पार्टी बनी थी उस जनता पार्टी के मैनीफिस्टो में यह बात लिखी गई थी कि जनता के ऊपर आज टैक्स इतने बढ़ गये हैं कि जनता उन टैक्सों को बर्दाश्त नहीं कर सकती (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौ. राम किशन, पदासीन हुए) और अगर जनता पार्टी सत्ता में आई तो जनता पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन चेयरमैन साहब, उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने किसानों पर टैक्स लगाये और टैक्स के ऊपर भी 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाया। चेयरमैन साहब, सरकार किसी किस्म का भी टैक्स लगा दे उससे जनता को काफी परेशानी होती है। आज हिन्दुस्तान में टैक्सों की पोजीशन में हरियाणा प्रान्त का दूसरा नम्बर है। चेयरमैन साहब, आप जानते हैं कि जो पहले टैक्स था वह 25 पैसे सैकड़े के हिसाब लगना शुरू हुआ था उसके बाद 40 या 50 पैसे सैकड़े के हिसाब से हुआ। इस पतरह से बढ़ता–बढ़ता आज 7 या 10 प्रतिशत ही नहीं बल्कि उस पर सरचार्ज भी है और आज टैक्स इतने बढ़ गये हैं कि आज की मंगगाई के कारण भी ये टैक्स ही हैं। आज हिन्दुस्तार का और हरियाणा का किसान, व्यापारी और दूसरा कोई भी आदमी हो सभी इन टैक्सों की भरमार से इतने दुखी हो गये हैं कि उनका जीना दुर्भर हो गया है। चेयरमैन साहब, उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के

अन्दर बहुत टैक्स लगाये थे पहले हरियाणा के अन्दर मार्किट फीस दो फीसदी थी लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने उसको तीन फीसदी कर दिया। चेयरमैन साहब, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई व्यापारी है और चाहे कोई दूसरा आदमी है इसको कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उस सयम की जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चौ. देवी लाल जी ने आबियाना पर जो सरचार्ज लगाया था उसको तो वापिस ले लिया लेकिन मार्किट फीस वही रखी। उस मार्किट फीस के खिलाफ पब्लिक सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यह कोई तरीका नहीं है मार्किट फीस लेने का और वह भी उस सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर वापिस लेनी पड़ी चेयरमैन साहब, एक बात के लिए मैं अपनी सरकार को और हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि बजट के बारे में जो चर्चाएं थीं, जो शंकाएं थी और जो बात जनता की मांग थी, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई किसान है और चाहे कोई आम आदमी है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी पर भी किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया है। चेयरमैन साहब, मैं यह कहता हूं कि बिना टैक्स के बजट की मिसाल जो हरियाणा ने पेश की है, आने वाली कोई भी सरकार किसी भी स्टेट में बने उस सरकासर को इस मिसाल पर अमल करके चलना चाहिए तभी जनता उन लोगों से प्यार करेगी और हमेशा उसी सरकार को बनाने की कोशिश करेगी। चेयरमैन साहब, में विरोधी भाईयों का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर वे इस बजट को ध्यान से पढ़ते तो उन्हें पता

लगता कि अगले साल वित्त मंत्री ने स्टेट की आमदनी कितनी बढ़ाई है। चेयरमैन साहब, 1978–79 में टैक्सों से 131 करोड़ रूपए की आमदनी हुई जबकि 1977–78 में 119.64 करोड़ रूपए हुई थी। 1979–80 में 153 करोड़ रूपए की आमदनी हुई और 1980–81 मैं तो यह सारा हाउस जानता है कि देश के अन्दर सूखा पड़ा सारे प्रान्त में सूखा पड़ते से बिजली की दिक्कत हुई। ये दोनों ही ऐसे कारण है जिससे फैक्ट्रियों में होने वाली पैदावार में भी कमी हुई और जमीन की पैदावार भी घटी है। देश में पैदावार कम होने के बावजूद भी चेयरमैन साहब, 167 करोड़ 56 लाख रूपया टैक्सिज से आमदनी होगी। टैक्सिज से आमदनी में जो इतनी बड़ी बढ़ौत्तरी सरकार ने की है इसका क्या कारण है? चेयरमैन साहब, मेरे साथी हाउस में कहते थे कि सरकार ने व्यापारियों के साथ रियायत की है। मैं मानता हूं कि सरकार ने रियायत की है, लेकिन यह रियायत व्यापारियों से नहीं बल्कि कंज्यूमर्ज के साथ की है। चेयरमैन साहब, जब एक आदमी को हम चोर समझते हैं, और अगर उसको चोरी करने की और गुंजाईश मिल जाए तो वह और ज्यादा चोरी करेगा। कुछ अफसरों के खिलाफ भी मेरे कुछ साथियों को गिला है कि वे ट्रेडर के साथ मिलकर चोरी करते हैं। मैं समझता हूं कि एक व्यापारी को टैक्स में चारी करने की जितनी गुंजाईश हो सकती है, अगर उसके साथ अफसर मिलकर चोरी करता है तो टैक्स की चोरी और बढ़ेगी। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि टैक्स की दर और घटा दी जाए जिससे कि टैक्स की चोरी की गुंजाइश कम हो जाये।

फाइनैंस मिनिस्टर श्री तायल ने कुछ कंट्रोल तो किया है लेकिन इसके साथ ही साथ अगर वे टैक्सेशन डिपार्टमैंन को थोड़ा सा काबू कर लें तो टैक्स की कम चोरी हो जायेगी और हमारी आमदनी ज्यादा बढ़ जाएगी।

चेयरमैन साहब, अब मैं हरिजनों के लिए चौपालें बनाने के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने चौपालें बनाने के लिए काफी ग्रांट दी है। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसकी दरख्वास्त चौपाल बनाने के लिए नामन्जूर की हो। जब मुख्यमंत्री दौरा कर रहे थे तो जितनी डिमांडज चौपालों के लिए आई थी सब की सब मन्जूर कर दी और आज एक भी हरिजन यह नहीं कह सकता कि उसको किसी किस्म की ग्रांट न मिली हो, सरकार के फ्राखदिली से हरिजनों को पैसा दिया है। चेयरमैन साहब, शराब की पालिसी के बारे में मैरे कुछ साथियों को एतराज है। आप जानते हैं कि शराब का मामला हरियाणा का ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान का मामला है। हमारी केन्द्रीय सरकार भी इस पर काबू नहीं पा सकी है। आपको याद होगा, सरकार ने रोहतक जिले को ड्राई एरिया घोशित किया था लेकिन रोहतक जिले के अन्दर शराब बन्द नहीं हुई बल्कि बढ़ी थी। शराब की इतनी भरमार थी कि चोरी छिपे खूब शराब बिकी, कितने ही केसिज लोगों के ऊपर बने। इसके बाद जनता ने सरकार से अपील की कि इस बंदिश के मुकदमेंबाजी हो रही है और खुले तरीके से शराब इस्तेमाल हो रही है, इसलिए रोहतक जिले में शराब की

पाबन्दी को खत्म किया जाए। उसी वक्त सरकार ने इस बात पर गौर किया और महसूस यिका कि वाकई यह बात सही है। पिछली सरकार ने प्रोहिबिशन का तरीका अख्तियार किया था लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सकी। पंचायतों से रैजोल्यूशन पास हो कर आये कि उनके गांव में शराब के ठेके बन्द किए जाएं। ठेके कागजों में तो बन्द हो गए, एक्साईज डयूटी भी खत्म हो गई, लेकिन शराब बन्दी नहीं हुई, बल्कि इसका नतीजा यह हुआ कि घर–घर में शराब की भट्ठियां बनने लगी, लोग नाजायज तरीक से फायदा उठाते रहे जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को एक्साईज डयूटी कम आने से घाटा होने लगा। अगर दूसरी स्टेटों में शराब की पाबन्दी न हो और इधर हरियाणा सरकार पाबन्दी लगाने की कोशिश करे तो मैं समझता हूं कि हरियाणा में शराब बन्दी नहीं हो सकती। इसलिए हमारी केन्द्रीय सरकार ने और हरियाणा सरकार ने यह महसूस किया कि जब तक हिन्दुस्तान की सरकार स्टेटों में प्रोहिबिशन की पालिसी लागू नहीं होगी, सारे देश के लिए एक ही कानून नहीं बनेगा, तब तक अकेला हरियाणा कामयाब नहीं हो सकता। नाजायज शराब निकालने से लोगों पर केसिज बन रहे हैं लेकिन पुलिस मिल–मिला कर, पैसा लेकर उनको छोड़ देती है। हमारी सरकार ने सोचा कि यह पालिसी ठीक नहीं और पालिसी बदल कर एलान कर दिया कि आइंदा के लिए सही तरीके से शराब के ठेके बिकेंगे। पिछली सरकार की तरफ नहीं कि घर में ही बैठ कर ठेकों की लाटरी निकाल ली और जिसको चाहा

ठेका दे दिया। हम तो बाकायदा पब्लिक में अनाउंसमेंट करके नीलाम करेंगे .....

चौ. सतबीर सिंह मलिक: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। चेयरमैन साहब, इन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने घर में बैठ कर ठेकों की लाटरी निकाल दी, मैं इस चीज को चैलेंज करता हूं। जो भी लाटरी निकली है वह डी.सी. और एक्साईज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के सामने निकाली है और बाकायदा दरखास्ते लेने के बाद लाटरी निकाली गई। ये साबित करें कि किसी अफसर या मिनिस्टर या एम.एल.ए. के घर पर बैठ कर किसी को ठेका दिया हो। ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। नो इन्ट्रप्शन प्लीज।

सरदार सुखदेव सिंह: चेयरमैन साहब, आन ए प्वायंट आफर आर्डर। चेयरमैन साहब, फाइल में रिकार्ड है कि पिछले साल 15 करोड़ रूपये का नुक्सान इनकी इस पालिसी से हुआ है जब ये एक्साईज मिनिस्टर थे। इसके बारे में मैंने एक बार असैम्बली में भी सवाल पूछा था कि क्या इसकी इन्क्वायरी होगी कि क्यों नुक्सान हुआ है? आज ये इन्क्वायरी से बचने के लिए दूसरों को गुमराह करने की बात कैसे कह सकते हैं। (व्यवधान)

मास्टर शिव प्रसाद: चेयरमैन साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। चेयरमैन साहब, इन्होंने कहा है कि घर में बैठकर फैसला किया है। ये इस बात को साबित करें कि किस के घर में बैठ कर फैसला किया है?

Mr. Chairman: Master ji, please sit down. This is no point of order. I would request Sh. Mange Ram Gupta to please carry on.

श्री मांगेराम गुप्ता: चेयरमैन साहब, हाउस में आज चीनी की मंहगाई के बारे में काफी चर्चा हुई और अपोजीशन के भाइयों ने कहा कि चीनी के भाव 4 रूपये किलो से बढ़ कर 7 रूपये किलो हो गए। मैं मानता हूं कि चीनी का भाव बढ़ा, लेकिन उसका कारण आज की सरकार नहीं है बल्कि केन्द में जो काम चलाऊ सरकार बनी थी उसकी गलत नीतियों के कारण, गलत पालिसी बनाने के कारण ये भाव बढ़े हैं ओर मैं यह साबित करने के लिए तैयार हूं कि केन्द्रीय सरकार ने कैसे भाव बढ़ाये हैं। चेयरमैन साहब, आपको पता है, सरकार ने 17.12.79 को एक पालिसी बनाई कि जिस ट्रेडर के पास चीनी का स्टौक पड़ा हैं, उसक 65 परसैंट स्टौक सरकार 280 रूपये पर क्विंवटल के हिसाब से खरीद लेगी और जो स्टौक बाकी बचेगा, यानी 35 परसैंट स्टौक को ट्रेडर फ्री सेल में बेच सकता है। चेयरमैन साहब, सरकार अगर किसी जमीन को एक्वायर करती है तो कानूनी इजाजत देता है कि एक्वीजीशन के समय जमीन का जो भाव है उसी भाव से जमींदार को कम्पैंसेशन मिलना चाहिए। चीनी का 65 परसैंट स्टौक एक्वायर

करने पर भी यही कानून लागू होना चाहिए लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उस वक्त मार्किट में 380 रूपये क्विंटल का रेट था लेकिन सरकार ने फैसला किया कि 280 भाव से लेगी। इस तरह से एक ट्रेडर का एक क्विंटल चीनी पर 100 रूपये का घाटा होता है। मैं मानता हूं कि गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रेडर्ज को नुक्सान हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कानून बनाने वालों ने इसमें एक नुक्स छोड़ दिया .....

चौ. हरस्वरूप बूरा: चेयरमैन साहब, ट्रेडरों ने किसानों के नाम पर सैकड़ों बोरियां किसानों के घरों में रखी हुई थी जो बाद में खुले आम बेची, इनको नुक्सान कैसे हो गया?

श्री मांगे राम गुप्ता: मैं उसी प्वायंट पर आ रहा हूं। चेयरमैन साहब, चीनी इसलिये मंहगी हुई क्योंकि पालिसी डिफैक्टिव थी। 17.12.79 को सरकार ने कानून बना दिया कि जितनी चीनी ट्रेडर के पास है उसका 65 परसैंट सरकार 280 रूपए पर क्विंटल के भाव एक एक्वायर कर लेगी और 35 परसैन्ट वह खुले आम बेच सकता है। यही इस पालिसी में लैकूना हैं अगर सरकार ऐसा कानून बनाती है कि जितनी चीनज ट्रेडर्ज के पास है, वह सारी की सारी मार्किट रेट पर एक्वायर कर लेती और एक क्विंटल चीनी भी किसी ट्रेडर को खुले आम बेचने की इजाजत न देती तो मै। दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 महीने तक चीनी का भाव 5 रूपये किलो से ज्यादा नहीं बढ़ सकता था। ऐसी नीति बनाने वालों ने मिल मालिकों के साथ मिलकर घपला किया है।

घाटा पूरा करने के लिये ट्रेडर्ज ने चीनी को खुले आम अपनी मर्जी से मुताबिक बेचना शुरू कर दिया और अगर किसी व्यापारी के खिलाफ सरकार कोई ऐक्शन लैने की बात करनी जो वह कोर्ट में जाकर खड़ा हो जाता और उसको स्टे मिल जाता क्योंकि कानून में स्टे लैने की गुंजाईश है। सरकार ने कानून बनाते समय ट्रेडर से यह नहीं पूछा कि बताओं तुम्हारे पास चीनी का कितना स्टौक है? उसने इसकात फायदा उठाया और 100 रूपया एक बोरी पर जो उसका घाटा होता था वह पूरा करना शुरू कर दिया। जहां तक किसान के घर बोरियां रखने वाली बात है, उसमें तो किसान का भी हिस्सा था, वरना कौन अपने घर में ट्रेडर की बोरियां रखवाता है।

चौ. हरस्वरूप बूरा: चेयरमैन साहब, मैं दावे से कहता हूं कि अगर कोई एक कतरा चीनी भी मेरे यहां से पकड़वा दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता: मैंने इनके बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने तो जनरल बात की है।

चौ. हरस्वरूप बूरा: वह तो सीधा मेरे ऊपर अटैक है। (शोर)

श्री मांगे राम गुप्ता: माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि मेरा मतलब उनसे नहीं था बल्कि मैंने तो जनरल बात की थी। चेयरमैन साहब, इन्होंने कहा था कि व्यापारी किसानों के पास

चीनी रखते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि बगैर हिस्सेदारी के कोई चीनी नहीं रख सकता। (शोर)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

श्री मांगे राम गुप्ता: चेयरमैन साहब, इंडस्ट्रीज के बारे में यहां बड़ी चर्चा हुई। यहां एक सवाल भी आया था और मंगला साहब यह बात कर रहे थे कि रूरल इंडस्ट्रीज जो देहात में लगी हुई हैं उनसे औक्ट्राय चार्ज किया जाता है जबकि सरकार की तरफ से वह माफ है। मेरे साथी ने ऐसा लगता है कि इस बात की गहराई में जाने की कोशिश नहीं की। चेयरमैन साहब, सरकार की तरफ से तो औक्ट्राय माफ है लेकिन म्यूनिसिपल कानून में खामी होने की वजह से वह चार्ज हो जाता है। होता यह है कि जो माल रूरल इंडस्ट्रीज का ट्रांसपोर्ट में आता है वह अगर 24 घंटे के बाद वहां पड़ा रह जाए तो म्यूनिसिपल कमेटी ट्रांसपोर्ट वालो से चुंगी चार्ज कर लेती है और ट्रांसपोर्ट वाले उसे उनसे चार्ज कर लेते हैं। दिक्कत यह है कि देहात में जो इंडस्ट्रीज लगी होती है उनको समय से यह पता नहीं लगता कि तुम्हारा माल ट्रांसपोर्ट वालों के पास आ चुका है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल ऐक्ट में यह अमैन्डमैंट की जाये कि रूरल इंडस्ट्रीज का जो माल ट्रांसपोर्ट में पड़ा हो उस पर एक दिन की नहीं बल्कि सात दिन की मोहलत होनी चाहिए ताकि उस समय में उसे इत्तलाह मिल सके और वह अपना माल उठा सके।

चेयरमैन साहब, एक बात मैं आम जनता के भले की सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, हरियाणा के अन्दर ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दू लोग रामलीला करते हैं। एक साल में यह दस दिन का फंक्शन होात है। इस फंक्शन में जो बिजली खर्च होती है उसका रेट पिछली सरकार ने तीन रूपया प्रति यूनिट रखा है जबकि रेडक्रास मेले के लिये, जिसके अन्दर नंगा नाच और जुआबाजी चलती है और जिसे अब हमारी सरकार ने बन्द कर दिया है, 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती थी। चेयरमैन साहब, यह बड़ी गलत बात है कि रैडक्रास के मेले को तो 45 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाए और रामलीला, जो हिन्दुओं का एक धार्मिक फंक्शन है, के लिये तीन रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाए। मेरी यह प्रार्थना है कि सरकार की तरफ से बिजली बोर्ड को यह हिदायत होनी चाहिए कि ऐसे धार्मिक फंक्शज के लिये, चाहे वह रामलीला का फंक्शन हो या कोई और फंक्शन हो, 45 पैसे प्रति यूनिट से ज्यादा रेट चार्ज न किया जाय।

श्री सभापति: कृपया वाइन्ड अप करें।

श्री मांगे राम गुप्ता: चेयरमैन साहब, मैं ऐजुकेशन के बारे में एक दो मिनट कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। (विघ्न) चेयरमैन साहब, आप जीन्द डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं और आपको पता है कि वहां कोई पोस्ट ग्रेजुएट कालेज नहीं है। हमारे सारे के सारे लड़के दाखिला लेने के लिये दूसरे जिलों में टक्करें

खाते रहते हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे यहां कालेज हैं उनमें पौलिटिकल सांईस और इकनोमिकस की एम.ए. क्लासिज चालू की जाएं तथा एक पौलिटैकनिक भी खोला जाए ताकि हमारे जिले के लड़कों को दूसरे जिलों में न जाना पड़े।

12.00 बजे

चेयरमैन साहब, सबसे ज्यादाया अन–एम्पलायमैंट जींद जिले में है क्योंकि न तो वहां सरकार की तरफ से कोई इंडस्ट्री लगाई गई है और न ही प्राईवेट बिजनैसमैन की तरफ से लगाई गई है जिसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों को कोई धन्धा मिल सके। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कोई बड़ी इन्डस्ट्री वहां लगाएं जिसमें हजारों की तादाद में पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग मजदूरी और नौकरी करके अपने बाल–बच्चों का गुजारा कर सकें और अपनी पढ़ाई लिखाई का फायदा अपने मां बाप को दे सकें। इन शब्दों के साथ चेयरमैन साहब, मैं मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। (विघ्न)

श्री गुलजारी सिंह (राजौंद): चेयरमैन साहब, आपने समय दिया इसके लिये आपका बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब, आज बजट पर चर्चा हो रही है। मैं भी उसके बारे में दो चार बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो यह बजट हम सबके लिये

जाना पहचाना है क्योंकि यह वही पुराना ज्योग्राफीया है जो हम पिछले तीन साल से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कोई नई बात नजर नहीं आती। इसमें जो भी स्कीम्ज और प्लान्ज रखी गर्ठ हैं, चाहे वे पानी की हैं, चाहे फ्लड की हैं, चाहे बिजली की हैं, चाहे किसानों को सबसिडी देने की हैं या बेरोजगारों को रोजगार देने की हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं और उन्हे पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है जबकि प्रैक्टीकली उनका अनुभव हम करते आ रहे हैं। आप ड्रेनेज स्कीम को ही ले लीजिए। इनमें से कौर ऐसा विधायक है जिसने चौ. देवी लाल जी के राम में सिर टोकरी उठा कर काम न किया हो? इसी तरह से आप जनते हैं कि उस वक्त नहरों को पक्का करने का काम बहुत जोर शोर से चल रहा था। यही बात फ्लड के बारे में हैं। आपको मालूम है कि फ्लड के दिनों में हर एम.एल.ए. और दूसरे लोग किस तरह से गांव–गांव में पहुंचे थे। इसी तरह से किसानों को सबसिडी आदि देने के बारे में जो काम किया गया है वह भी कोई नई बात नहीं है। बैंकों को सूद भी पहले ही घटाया जा चुका था। बिजली का फ्लैट रेट भी उसी समय कर दिया गया था। (विघ्न) चेयरमैन सहाब, चौ. देवी लाल की सरकार ने जब बिजली के फ्लैट रेट का फैसला किया था तो सारे हरियाणा में एक त्योहार मनाया गया था, एक खुशी मनाई गई थी लेकिन क्या करें हमारी बदकिस्मती है कि आज बिजली बादलों में तो चमक सकती है लेकिन किसानों को नहीं मिलती। चेयरमैन साहब, आप हैरान होंगे कि अभी पिछले दिनों में जब हमारे एक जिम्मेवार मंत्री जी गांव–गांव में घूम रहे

थे और अपनी पार्टी के लिये वोट मांग रहे थे और कह रहे थे कि खूनी पंजे से बचो और याद करों रिवासा कांड तो लोगों ने कहा था कि मंत्री जी यह बात छोड़ो और बिजली की बात बताओ। उस समय मंत्री जी ने कहा था कि क्या करें चौ. देवी लाल जी ने रात दिन बिजली देकर के तारें इतनी कमजोर कर दी है कि बिजली नहीं दी जा सकती। (विघ्न) अब तार तो कमजोर हो चुके हैं इसलिये वे बिजली जो सहार नहीं सकते। आप हैरान होंगे कि यह बात एक जिम्मेदार मिनिस्टर की तरफ से कही गई है। चेयरमैन साहब, अब मैं बिजली के फ्लैट रेट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। बिजली का फ्लैट रे 18 रूपए प्रति हार्स पावर है यानी पांच हार्सपावन की मोटर हो तो 90 रूपये लेने चाहिएं परन्तु आज गरीब जमींदार को बुरी तरह से लूटा जा रहा है। लूटने का इस सरकार ने एक नया ही तरीका अख्तियार किया है। इन्होंने एक नया शब्द रखा है सन्डरी चार्जिज। पांच सौ रूपये का बिल है तो सन्डरी चार्जिज के साथ 600 रूपये लिख दो कोई पूछने वाला नहीं। आज इन सन्डरी चार्जिज का कोई इलाज नहीं है। मेरी तो ऐसा समझ में आया है कि जैसे हमारे सियासी भाई हैं चाहे ये कुछ भी कर लें, चाहे दिन में तीन बार दल बदल लें लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मन चाहा किसी के साथ दोस्ती करें ओर मन चाहा किसी के साथ रिश्तेदारी करें, उनसे पूछते हैं तो यही कहते हैं कि तेरे को इन बातों का क्या पता यह तो सियासत की बात है। यही इन सन्डरी चार्जिज की पोजीशन है। ये भी सियासत के ही बराबर हैं।

चेयरमैन साहब, यह जो सरकार की ओर से किसानों को फसलों पर छिड़कने के लिये दवाईयां देते हैं इनकी भी बड़ी बुरी हालत है। आज कहत पड़ा हुआ है और सरकार कहती है कि हम बड़ी भारी इमदाद किसानों को दे रहे हैं लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप किस प्रकार की इमदाद दे रहे हैं। आप भी किसान घराने से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है किसान के खेत में अगर बिल्कुल ही कमजोर फसल खड़ी हो और उसको यह भी पता हो कि इस खेत से केवल पांच मन ही अनाज पैदा हो सकात है लेकिन फिर भी वह उस पर और अधिक पैसा खर्च करने के लिये तैयार होता है क्योंकि उसको अपनी फसल से बहुत ही प्यार है। वह चाहता है कि इस फसल को किसी तरह से बचा लिया जाये लेकिन यह सरकार कहती है कि बिजली की तार कमजोर हो गई हैं, बिजली उनसे गुजर नहीं सकती है। मैं नागर साहब से निवेदन करूंगा कि वे अब हरियाणा भवन में जाना छोड़ कर डीजल का प्रबन्ध करें। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आज डीजल की यह हालत है कि गरीब किसानों की औरतें, बच्चे और लड़के लाइनों में खड़े हुए हैं और अपने जेवर बेच कर ब्लैक में तेल खरीद रहे हैं। यह सरकार यहां कहती है कि किसानों को सबसिडी दी जा रही है।

श्री सभापति: आपका समय हो गया है, आप वाइंड–अप करें।

श्री गुजजार सिंह: आप को पता है कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी स्टेट के किसानों के विशय में अर्ज कर रहा हूं। चेयरमैन साहब इस सरकार को जो खतरा था वह तो टल गया, अब इनको भलाई के कामों की तरफ भी आना चाहिए। आज से अढ़ाई वर्श पहले सभी साथी जनता के दरबार में बड़ी उमंग के साथ गये थे और लोगों से वोट मांगे थे। उस टाईम पर लोगों के मन में बड़ा स्वप्न था लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा जो वायदा करके आये थे वह पूरा नहीं कर पाये। अब मैं इन भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो आपने दिमांग मैं टिकट का खतरा था वह भी टल गया है और मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि इलैक्शन टल गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अब तो आपको कुछ हित के कामों की तरफ आना चाहिए। वैसे चेयरमैन साहब, यह टिकट की बहुत ही बुरी बीमारी है। अच्छे भले आदमी की इज्जत बिगाड़ देती है। इसी टिकट के सिलसिले में एक गांव के साधारण ताऊ की बात मुझे याद आ गई। पानीपत के पास एक गांव है। यह साधारण किसान अपनी लड़की को मिलने के लिये जाना चाहता था। उसने सोचा कि अपनी लड़की से भी मिल आऊंगा और उसका सिन्धारा (सीधा) भी दे आऊंगा वह किसान अपने गांव चे चल कर स्टेशन पर गया तो उसने टिकट ले ली और टिकट लेने के बाद वह पास खड़े कालेज के कुछ लड़कों को टिकट दिखाने के लिये चला गया। ताऊ ने उन कालेज के लड़कों से पूछा कि बाबू जी क्या यह टिकट ठीक है? वह कहने लगे कि ताऊ ने उन कालेज के लड़कों से पूछा कि बाबू

जी क्या यह टिकट ठीक है? वह कहने लगे कि ताऊ तुम ने तो गजब कर दिया। आपने तो जनाना टिकट खरीद लिया। अब उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वह दूसरा टिकट खरीदता। उसने सोचा अब कैसे सफर करूं? चेयरमैन साहब, वह पास के ही जानाने विश्राम गुह में गया ओर जो उसके सिन्धारे में चुंदड़ी और लहंगा था उसको पहन कर रेल में बैठ गया। वह तो छः फुट लम्बा था इसलिये अजीबोगरीब दिखायी दे रहा था। इतने में ही चैकर आ गया और ताऊ के पास जाकर पूछा कि अपना टिकट दिखाओ उसने टिकट दिखाया तो बाबू ने कहा कि आप मर्दाने टिकट पर सफर क्यों कर रहे हो? उस ताऊ ने गुस्से में आकर वह चुन्दड़ी फेंक दी और कहने लगा कि इस टिकट में तो मेरी जात ही बिगाड़ दी। मैं तो इस टिकट के ऊपर जनानी भी बन लिया। इसलिये चेयरमैन साहब, टिकट बड़े–बड़े इन्सानों की जात बिगाड़ देता है।

चेयरमैन साहब अब टिकट का खतरा भी दो साल के लिये टल गया है इसलिये मेरी मिनिस्टर साहेबान से रिक्वैस्ट है कि इस ऐशो–आराम की जिन्दगी को छोड़ कर जनता के लिये भी कुछ काम करें। मेरी समझ में नहीं आता कि गर्वनर साहब के लिये यह सरकार कहां झूलने बनाने जा रही है। हमने तो देखे नहीं लेकिन लाखों रूपया जनता की कश्ट कमाई का यों ही जाया कर रहे हैं।

चेयरमैन साहब, मेरे राजौंद हल्के में सरदार लछमन सिंह कुछ घोशणाएं करके आये थे परन्तु जिन योजनाओं के बारे में घोशणाएं करके आये थे परन्तु जिन योजनाओं के बारे में घोशणाएं करके आये थे वे यों की यों पड़ी क्योंकि जब ये घोशणा करके आये थे उसके साथ ही हमारे कुछ साथी भारत दर्शन पर चाले गये। इसी कारण वे सभी योजनायें अधूरी पड़ी हैं। अलावा में एक डिस्पेन्सरी बननी थी, कुछ सड़कें बननी थीं वे सभी अधूरी पड़ी है कोई पूछता तक नहीं। कई माइनर्ज मंजूर की गई थी वे सारी की सारी बन्द पड़ी है, उन पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। मैं मिनिस्टर महोदय से रिक्वैस्ट करूंगा कि उस सारे कामों को पूरा किया जाये। इस बजट में कोई भी ताइद करने वाली बात नहीं है। यह तो ऐसा ही बजट है जैसे मोटरों में बिकने वाली किताब होती है। जैसे मोटर में किसाब बिकती है कि सब बीमारियों का इसमें इलाज हैं, इसी प्रकार का यह बजट है। इस बजट की पुरजोर मुखालफत करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री रघुनाथ गोयल (कैथल): चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पीछे बैठे हुए मैम्बरों का भी ख्याल किया। चेयरमैन साहब, दस तारीख को जो बजट तायल साहब ने पेश किया था वे बड़ी मुश्किल से दो घन्टे में पढ़ पाये थे। जब वे बजट पढ़ रहे थे तो कुछ मैम्बर सो रहे थे और कुछ बैठे बैठे करवटें बदल रहे थे। तायल साहब ने भी पानी पी कर बजट पढ़ दिया, यह भी बड़ा अच्छा ही हुआ।

13.00 बजे

चेयरमैन साहब, अब मैं आपके द्वारा बजट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज हरियाणा में किसानों और मजदूरों की जैसी हालत हो रही है इसको देखकर मस्तक नीचा हो जाता है। जब हमारी सी.एम. साहब 22 तारीख को जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए तो मैं शर्म के सारे घर से बाहर नहीं निकला। मैंने सोचा कि जिन्होंने अपनी जमीर बेच दी है उनके विशय में क्या कहूं? (शोर) चेयरमैन साहब, मैं सियासतदां नहीं हूं, मैं तो पहली बार ही हाउस में बोल रहा हूं लेकिन इस बजट को देख कर दु:ख होात है कि हय बजट कुछ ऐसा ही है जिसके बारे में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। इस बजट को देखकर मुझे दु:ख हुआ कि जिस तारीख को हमारे मुख्यमंत्री महोयद कैथल के अन्दर उदघाटन करने के लिये गए थे तो उन्होंने वहां पर कहा था कि कैथल को एक अप्रैल से अलग जिला घोशित कर दिया जायेगा लेकिन अभी तक उस जिले की घोशणा नहीं की गई हैं। इसी तरह से कैथल के अस्पताल की पोजीशन है। उस अस्पताल की बहुत बुरी दशा है। उसके बारे में हमारे सी.एम. साहब ने कहा था कि 50 बैड के अस्पताल को 100 बैड का कर दिया जायेगा। उस अस्पताल में 150–200 के करीब मरीज रहते हैं। को मरीज बरान्डे में पड़ा रहता है तो कोई कहीं पर पड़ा रहता है। उनके लिये बैडज का कोई प्रबन्ध नहीं है। सी.एम. साहब ने कहा था कि 100 बैडज का अस्पताल बना दिया जायेगा लेकिन आज तक उस

घोशणा के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अस्पताल के अन्दर लोगों की बहुत बुरी दुर्दशा है। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से हाऊस को बताना चाहता हूं कि कैथल का सारे का सारा इलाका बहुत दु:खी है।

श्री मांगे राम गुप्ता: जिस दिन यह एलान किया यगा था उस दिन यह एलान भी किया गया था कि ये मामे–भानजे श्री जगजीत सिंह पोहलू और श्री रघुनाथ गोयल इक्ट्ठे रहेंगे, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं।

श्री रघुनाथ गोयल: चेयरमैन साहब, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहात हूं कि कुरूक्षेत्र के अन्दर एक गीता स्कूल है। आप जानते हैं कि कुरूक्षेत्र की भूमि पवित्र भूमि है। (शोर) और उस पवित्र भूमि पर आपातकाल में उस स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। मास्टरों को जेल के अन्दर बन्द कर दिया गया और कम से कम 10 लाख रूपये का नुक्सान हुआ। आज तक इस सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए सरकार का एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज हरियाणा में भ्रश्टाचार का कितना बोलबाला है। हमारे यहां कैथल के अन्दर एक आर.के.एस. डी. डिग्री कालेज है। उस डिग्री कालेज में बड़ा गबन हुआ है। उस कालेज को चलाने के लिये किसान पैसा देते हैं और उस कालेज में किसनों और मजदूरों के तथा गरीब व्यक्तियों के बच्चे पढ़ने के लिये आते हैं। इस गबन के बारे में मैंने सी.एम. साहब

को दरखास्त दी थी। उन्होंने वह दरख्वास्त डी.सी. साहब को मार्क कर दी। डी.सी. साहब ने वह एस.डी.एम. साहब को मार्क करके भेज दी। इसके बाद एस.डी.एम. साहब ने उसका समर्थन करते हुए वह दरखास्त वापिस डी.सी. साहब को भेज दी और डी.सी. साहब ने भी उस दरखास्त का समर्थन करते हुए यहां चण्डीगढ़ में भेज दी है। चण्डीगढ़ से वह दरखास्त विजीलैन्स डिपार्टमैंट के पास चली गई है जब से यह दल बदलू सरकार आई है उस दरख्वास्त के बारे में कुछ पता नहीं है कि कहां पर गई है। उस कालेज के सब रजिस्टर वगैरह गायब हैं। कोई इन्क्वायरी नहीं हो रही है। इसलिये मेरी सरकार से गुजारिश है कि उसकी इन्कवायरी होनी चाहिए। इस कालेज में गरीब जनता का पैसा लगा हुआ है ओर इस तरह से यह जो गबन हुआ है यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये इसकी जल्द से जल्द इन्कवायरी होनी चाहिए। बातें तो छोटी छोटी और भी बहुत हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहात हूं, जैसा मेरे साथी मैम्बर पोहलू साहब ने बतलाया है कि वहां पर यानी कैथल की आबादी 80 हजार है। उसको अब तक डिस्ट्रिक्ट घोशित नहीं किया गया जबकि जींद की आबादी 30 हजार के करीब है। उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। मैं जीन्द का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। (शोर) मैं यह कहता हूं कि कैथल के अन्दर एक जेल है। उस जेल के अन्दर न कोई टेलीफोन की सुविधा है न और किसी प्रकार की सुविधा है। कैथल की 80 हजार की आबादी है इसलिये उन जेल में सभी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिएं। इसी प्रकार से चेयरमैन साहब, मैं कैथल में

जो सिटी थाना था उसके बारे में कहना चाहता हूं। उस थाने की बिडिंग खराब हो गई थी। उस थाने को वहां से हटा कर 3–4 मील की दूरी पर एक किराये की बिल्डिंग ले करके थाना बनाया गया है। वहां पर उस थाने में भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और वह सिटी के काफी दूर पड़ता है। इसलिये सिटी के अन्दर थाने की बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनाई जानी चाहिए। वहां पर ट्रेजरी की बिल्डिंग भी जल्द से जल्द बनाई जाये। चेयरमैन साहब वहां पर ऐसी बिल्डिंग बनाई जाये जिसके अन्दर तहसील, ट्रेजरी, कोर्ट तथा दूसरे अफिसिज सबके सब इक्ट्ठे हो जायें ताकि आम पब्लिक को अपने कार्यो को अपने कार्यो के लिये किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आये।

चेयरमैन साहब, वहां पर एक को–आप्रेटिव बैंक था। वह किसी एक प्राइवेट बिल्डिंग के अन्दर स्थित था। 8–10 साल पहले वह बैंक उस बिल्डिंग को खाली करके चला गया। लेकिन अभी तक उस प्राइवेट बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली नहीं किया गया है। इसलिये मैं सी.एम. साहब के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि सरकारी दफतर वाले भी पगड़ी मांग रहे है। वहां से सारा दफतर चला गया है लेकिन एक कमरे के अन्दर कुछ टाट और फर्नीचर पड़ा हुआ है और उस बिल्डिंग पर कब्जा किया हुआ है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि उस बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली करवाया जाये।

शूगर और तेल के बारे में मैं अर्ज करूं कि हमारी इलाके की जो हालत है वह सारी की सारी हमारे इलाके की जनता जानती है। वहां पर तेल और शूगर के लिये बहुत देर–देर तक लाईनों में खड़ा रहना पड़ता है। एक दिन एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुई लाईन में खड़ी थी कि वह यह सुनने पर कि तेल खत्म हो गया है, बेहोश हो कर गिर गई। चेयरमैन साहब, मैं क्या क्या कहूं। आज तो हालत यह है:–

''आग लगी बनखण्ड में, जलने लगे पात,

तुम क्यों जलने लगे रहे पक्षियों पंख तुम्हारे साथ।

इस पर पक्षियों ने उत्तर दिया –

''फल खाए इस वृक्ष के बन्ध इन्हीं पात,

हमारा भी धर्म है जलें इन्हीं के साथ''

चेयरमैन साहब, मैं क्या–क्या बात बताऊं।

चेयरमैन साहब, मैं क्या–क्या बात बताऊं। मैं कोई सियासी आदमी तो नहीं हूं। मैं तो एक सीधा–साधा आदमी हूं। मैं यहां पर पहली बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस प्रकार से यह दल बदल कर रहें हैं, इस प्रकार से यह सरकार चलने वाली नहीं है।

चेयरमैन साहब, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो बजट यहां पर हाउस में पेश किया गया है, इस बजट के अन्दर 31 करोड़ रूपये का घाटा दिखाया है। हमारे अन्य साथियों ने यह कहा है कि यह घाटा 50 करोड़ रूपये तक पहुंच जायेगा। लेकिन इसके विपरीत मेरा ख्याल है कि यह घाटरा 50 करोड़ तक ही सीमिति नहीं रहेगा बल्कि यह घारा 60 करोड़ रूपये तक पहुंच जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

चौ. बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): सभापति महोदय, जो बजट इस हाउस के अन्दर पेश किया गया है मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हरियाणा सरकार का जो बजट 1980–81 का हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री बलवन्त राय तायल जी ने सदन में रखा और इस बजट की जो रूप रेखा उन्होंने बनाई हैं वह इस बात को साबित करती है कि हरियाणा का जो आगामी बजट है वह कांग्रेस की और इन्दिरा जी की नीतियां को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। (व्यवधान एवं शोर)

चौ. संत कंवर: इन्होंने तो इलैक्शन की बात को ध्यान में रखा है? .....

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

चौ. बीरेन्द्र सिंह: आपको दो साल नहीं हटते देते, घबराओ नहीं।

चौ. संत कंवर: हम तो तैयार हैं। आप इलैक्शन तो करवाओं। (व्यवधान)

चौ. बीरेन्द्र सिंह: आप आज इस्तीफा दे दें, 6 महीने में इलैक्शन करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी चौ. संत कंवर इस बात के लिये बहुत चिन्तित हैं कि इनको दो साल का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। इनको हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं आज की असैम्बली भंग न हो जाये। इनको यह डर है कि कहीं आज अगर असैम्बली भंग हो गयी तो हो सकता है दोबारा इनको मौका न मिले। मैं हमेशा इनको रात को चूंकि हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं यह यकीन दिलाता रहता हूं कि आप चिंता न करो और सो जाओ। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे में हमारे लायक दोस्त बाबू मूल चन्द जैन जो हमारे एक बुजुर्ग साथी हैं, ने यह कहा था कि हर जगह पर जहां पर प्रजातांत्रिक ढांचा होता है, वहां पर इस बात को देखकर बजट बनाया जाता है कि उस देश के अन्दर या प्रदेश के अन्दर जो गरीब लोग है, जो साधनहीन लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं या जो समाज का दबा हुआ वर्ग है, उसकी ज्यादा से ज्यादा सहायता कैसे की जाये। इसी सिद्धान्त को लेकर जबसे देश आजाद हुआ और इस देश की बागडोर कांग्रेस ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में संभाली थी, बजट बनाये जाते रहे हैं। उन्होंने समाजवाद की बात कही। उस समाजवाद के अन्दर उन्होंने यही बात की थी कि किसी तरह से इस देश की

कुल सम्पति का सही तरीके से बंटवारा उन लोगों में हो सके, जो गरीब हें और उन लोगों तक इस देश में होने वाले कामों का फायदा पहुंच सके जो गरीबी की लाईन से नीचे रहते हैं। यही कारण था कि कल 28–30 साल के कांग्रेस के शासन के बाद इस देश की गरीब जनता ने यह महसूस किया कि हो सकता है कि कोई ऐसी पार्टी हो, कोई ऐसी लीडरशिप हो, जो इस देश को कांग्रेस के शासन से बेहतर शासन दे सके और इस देश के गरीब लोगों का भला कर सकें 1977 के इलैक्शन में कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया गया। उसके बाद का इतिहास जो दो अढ़ाई साल ाक है वह जनता के सामने है। मैं एक बात की मिसाल देकर साबित करना चाहता हूं कि इस देश के गरीब लोगों ने, इस देश के पिछड़े हुए वर्गो ने, इस देश के गरीब हरिजनों ने जनता सरकार से बड़ी आशायें बांधी थी कि यह हमें बेहतर शासन देगी हमारा भला करेगी, वह सब बेकार साबित हुई। आज से शायद डेढ़ दो साल पहले की बात है। सैन्टर में एक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको एक खास घटक से सम्बन्ध था, (व्यवधान) उनके आने से पहले कांग्रेस गवर्नमैंट ने यह पालिसी तय की हुई थी कि 25 कराउ़ से कम की जो कन्सर्न है, वह इस देश के अन्दर कुछ खास किस्म की रियायतें प्राप्त कर सकेगी। जैसे इन्पोर्ट के लिये और अपना सामान दूसरे देशों को भेजने के लिये उनको गवर्नमै।अ की ओर से काफी सहायता भी थी। उन साहब ने जो खास घटक से ताल्लुक रखते थे, जो समाज के एक खास वर्ग से ताल्लुक रखते थे यानी जो कैपिटलिस्ट पार्टी से ताल्लुक

रखते थे और खुद कैपिटलिस्ट थे, अपने दो तीन महीने के मंत्री बनने के अर्से के बाद ही एक पालिसी स्टेटमैंट दिया कि 25 करोड़ की जो डैड–लाईन है, उसे बढ़ाकर 75 करोड़ रूपया कर दिया जाये ताकि उन बड़े इंडस्ट्रियलिस्टस को, उन बड़े घरानों को वह सहायता मिल सके और जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्टस है, रोजगार धन्धा दिलाने वाली इंडस्ट्रीज है, या कारखाने हैं, वे उस सहायता से वंचित हो जाये। इस बात से ही आप अन्दाजा लगा सकते ळैं कि जनता सरकार कितनी गरीबों की हमदर्द थी? अध्यक्ष महोदय बाबू मूल चन्द जैन ने बड़े विस्तार से यह बताया कि इस बजट के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं है जो इस चीज को साबित करे कि यह बजट समाजवादी ढांचे की स्थापना करने के लिये बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में दो तरह की विचारधारायें हैं। कुछ अर्थशास्त्री यह कहते हैं कि घाटै को जो बजट होता है, वह अच्छा नहीं होता। कुछ अर्थशास्त्री यह कहते है कि जो देश तरक्की करता है, या तरक्की करना चाहता है, अगर वहां पर घाटे का बजट नहीं है तो वह ठीक नहीं है। उनका मत यह है कि जिस देश में या प्रदेश में जिस साल घाटा नहीं हुआ, आप यह समझ लें कि उस प्रान्त या उस देश मे उस साल कोई तरक्की नहीं हुई। उनका ख्याल यह है कि घाटा होना बहुत जरूरी है। जिस देश या प्रदेश के बजट के अन्दर घाटा दर्शाया जाता है, उसके अन्दर यह निहित है कि उस साल उस प्रान्त में तरक्की हो। (व्यवधान व शोर) मेरा कहने का मतलब यही है कि जो प्लैन्ड एक्सपैन्डीचर होना चाहिए वह ज्यादा होना चाहिए। जो डिफरैन्ट

स्कीम्ज हैं, उनके तहत पैसा खर्च किया जाता है। वह पैसा अगर ज्यादा खर्चा जाता है तो उस बजट के अन्दर घाटा आ जाजात है। वह पैसा अगर ज्यादा खर्चा जाता है तो उस बजट के अन्दर घाटा आ जाता है। अगर वह प्लैन्ड एक्सपैन्डीचर जो योजनाओं पर खर्च होना है, वह कम खर्च होता है तो उसका मतलब यह है कि जो डिवैल्पमैंट की स्पीड है, वह कम है। यानी जो पार्टी सत्ता में है, जिस स्पीड से वह डिवैल्पमैंट करना चाहती है, वह प्लैन्ड एक्सपैन्डीचार से साबित होती है। मैंने तायल साहब के बजट में से कुछ ऐसी मदे निकाली हैं जिनमें से इन्होंने 14 कराउ़ रूपया बचाया है। जो पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव मदों से काटकर बचाया गया है, उसकी तो मैं उनकी तारीफ करता हूं लेकिन ऐसी भी कई स्कीम्ज होंगी जिनके तहत खर्च होना था लेकिन वह खर्च नहीं हुआ। मैं यह समझता हूं कि यह पिछली गवर्नमैंट की इनएफीशिएन्सी है। वह पैसा क्यों खर्च नहीं हुआ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे साथी विरोधी–पक्ष के तो बड़ी तैयारी के साथ आये थे कि जिस प्रकार हमने जैन साहब की बजट स्पीच को फाड़ा था, उसी प्रकार से तायल साहब और उसी तरह का बजट पेश करेंगे तो हम 40 के 40 सदस्य उसे भी फाड़ेगें। जब हम इनसे लाबी में बात कर रहे थे तो इन्होंने यह कहा कि अब हम क्या करें? मैंने यह कहा कि अब आप यह कहो कि टैक्स क्यों नहीं लगाया गया है? (व्यवधान व शोर) अध्यक्ष महोदय, इन साथियों के पास कोई ऐसी बात कहने के लिये नहीं थी जिसके आधार पर यह खड़े होकर यह कह सकते कि यह ऐन्टी किसान

बजट हे, प्रोकुलक बजट है या प्रो–कैपिटलिस्ट बजट है। इनको कोई ऐसी बात नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं लाबी की सारी बात बताना नहीं चाहता। मैंने इनको कहा था कि अगर आपको कोई चीज फाड़ने के लिये नहीं मिलती तो कम से कम अपना गला ही फाड़ो। स्पीकर साहब, 1980–81 को जो बजट हे वह जनता सरकार के दो सालों के बजट से बिल्कुल भिन्न है। अध्यक्ष महोदय, मेरे आदरणीय मित्र चौ. राम लाल वधवा बार बार यह दुहाई दे रहे थे कि हमारी जनता सरकार की ये उपलब्धियां है लेकिन अध्यक्ष महोदय, अपनी जिन उपलब्धियों के बारे में यह बहुत शोर मचा रहे हैं, उन उपलब्धियों में से एक उपलब्धि रूरल इंडस्ट्रियलिस्टस है जिसके बारे में ये सबसे ज्यादा शोर कर रह हैं। अपनी सरकार का सबसे बड़ अचीवमेंट मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं एक बात बार बार कह चुका हूं कि रूरल इंडस्ट्रियलिस्टस की स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है और इसको मैं मानता हूं लेकिन इस स्कीम को न पनपने देने का कारण अपोजीशन में बैठे हुए मेरे साथियों की रूकावटे थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह साबित कर सकता हूं कि रूरल इंडस्ट्रियलिस्टस की स्कीम में जिन दो हजार, तीन हजार या चार हजार लोगों को रोजगार मिला वह वर्ग उन लोगों से ताल्लुक रखता है जो अगर रूरल इंडस्ट्रियलिस्टस की नीति को न अपनाता तब भी गुजारा कर सकता था। ये वे लोग हैं जो गांव में अच्छा खाते पीते हैं, जिनके पास जमीन है और गुजारे के और दूसरे साधन हैं, उन्हीं ने इस स्कीम को पकड़ा है। दुर्भाग्य की बात है कि जिनके पास गुजारे

का साधन नहीं है उनको इस स्कीम का कोई फायदा नहीं हुआ। चौ. देवी लाल, जब वे मुख्यमंत्री थे और गांवामें में जाते थे और दस बीर या पचास पढ़े लिखे लड़के खड़े होकर कहते थे कि यह लड़का ग्रेजुएट है, यह लड़का एम.ए. पास है और यह लड़का दसवीं पास है लेकिन इनकी नौकरी नहीं मिलती है, फलां लड़के ने डिप्लोमा भी कर लिया है तब भी नौकरी नहीं मिलती। हम बेकार फिर रहे हैं तो वे बड़े गर्व से कहते थे कि नौकरी की बात न करो। हमने ग्रामीण उद्योग की स्कीम निकाली है, आप लोग उसका फार्म भरो और आपको कर्जा मिलेगा और आप इंडस्ट्रीज खोलो। मैं उस समय विरोधी पक्ष में बैठता था। मैं बार–बार कहता था कि इस स्कीम को सरकार जिस तरीके से चलाना चाहती है उससे उसाक ध्येय पूरा नहीं हो सकात और यही कारण हे कि पिछले दो अढ़ाई साल में इस रूरल इंडस्ट्रियलिस्टस की स्कीम से केवल दो तीन हजार आदमियों को फायदा हुआ और यह मैं पहले की बता चुका हूं कि वे कौन लाग है जिनको इस स्कीम से फायदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, गांव के किसी भी पढ़े लिखे आदमी को इस स्कीम से फायदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, गांव के किसी भी पढ़े लिखे आदमी को इस स्कीम से फायदा नहीं पहुंचा और न ही किसी गांव के पढ़े लिखे आदमी को सरकारी नौकरी ही मिली। अध्यक्ष महोदय, बजट के अन्दर जो आंकड़े दिए हुए हैं उनमें बताया गया है कि एक्पलाएमेंट एक्सचेंजिज में इतने लोगों ने नौकरी के लिये ना लिखाए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बढ़ौतरी का कारण यह है कि देहात के जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं

उनका शिक्षापर ज्यादा जोर है और वे नौकरी ही चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि रूरल इंडस्ट्रियलिस्टस की स्कीम के तहत देहात के लोगों को गुमराह कियागया और इससे किसी भी गांव के आदमी को फायदा नहं पहुंचा और न ही गांव के पऐ लिखे लड़कों को सरकारी नौकरी मिल पाई।

अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर 35–36 के करीब कार्पोरेशंज और बोड्र्ज हैं और बाबू मूल चन्द जी ने अपनी स्पीच में बताया था कि बिजली बोर्ड को छोड़कर हरियाणा सरकार ने इन कार्पोरेशंज को और बोडर्ज को सत्तर करोड़ रूपया लोन की शक्ल में या ग्रान्ट की शक्ल में दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह बात भी दुरूस्त है कि कुछ को छोड़कर सारी की सारी कार्पोरेशंज घाटे में चल रही हैं। ये कार्पोरेशंज घाटे में क्यों चल रही हैं यह अलग बात है लेनिक देखना यह है कि स्टेट की जो इंवेस्टमेंट है उसेस स्टेट को क्या लाभ हो रहा है। स्टेट को केवल नुक्सान हो रहा है यह देखने वाली बात है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात आप सोंचे कि कार्पोरेशंज में आपने जो पैसा लगाया है उस पैसे का आपको ब्याज या उसकी रिटर्न नहीं मिलती जबकि दूसरी ओर बिरला के बारे में कहा जाता है कि उसकी असैटस ग्यारह सौ करोड़ रूपये की है, (व्यवधान) उसकी इंवेस्टमेंट ग्यारह सौ करोड़ रूपये की ळे और इसके ऊपर उसको 92 करोड़ रूपये का फायदा है, अध्यक्ष महोदय, अगर हम

बाबू मूल चन्द जी के आकड़ें ले लें तो दो सौ कराड़ की इंवेस्टमेंट में सरकार को कोई रिटर्न न हो, यह एक बड़े दु:ख की बात है। अध्यक्ष महोदय, इन कोर्पोरेशंज के अन्दर एक बेलेन्स शीट बनती है और जिसको कुछ फायदा होता है उसको उस बेलेन्स सीट में इस तरह दिखाते हैं कि इतना पैसा ऐक्सपेंशनके लिये, इतना पैसा ऐन्टरनमेंट के लिये और इतना पैसा चेयरमैन के विदेश जाने के लिये रख रहे हैं (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा सुझाव है कि जो कार्पोरेशन कौमर्शियल टाईप का कोर्ठ भी धंधा करती है उसके ऊपर सैस लगा दिया जाए और यह तय कर दें कि उसका टोटल बिजनैस पर चाहे वह कम से कम हो, एक रूपये पर चाहे एक पैसा हो या आधा पैसा हो वह उनको सरकार को देना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इस तरह से सरकार को कम से कम साढ़े आठ कराड़े रूपये का फायदा हो सकता है। अगर इस किस्म का सैस सरकार उन पर लगा दे और इस बारे में कोई बिल या लैजिस्लेशन लाया जाए तो मैं समझता हूं कि स्टेट का काफी भला हो सकता है। इस वक्त तो हालत यह है कि जिन कार्पोरेशंज को लोन दिया हुआ है उनकी तरफ से रिक्वैस्ट आती रहती है कि इस लोन को पांच साल के लिये डैफर कर दिया जाए। हम पांच साल के बाद दे देंगे। अगर सैस लगा दिया जाएगा तो फिर यह बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। बजट में कहा गया है कि दो सौ बसें और चलाई

जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं श्री जगननाथ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और इनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट पर किसी किस्म का कोई कन्ट्रोल नहीं है (थंपिंग) आप चाहें मेजों को कितनी ही थपथ्पा लें मेरा कहना यह है कि ये ही नहीं अगर इनकी जगह कोई और भी मिनिस्टर आ जाएगा तब भी ट्रांसपोर्ट महकमें की समस्याओं को हम नहीं कर सकेगा। अध्यक्ष महोदय, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को चलाने वाले अधिकारी हैं उनकी कौंफिडेन्शियल रिपोर्ट मुख्यमंत्री लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लिखते हैं या एस.टी.सी. लिखते हैं फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की पूंछ कहां होगी। समाज का यह ढांचा है कि जब तक कोई डरता नहीं है उस वक्त तक कोई काम नहीं करता। मेरा कहना यह है कि खासतौर पर जहां तक ट्रासंपोर्ट महकमें का ताल्लुक है, मिनिस्टर फाइनल अथौरिटी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह एक विचारणीय बात है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सैन्ट्रल वर्कशाप जो बसों की बौडी बिल्डिंग के लिये है और जो बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां यह प्रोजेक्ट अभी छोटे स्केल पर गुड़गांवा में शुरू किया गया है। पिछले दो साल के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि एक महीने में बाईस तेईस बौडी बनकर तैयार हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा रोजवेज अढ़ाई सौ या तीन सौ बसें हर साल रिप्लेस करता है और कम से कम दो सौं बसें अपने फलीट में एड करता है इस तरह से पांच सौ या

साढ़े पांच सौ बसों की बौडी सारी की सारी एक ही वर्कशाप के अन्दर बनाई जाएं तो मेरा अन्दाजा है कि कम से कम हरियाणा के पांच हजार तकनीकी ज्ञान रखने वाले लड़कों को नौकरी मिल सकती है और पिछले दो साल का तो मुझे पता है कि 48 हजार रूपये में बौडी बनती थी आज वह बौडी साठ पैसठ हजार में बनती होगी। अगर यह सारी बौडीज अपने ही प्रान्त में बनने लगे ओर प्राइवेट कंसर्ज से न बनवाई जाएं तो करोड़ों रूपेय का फायदा हरियाणा सरकार को हो सकता है। इसलिये मेरी सजैशन है कि इस प्रौजेक्ट के बारे में एक बड़ी स्कीम तैयार की जाए ओर इस प्रौजैक्ट को बढ़ाया जाए और सभी बसों की बौडीज यहीं पर बनाई जाएं तो मैं समझता हूं कि स्टेट को अढ़ाई या तीन करोड़ रूपये का फायदा होने की आशा हैं अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार की यह नीति रही है और जितने भी समाजवादी देश हैं, उनमें ऐसी प्रथा है कि जितने भी बड़े बड़े कसंर्नज हैं उन सबकी नेशनेलाइजेशन की जाती है ताकि उसका सीधा फायदा गरीब आदमी को ही पहुंचे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन कंसर्नज के अन्दर लूट है ओर जहां से करोड़ों रूपये का फायदा होता है और उस पैसे को बड़े बड़े आदमी ही खा जाते हैं ओर इसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं, वे बेचारे हड़तालों पर बैठते हैं, बोनस के लिये चिल्लाते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस मुनाफे को बड़े लोगों को खाने का कोई हक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि सरकार, बड़ी बड़ी प्राईवेट कंसर्नज हैं, जैसा कि गुड़गांव में बसों की बौडी बनाने की

कंसर्नज हैं, जहां से सरकार को काफी फायदा हो सकता है, उनको नेशनेलाइज करें। सरकार को चाहिए कि वह इस काम को पूरी तरह से अपेन हाथ में लें।

श्री अध्यक्ष: चौ. बीरेन्द्र जी, समय हो गया है, अब आप वाइंड अप करिये।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: इसके बाद अध्यक्ष महोयद, मैं पे कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करना चाहता हूं। (विघ्न)

Mr. Speaker: The hon. Member will continue on the next day. The House stands adjourned till 9.00 a.m. on Thursday, the 13th March, 1980.

***13.30 बजे**

(The Sabha then*adjourned till 9.00 hours on Thursday, the 13th March, 1980.)